

For All Competitive Exams

•LIVE

RNA[®]

By Ankit Avasthi Sir

THE HINDU

THE TIMES OF INDIA

HT Hindustan Times

The Indian EXPRESS

09:00Am 02 AUGUST 2024

REAL NEWS & ANALYSIS



Every day
is a

Chance to

LEARN

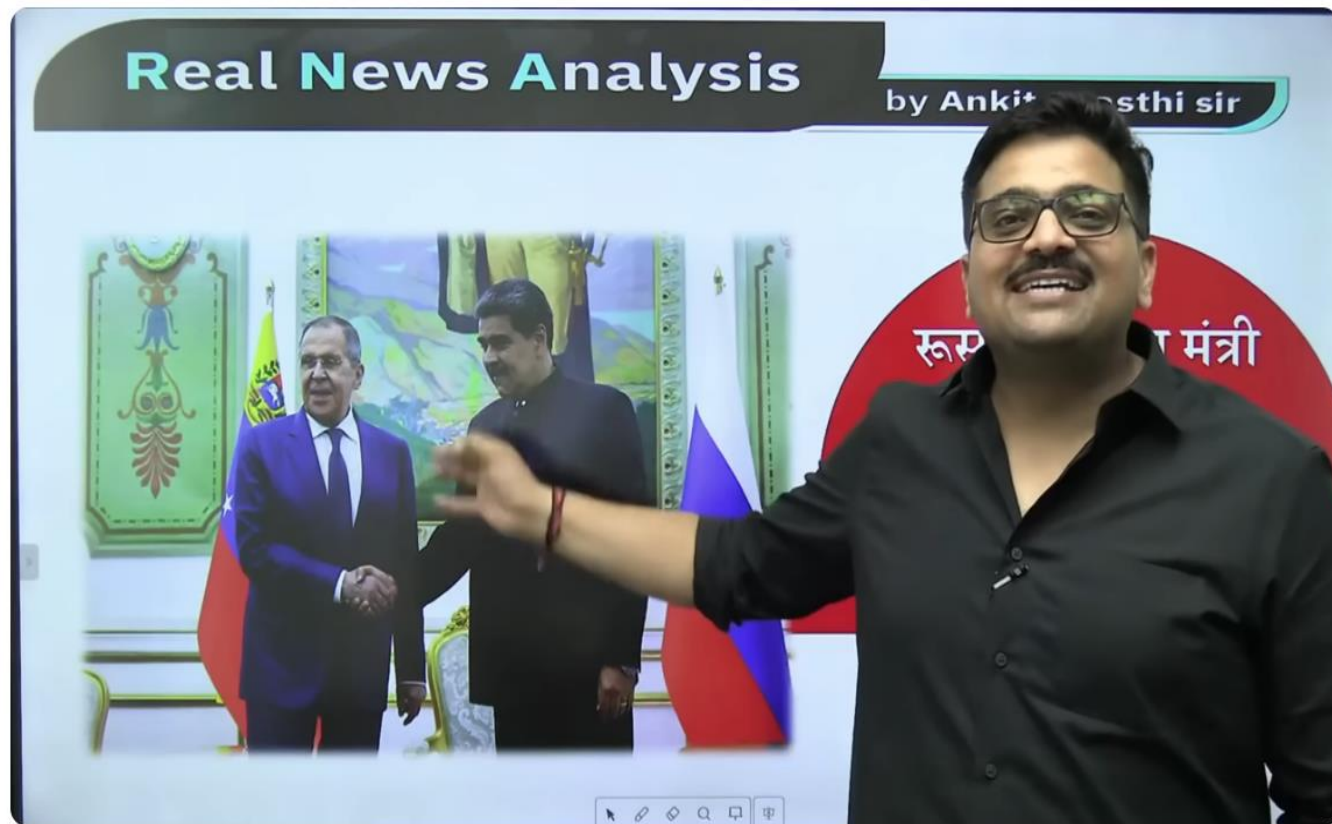




जानिए कैसे अमेरिका और रूस की भेंट चढ़ा वेनेजुएला?



22 Apr 2023



जानिए कैसे अमेरिका और रूस की भेंट चढ़ा वेनेजुएला? | RNA by Ankit Avasthi Sir

Apni Pathshala
2.02M subscribers

Subscribed

21K | Share | Download

Venezuela's Maduro declared winner in disputed vote

4 days ago

Share 

Vanessa Buschschlüter

Latin America and Caribbean editor, BBC News Online



U.S. says opposition beat Maduro in Venezuela elections



Astrid Galván, Marina E. Franco (Noticias Telemundo for Axios)



☰ Top stories :

News about Elon Musk • Nicolás Maduro >



TOI Times of India

'If he wins, I give him free ...': Elon Musk accepts Venezuela President Maduro's...

1 day ago

18 News18

'Whoever Messes With Me...': Venezuelan President Nicolas Maduro Dares Elo...



11 hours ago

N NDTV

Venezuela's Nicolas Maduro, Elon Musk Battle It Out Online ✓

1 day ago



in India Today

Elon Musk accepts Venezuelan President's fight challenge: Coming for you...

22 hours ago



m mint

Mint Quick Edit | Virtual Bravado 2.0: Elon Musk versus Nicolas Maduro |...

49 minutes ago



"If I Win, He Resigns. If He Wins...": Elon Musk Dares Venezuela President Nicolas Maduro

The animosity between Elon Musk and Nicolas Maduro has been brewing for some time amidst political turmoil in Caracas. Maduro, whose victory in the recent elections has been widely contested.

World News | Edited by Samiran Mishra | Updated: August 01, 2024 7:15 am IST

TRENDING



Explained: Women's Boxing Match At Paris Olympics Sparks Gender Row



Olympics 2024: Sindhu Suffers Heart-Breaking Loss, Out Of Paris Games



Intel Says It Will Sack 18,000 Staff, Cut \$20 Billion In Expenses







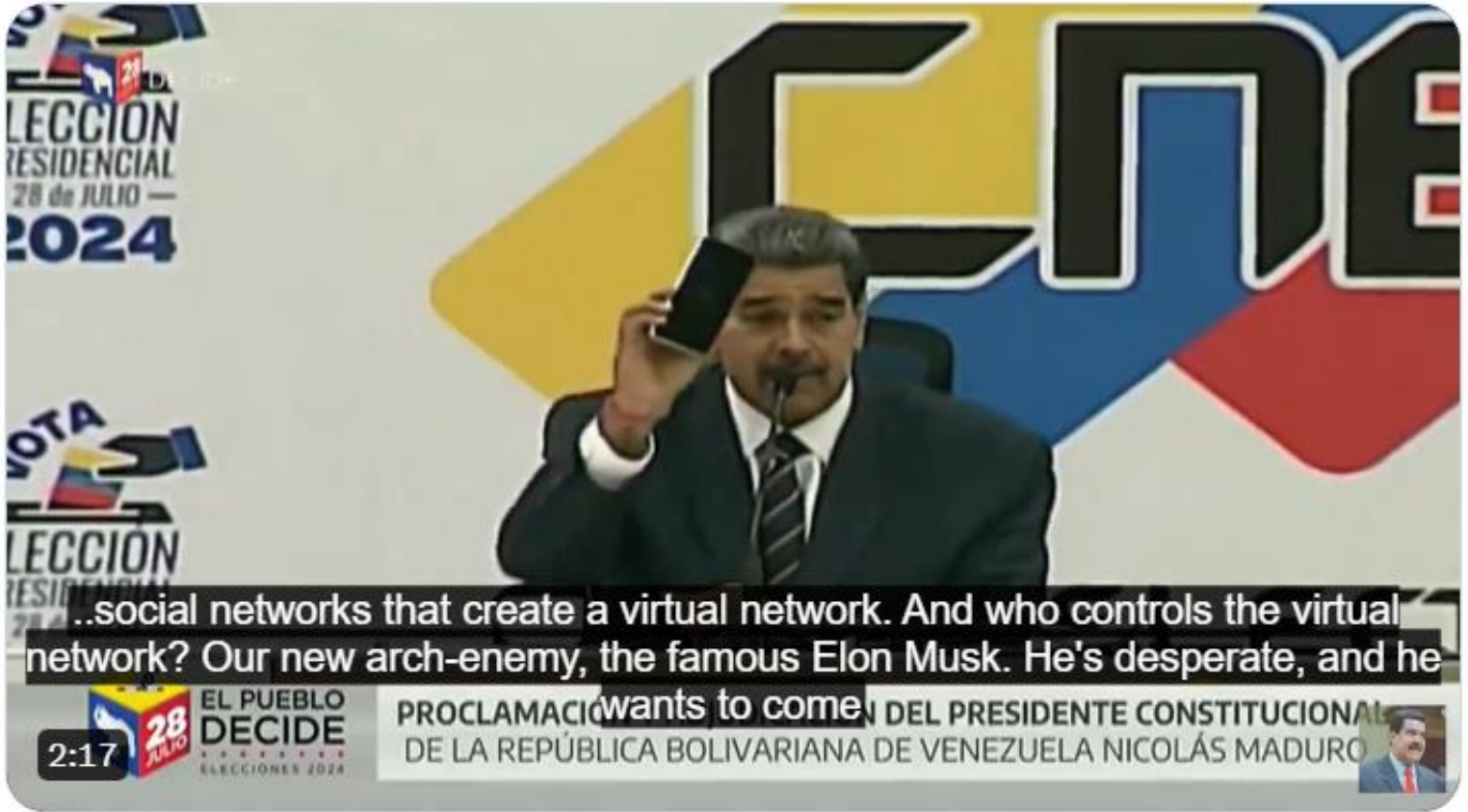
Ian Miles Cheong ✓

@stillgray

Subscribe



Illegitimate Venezuelan leader Nicolás Maduro, who very likely won reelection through fraud, is declaring war on Elon Musk, whom he calls his "arch-enemy." He claims Elon Musk wants to invade Venezuela with his space rockets.



2:03 AM · Jul 30, 2024 · 92.3M Views







LARGEST OIL
RESERVES
BY COUNTRY

01

Venezuela

300 billion barrel

02

Saudi Arabia

267 billion barrel

03

Iran

208.6 billion barrel

04

Canada

171 billion barrel

05

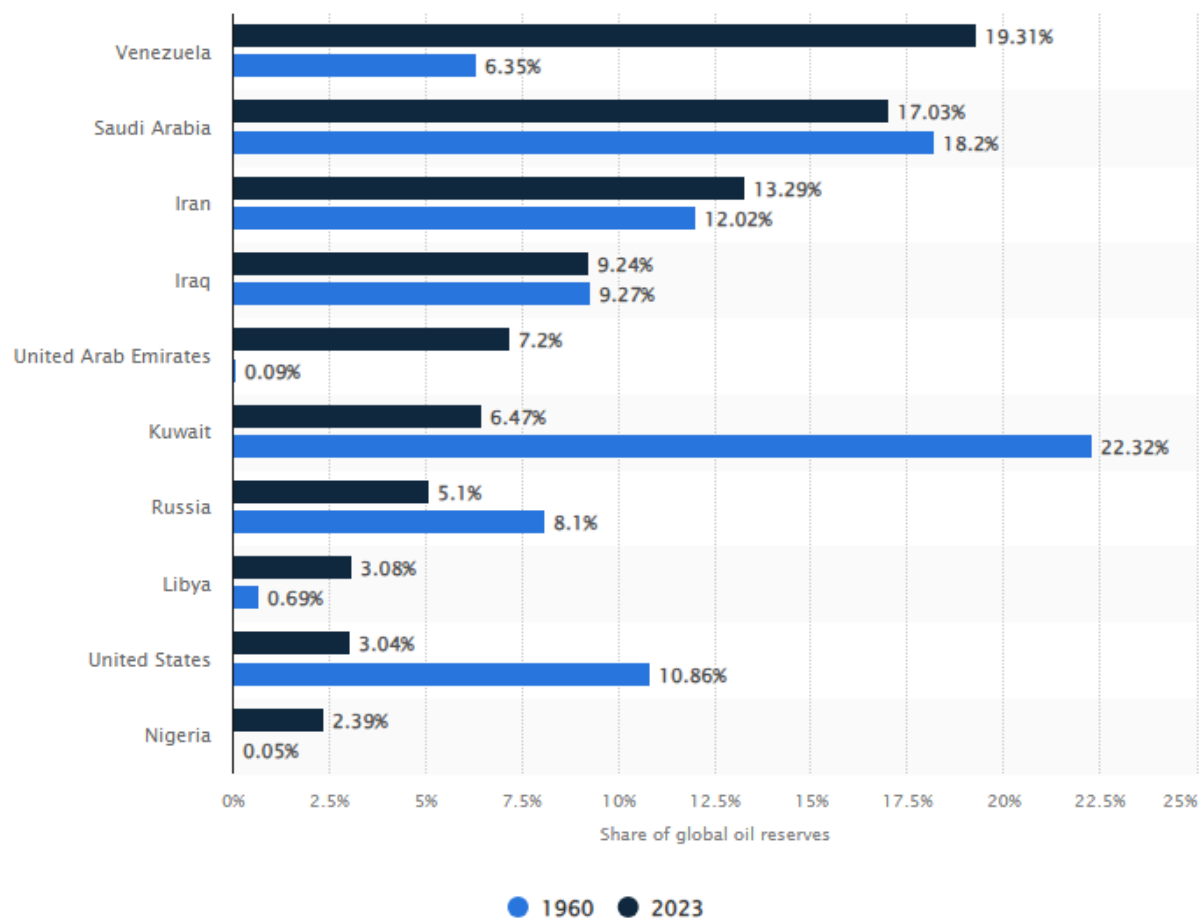
Iraq

145 billion barrel



Chemicals & Resources > Fossil Fuels

Distribution of proved oil reserves worldwide in 1960 and 2023, by country



- ★
- 🔔
- ⚙️
- 🔗
- “
- 🇪🇸
- 📄

DOWNLOAD

PDF + XLS + PNG +

Source

- [Show sources information](#)
- [Show publisher information](#)
- [Use Ask Statista Research Service](#)

Release date

2024

Region

Worldwide

Survey time period

1960 and 2023

Supplementary notes

Figures manually calculated using absolute values. Does not include Canada's oil reserves.

Open this statistic in...

- 🇪🇸 [Spanish](#)
- 🇩🇪 [German](#)

INFLATION



HYPERINFLATION

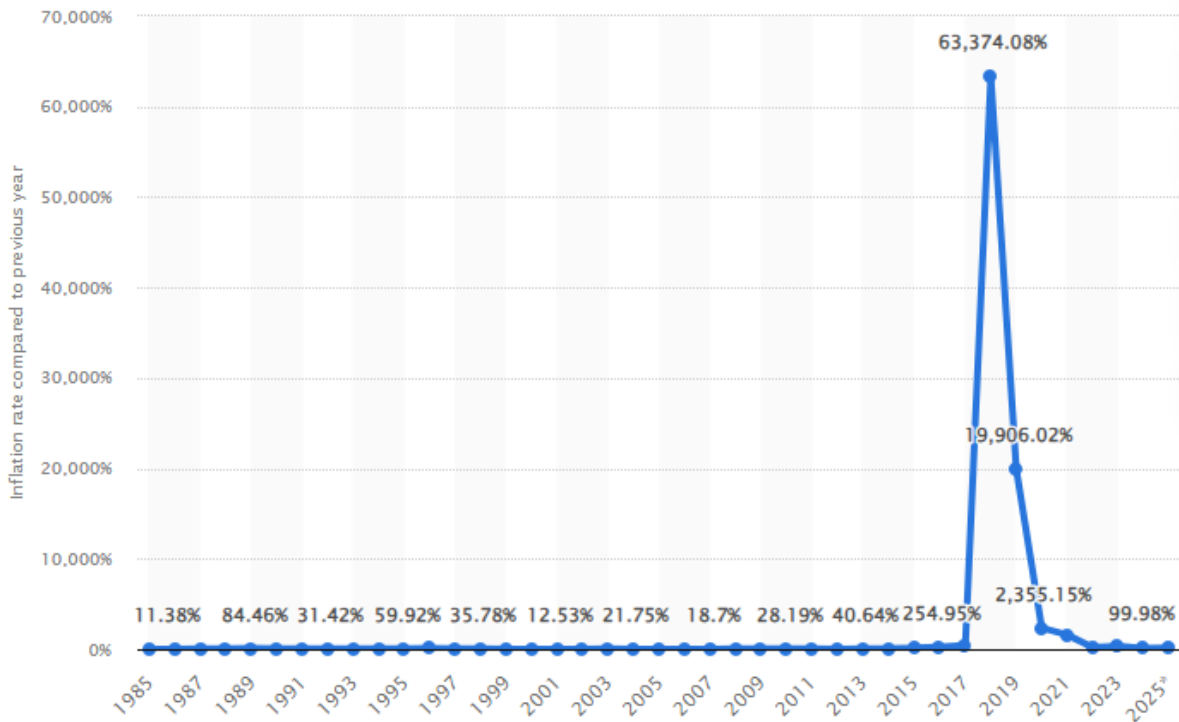


Economy & Politics > International

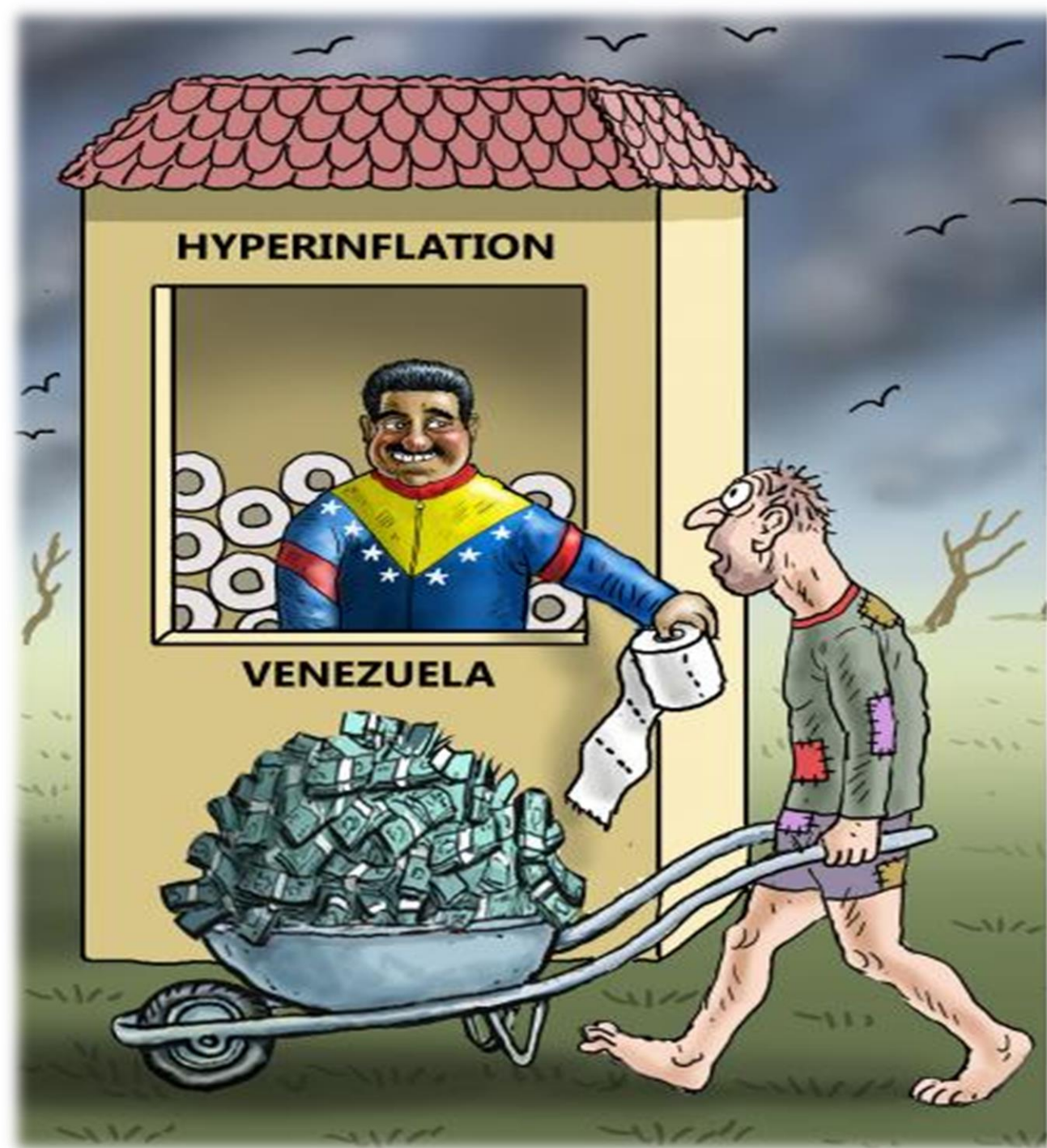
Venezuela: Inflation rate from 1985 to 2025

(compared to the previous year)

Zoomable Statistic: Select the range in the chart you want to zoom in on.









वेनेजुएला वह लैटिन अमेरिकी देश, जिसने तेल के बूते अगाध संपन्नता देखी, लेकिन आज यहां लोगों के भूखे मरने की नौबत है।

वेनेजुएला का संकट इसलिए अधिक पेचीदा है, क्योंकि यहां राजनीतिक घमासान, कमजोर अर्थव्यवस्था और सेना का सियासी इस्तेमाल सब एक-दूसरे में गुंथे हुए हैं। रही-सही कसर तब पूरी हो जाती है, जब दुनिया के कई बड़े देश अपना वर्चस्व साबित करने के लिए वेनेजुएला को नूराकुशती का अखाड़ा बना देते हैं। वेनेजुएला संकट क्या है और क्यों दुनिया के तमाम देश इस पर आमने-सामने आ रहे हैं।



वेनेजुएला एक समय लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था। वजह, इसके पास सऊदी अरब से भी ज़्यादा तेल है। सोने और हीरे की खदानें भी हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल पर टिकी है।

सरकार की 95% इनकम तेल से ही होती रही। 1998 में राष्ट्रपति बने ह्यूगो शावेज ने लंबे समय तक कुर्सी पर बने रहने के लिए देश के सिस्टम में तमाम बदलाव किए। सरकारी और राजनीतिक बदलावों के अलावा शावेज ने उद्योगों का सरकारीकरण किया, प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ हल्ला बोल दिया, जहां भी पैसा कम पड़ा तो खूब कर्ज लिया और धीरे-धीरे देश कर्ज में डूबता चला गया। तेल कंपनियों से पैसा लेकर ज़रूरतमंद तबके पर खुलकर खर्च करने से शावेज मसीहा तो बन गए, लेकिन वेनेजुएला की इकॉनमी में दीमक लग गया।



2013 में शावेज ने मादुरो को अपना उत्तराधिकारी चुना, जिन्हें विरासत में भारी-भरकम कर्ज मिला। पॉलिटिक्स तो चरमरा ही रही थी, साथ में तेल की कीमतें भी गिर रही थीं। तेल सस्ता होने पर इनकम घटी और गरीबी बढ़ी, तो मादुरो ने करंसी की कीमत गिरा दी। इस कदम से भला तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन महंगाई ज़रूर बढ़ने लगी। जनता की जेब तो पहले से हल्की हो रही थी, अब उसके पेट पर भी लात पड़ने लगी। यहां से देश का आर्थिक और राजनीतिक बंटोधार होने लगा।



वेनेजुएला की बड़ी दिक्कतें

करंसी की कीमत घटना, बिजली कटौती और मूलभूत ज़रूरतों वाली चीज़ें महंगी होना। वेनेजुएला में हाइड्रो-पावर का बहुत यूज़ होता है। **2015** में पड़े सूखे की वजह से यहां बिजली का उत्पादन गिर गया। बिजली का संकट इतना बढ़ गया था कि **अप्रैल 2016** में सरकार ने फैसला लिया कि अब से सरकारी दफ्तर सिर्फ सोमवार और मंगलवार को चलेंगे। नैशनल असेंबली के आंकड़े बताते हैं कि बीते एक साल में **मुद्रा-स्फीति (इन्फ्लेशन) दर 13,00,000% हो गई**।

दिसंबर 2017 तक ही वेनेजुएला पर 14 हज़ार करोड़ डॉलर यानी करीब **9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का विदेशी कर्ज** हो चुका था। **जुलाई 2018** में **सालाना महंगाई दर 83,000%** तक पहुंच गई। वेनेजुएला के पास सऊदी से ज़्यादा तेल है, लेकिन भारी तेल होने के चलते इसे रिफाइन करने में ज़्यादा खर्च आता है। वहां तेल कंपनियां सरकारी तो हो गई हैं, लेकिन तेल उत्पादन कम हो रहा है, जिससे रोजगार और आमदमी का सवाल खड़ा हो गया है।

जब तक वेनेजुएला में तेल बेच-बेचकर पैसा आ रहा था और शावेज जनता पर पैसा बरसा रहे थे, तब तक सब ठीक था। हालांकि, अर्थशास्त्री तब भी 'शावेज की सोशलिस्ट पॉलिसी' को खतरा बता रहे थे, लेकिन तब सबसे कानों में तेल पड़ा हुआ था। वेनेजुएला की करंसी बोलिवर का आलम यह है कि लोग एक किलो मीट के लिए 3 लाख बोलिवर तक दे रहे हैं। एक कप कॉफी के लिए 50 हजार बोलिवर तक दे रहे हैं। औरतें अपने बाल बेचकर पैसे इकट्ठा कर रही हैं। हर 35 दिनों में चीजों के दाम दोगुने हो रहे हैं। आज यहां 5 में से 4 लोग गरीब हैं। होटल-रेस्ट्रॉन्ट में लोग अपना बैंक बैलेंस दिखा रहा है कि उनके पास पेमेंट करने के लिए पैसे हैं। जिनके पास खाने का पैसा नहीं, वो लूट-मार कर रहे हैं।

2014 से अब तक कुल 70 लाख लोग देश छोड़ चुके हैं, 2014 से अब तक पेट्रोल कीमतें 6000% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तेल का उत्पादन 30 लाख बैरल से ढाई लाख बैरल पर पहुंच गया है। हर 21 मिनट में एक मर्डर होता है। 1 सितंबर 2018 से एक दिन का मेहनताना 34 गुना बढ़ा दिया है, जिसका भुगतान करने की क्षमता कंपनियों के पास नहीं है। राशन लेने के लिए लोग 65-65 घंटे कतार में खड़े होते हैं। गोदामों के बाहर सैनिक तैनात रहते हैं।

LATINO

Venezuela unveils new currency with 6 fewer zeros

The change for the bolivar, which has been made almost worthless by years of the world's worst inflation, is intended to ease both cash transactions and bookkeeping.



अक्टूबर, 2021 में उठाया था ये बड़ा कदम: वेनेजुएला ने बेलगाम महंगाई से निपटने के लिए एक अक्टूबर, 2021 को अपनी करेंसी से छह जीरो हटा दिया था. इस कदम के बाद देश में एक लाख बोलिवर को चेंज करके एक सॉवरेन बोलिवर कर दिया गया था. इतना ही नहीं 100 सॉवरेन बोलिवर को देश का सबसे बड़ा नोट बनाया गया.



2019 की शुरुआत में यहां राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें पहले से सत्ताधारी निकोलस मादुरो चुनाव जीत गए, लेकिन उन पर वोटों में गड़बड़ी करने का आरोप लगा। चुनाव में मादुरो के सामने खुआन गोइदो थे, जो इसी महीने संसद में विपक्ष के नेता बने हैं। इससे पहले तक उन्हें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई नहीं जानता था, लेकिन आज वह खुद को राष्ट्रपति बता रहे हैं।

चुनावी नतीजों के बाद मादुरो ने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया, वहीं गोइदो का कहना है कि उनके पास अगला चुनाव न होने तक अंतरिम राष्ट्रपति बनने का संवैधानिक अधिकार है। गोइदो वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने पढ़ाई के दिनों में वेनेजुएला के पिछले राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज के खिलाफ प्रदर्शन किया था। शावेज ने खुद ही मादुरो को अपना उत्तराधिकारी चुना था, जो उनकी तरह करिश्माई नेता साबित नहीं हो सके। वेनेजुएला आज जिस संकट से जूझ रहा है, उसमें मादुरो की विफल आर्थिक नीतियों का बड़ा हाथ है।



Donald J. Trump

@realDonaldTrump · [Follow](#)



The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaidó, as the Interim President of Venezuela.



Vice President Mike Pence Archived @VP45

Today @POTUS announced the U.S. officially recognizes Juan Guaidó as the Interim President of Venezuela. To @JGuaido & the people of Venezuela: America stands with you & we will continue to stand with you until #Libertad is restored!

Statement from President Donald J. Trump Recognizing Venezuelan National Assembly President Juan Guaidó as the Interim President of Venezuela

Today, I am officially recognizing the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaidó, as the Interim President of Venezuela. In its role as the only legitimate branch of government duly elected by the Venezuelan people, the National Assembly invoked the country's constitution to declare Nicolás Maduro illegitimate, and the office of the presidency therefore vacant. The people of Venezuela have courageously spoken out against Maduro and his regime and demanded freedom and the rule of law.

I will continue to use the full weight of United States economic and diplomatic power to press for the restoration of Venezuelan democracy. We encourage other Western Hemisphere governments to recognize National Assembly President Guaidó as the Interim President of Venezuela, and we will work constructively with them to support his efforts to restore constitutional legitimacy. We continue to hold the illegitimate Maduro regime directly responsible for any threats it may pose to the safety of the Venezuelan people. As Interim President Guaidó stated yesterday: "Violence is the oppressor's weapon; we only have one clear action: to remain united and fight for a democratic and free Venezuela."

12:17 AM · Jan 24, 2019



🕒 This Article is From Mar 12, 2019

Venezuela Gives US Diplomats 72 Hours To Leave, Blames Trump For Blackout

The U.S. State Department had announced on Monday it will withdraw its staff from Venezuela this week, saying their presence had become "a constraint on US policy."

World | Reuters | Updated: March 12, 2019 11:19 pm IST

TRENDING



Explained: Women's Boxing Match At Paris Olympics Sparks Gender Row



Death Waited For Hamas Chief For 2 Months In A Posh Tehran Locality



Olympics 2024: Sindhu Suffers Heart-Breaking Loss, Out Of Paris Games





Trump administration imposes Venezuelan oil-related sanctions

The United States Treasury targeted three individuals, 14 entities and six vessels for their alleged ties to a network attempting to assist Venezuela's oil sector.

19 Jan 2021



Venezuela issues arrest warrant for US-based opposition leader Juan Guaidó

By Karol Suarez and Stefano Pozzebon, CNN

4 minute read · Updated 8:15 PM EDT, Fri October 6, 2023



Former Venezuelan opposition leader Juan Guaidó speaks during an event at the Center for Strategic and International Studies in Washington, DC, on May 5. Sarah Silbiger/Bloomberg/Getty Images

Bogotá (CNN) — Venezuelan authorities on Thursday issued an arrest warrant for opposition leader and former interim president Juan Guaidó, who dismissed the move as politically motivated.

During a press conference in the capital Caracas, Attorney General Tarek William Saab alleged that Guaidó had used the state-owned oil company PDVSA's resources to finance himself and pay his legal expenses.

Politics

US to Lift Sanctions Only if Venezuela Returns to Democracy

- Biden administration doesn't want sanctions 'in perpetuity'
- Colombia hosts summit in a bid to end Venezuela crisis



Venezuelan President Nicolas Maduro *Photographer: Matias Delacroix/Bloomberg*

By [Patricia Laya](#)

April 26, 2023 at 3:36 AM GMT+5:30

Updated on April 26, 2023 at 3:55 AM GMT+5:30



Gift this article

Save

Venezuela's government and US-backed faction of the opposition agree to work on electoral conditions

October 18, 2023



Venezuela: Presidential election date to be held on 28 July

6 March 2024

Share 



Americas

US resumes talks with Venezuela, pushes for fair July 28 election

By Vivian Sequera and Matt Spetalnick

July 4, 2024 2:12 AM GMT+5:30 · Updated a month ago

🔖 Aa 🔄



[1/2] Venezuela's National Assembly President Jorge Rodriguez addresses the media, in Caracas, Venezuela, June 4, 2024. REUTERS/Gaby Oraa/File Photo [Purchase Licensing Rights](#)



CARACAS/WASHINGTON, July 3 (Reuters) - Senior U.S. and Venezuelan officials restarted talks on Wednesday, with Washington saying it urged President Nicolas Maduro's government to ensure that elections scheduled for July 28 will be "competitive and inclusive."





#Venezuela's presidential election is today. The country currently ranks last in the WJP #RuleOfLawIndex sub-factor for "Lawful transition of power" with a score of 0.19 out of 1. It also has the lowest overall score in the Index, ranking 142 out of 142 countries and jurisdictions on the rule of law. #Democracy #RuleOfLaw #Venezuela #venezuelaelections2024

For more insights, visit: <https://bit.ly/4cZ8Kji>





BREAKING:

The streets of Caracas are packed to the brim with protesters out to support opposition leader María Corina Machado during her first major speech since the election.

[#VenezuelaLibre](#) 

Via [@AlertaMundoNews](#)





Elon Musk @elonmusk · Jul 30

The people of Venezuela want change!



Mario Nawfal @MarioNawfal · Jul 30

MARÍA CORINA MACHADO: WE HAVE 73% OF THE VOTES CAST

"We have all the minutes published, printed, and verified.

They will have to ratify the truth....

[Show more](#)



They published, printed and that we have, because they will have to ratify the truth. And the truth that we all saw yesterday in the streets of

9.4K

79K

396K

32M



VIOLENT PROTESTS BREAK OUT IN VENEZUELA

● LIVE







Maduro declared winner of disputed Venezuelan election

The opposition, which had warned of the potential for fraud, was expected to challenge the result.

9 min 1456

July 29, 2024



Presidential candidate Edmundo González, center, and opposition leader María Corina Machado, center right, greet supporters during a rally in Maracaibo, Venezuela, on Tuesday. (Matias Delacroix/AP)

दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हजारों की भीड़ राष्ट्रपति के महल की ओर बढ़ी। लोग विवादित चुनाव में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की जीत के दावे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 28 जुलाई को वेनेजुएला के चुनाव में निकोलस मादुरो को विजेता घोषित किया गया था। आधी रात के तुरंत बाद नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल ने कहा कि मादुरो ने मुख्य विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज को पछाड़ते हुए 51 फीसदी मत हासिल किए हैं।

अन्य लोगों ने भीड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिस पर कैप्शन लिखा 'तानाशाह को मार गिराओ'। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति के महल को बचाने के लिए बड़ी संख्या में सैन्य काफिले को जाते हुए देखा गया। बड़ी-बड़ी राइफलों के साथ सैनिक मौजूद थे। मादुरो की जीत के दावे के अगले दिन ही वेनेजुएला की राजधानी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था, जिस पर पुलिस बल ने आंसू गैस छोड़े थे। विपक्ष ने मादुरो की जीत की घोषणा को धोखाधड़ी बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि उसके उम्मीदवार एडमंडो गोजालेज को 73.2 फीसदी वोट मिले हैं।

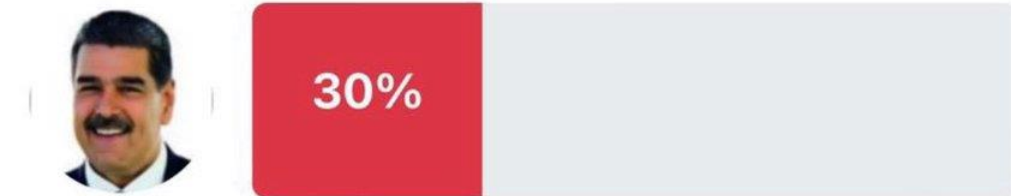
RESULTADOS - NACIONAL

Actas digitalizadas:
24.243 (80,35%).

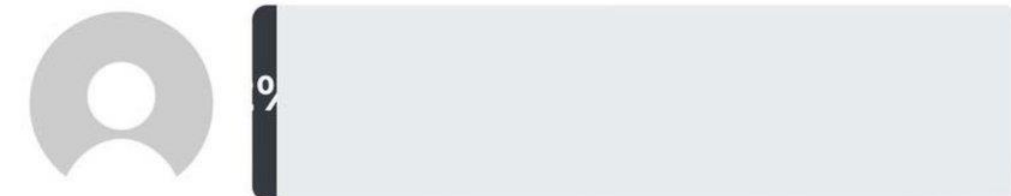
Edmundo González 7.086.955 votos



Nicolás Maduro 3.206.164 votos



Otros 248.865 votos



  VENEZUELA INVENTS NEW % FOR ELECTION RESULTS

Turns out you can have more than 100%...

According to local tv, 109% of the votes divided between the candidates.

$$51.2\% + 44.2\% + 4.6\% + 4.6\% + 4.6\% = 109.2\%$$

Source: [@visegrad24](#)



मादुरो से क्यों नाराज है जनता?

चुनाव से पहले ओपिनियन पोल ने एडमंडों की स्पष्ट जीत की संभावना जताई थी। देश के आर्थिक संकट को लेकर जनता में असंतोष है। 11 साल से मादुरो सत्ता में हैं, जिन्हें हटाने के लिए विपक्षी दल गोंजालेज के साथ एकजुट हो गए। कई पश्चिमी और लैटिन अमेरिकी देशों, साथ ही संयुक्त राष्ट्र सहित अंतरराष्ट्रीय निकायों ने वेनेजुएला के अधिकारियों से हर पोलिंग स्टेशन के मतदान रेकॉर्ड जारी करने का आह्वान किया है। इससे पहले कई लोग अपने घरों और सड़कों पर विरोध में बर्तन और तवे बजा रहे थे।

फुटेज में काराकास की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों को देखा जा सकता है। टायर जलाए जा रहे हैं। पुलिस लोगों को राष्ट्रपति भवन की ओर जाने से रोकने के लिए मोटरबाइकों पर आंसू गैस छोड़ रही है। मादुरो समर्थक अर्धसैनिक बल भी इकट्ठा हो रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल 41 वर्षीय पाओला सरजालेजो ने कहा कि वोटिंग में भयानक धोखाधड़ी हुई थी। हम 70 फीसदी से जीते हैं। लेकिन उन्होंने फिर से हमारे चुनाव को छीन लिया। वहीं उसके पिता मिगुएल (64) ने सहमति जताते हुए कहा कि हम अपने युवाओं और देश के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं। मादुरो चुनाव हार गए हैं, उन्हें राष्ट्रपति भवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है।



Elon Musk ✓ ✕

@elonmusk

Subscribe



The people of Venezuela have had enough of this clown 🤡



Mario Nawfal ✓



@MarioNawfal · Jul 30

🇺🇵 🇻🇪 POSTERS OF MADURO ARE BEING TORN DOWN IN VENEZUELA

x.com/MarioNawfal/st...



2:28 AM · Jul 30, 2024 · 131.6M Views



Elon Musk   @elonmusk · Jul 31

The people voted overwhelmingly for Gonzalez



Visegrád 24  @visegrad24 · Jul 31

BREAKING:

Machado's team posts their audited report of the true election result:

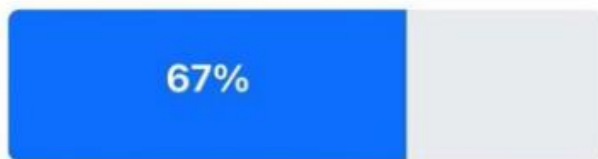
Gonzalez - 67%...

[Show more](#)

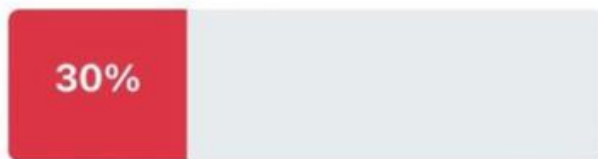
RESULTADOS - NACIONAL

Actas digitalizadas:
24.243 (80,35%).

Edmundo González 7.086.955 votos



Nicolás Maduro 3.206.164 votos



Otros 248.865 votos



मादुरो बोले- **वेनेजुएला में तख्तापलट की हो रही कोशिश**

सोमवार को टेलीविजन पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति मादुरो ने दावा किया कि वेनेजुएला में तख्तापलट की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद ऐसा होगा इसका उन्हें पहले से अंदाजा था, लेकिन वे उनके मंसूबों को कामयाब होने नहीं देंगे।

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला कई सालों से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों की वजह से तेल के लिए मशहूर ये देश दुनिया में अलग-थलग पड़ चुका है।





Ian Miles Cheong ✓

@stillgray

Subscribe



Illegitimate Venezuelan leader Nicolás Maduro, who very likely won reelection through fraud, is declaring war on Elon Musk, whom he calls his "arch-enemy." He claims Elon Musk wants to invade Venezuela with his space rockets.

..social networks that create a virtual network. And who controls the virtual network? Our new arch-enemy, the famous Elon Musk. He's desperate, and he wants to come

EL PUEBLO DECIDE 28 JULIO ELECCIONES 2024

PROCLAMACION DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA NICOLÁS MADURO

2:17

2:03 AM · Jul 30, 2024 · 92.3M Views



 **Elon Musk** ✓ ✕
@elonmusk

Subscribe



El burro sabe mas que Maduro

Translated from Spanish by Google

The donkey knows more than Maduro

Was this translation accurate? Give us feedback so we can improve:  

 **Ian Miles Cheong** ✓ @stillgray · Jul 30

Illegitimate Venezuelan leader Nicolás Maduro, who very likely won reelection through fraud, is declaring war on Elon Musk, whom he calls his "arch-enemy." He claims Elon Musk wants to invade Venezuela with his space rockets.



2:41 AM · Jul 30, 2024 · 91.2M Views

 **Elon Musk** ✓ ✕
@elonmusk



Subscribe



Perdón por comparar al pobre burro con Maduro. Es un insulto al mundo animal.

Translated from Spanish by Google

Sorry for comparing the poor donkey with Maduro. It is an insult to the animal world.

Was this translation accurate? Give us feedback so we can improve:  

3:29 AM · Jul 30, 2024 · 10.6M Views



Elon Musk   @elonmusk · Jul 30



This is real



NARCOTICS REWARDS PROGRAM OFFER



The Department of State Bureau of International
Narcotics and Law Enforcement Services (INL)
Offers

**Reward of up to \$15,000,000 United States
dollars
for Information Leading to Arrest/Conviction
Of
Nicolas Maduro Moros**



Contact the DEA with any tips by phone or e-mail:
Phone/Text/WhatsApp/Telegram/Signal: +1-202-681-8187
E-mail: CartelSolesTips@usdoj.gov

 35K

 229K

 1.1M

 98M





[Home](#) / [Nicolás Maduro Moros and 14 current and former Venezuelan officials charged with narco-terrorism, corruption, drug trafficking and other criminal charges](#)

Nicolás Maduro Moros and 14 current and former Venezuelan officials charged with narco-terrorism, corruption, drug trafficking and other criminal charges

March 26, 2020

[Share Article](#) ↗

[Download Press Release](#) ↓

For Immediate Release

Contact: Media Relations

Phone Number: (571) 776-2508

Maduro and other high-ranking Venezuelan officials allegedly partnered with the FARC to use cocaine as a weapon to “flood” the United States

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने टेस्ला CEO को नेशनल टेलीविजन पर आकर सामने से लड़ने की चुनौती दी थी, जिसे मस्क ने स्वीकार कर लिया है। मस्क ने कहा कि अगर मादुरो ये लड़ाई हार गए तो उन्हें रिजाइन करना होगा और अगर वे जीत गए तो मैं उन्हें मंगल ग्रह की फ्री सैर कराऊंगा। मस्क कई दिनों से सोशल मीडिया पर वेनेजुएला में चुनावी धांधली का आरोप लगाकर निकोलस मादुरो की आलोचना कर रहे हैं।

मादुरो बोले- **मस्क जहां बोलेंगे वहां लड़ने के लिए तैयार**

इससे पहले सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मादुरो ने कहा था कि **मस्क अपने हथियार और सेना लेकर वेनेजुएला पर हमला करना चाहते हैं। उन्होंने अपने पैसे और सैटेलाइट से अर्जेंटीना को कब्जे में ले लिया है और अब दुनिया पर कंट्रोल करना चाहते हैं।**

मादुरो ने कहा कि वह शावेज के बच्चे हैं। वह किसी से नहीं डरते हैं। मस्क जहां कहेंगे वहां जाने के लिए तैयार हैं। मादुरो ने ये भी कहा कि जिस किसी ने भी उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है वो बर्बाद हो गया है।



Elon Musk  

@elonmusk

Subscribe



I'm coming for you Maduro! 🚀💣

I will carry you to Gitmo on a donkey 🐴



Ian Miles Cheong  @stillgray · 23h

Maduro gives direct orders to his security forces, instructing them to **keep Elon Musk out at all costs**. The donkey dictator is delusional enough to think that Elon is going to personally show up and give him a thrashing.

He is afraid. How are these goons going to stop space

[Show more](#)



1:09

विपक्ष ने हार मानने से इनकार किया

निकोलस मादुरो को हटाने के लिए विपक्षी दल गोंजालेज के साथ एकजुट हुए थे। सोमवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी नेता मारिया मचादो ने दावा किया कि उनके गठबंधन को जनता का समर्थन हासिल है। सत्ताधारी पार्टी ने धांधली की है जिसकी वजह से एडमंडो गोंजालेज को जीत नहीं मिल पाई है।

मचादो वेनेजुएला में विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध की वजह से वह चुनाव नहीं लड़ पाईं। इसके बाद उन्होंने अपना समर्थन गोंजालेज को दिया। गोंजालेज ने परिणाम घोषित होने के बाद कहा कि वेनेजुएला में क्या हुआ है ये देश ही नहीं पूरी दुनिया जान रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने समर्थकों से हिंसा न करने और शांति से प्रदर्शन करने की अपील की।

UN ने चुनाव आयोग से मांग डाटा

अमेरिका ने मादुरो की जीत पर पर कहा उन्हें चुनाव रिजल्ट पर यकीन नहीं है। अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चिंता जताते हुए कहा कि यह रिजल्ट वेनेजुएला की जनता का मन नहीं बताता है।

संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय यूनियन समेत कई देशों ने वेनेजुएला में पारदर्शी तरीके से रिजल्ट जारी करने की मांग की है। उन्होंने चुनाव अधिकारियों से हर पोलिंग स्टेशन के मतदान रिकॉर्ड जारी करने की अपील की है।

निकोलस मादुरो को चीन, रूस और क्यूबा जैसे साथी देशों का साथ मिला है। उन्होंने राष्ट्रपति को लगातार तीसरी जीत पर बधाई दी है। हालांकि, पड़ोसी देशों ने ऐसा नहीं किया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डीसिल्वा ने अभी तक बधाई नहीं दी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने भी ऐसा ही किया है। इन दोनों देशों में वेनेजुएला की ही तरह वामपंथी विचारधारा वाली सरकार है।

VENEZUELAN POLITICAL CRISIS

Blinken says Venezuela's Nicolas Maduro lost election before claiming victory with 'no supporting evidence'

Many governments have denounced election results in favor of President Maduro



By **Louis Casiano** · Fox News

Published August 1, 2024 8:31pm EDT | Updated August 1, 2024 9:19pm EDT



Secretary of State Antony Blinken on Thursday said a Venezuelan opposition leader, not socialist and Hugo Chavez successor Nicolás Maduro, won the country's presidential election. Maduro has claimed victory and threatened the opposition since July 28, sparking widespread protests.

"Given the overwhelming evidence, it is clear to the United States and, most importantly, to the Venezuelan people that Edmundo González Urrutia won the most votes in Venezuela's July 28 presidential election," Blinken said.

Maduro is widely believed to have lost before declaring victory, and numerous regional governments have cast doubt on the results.





U.S. DEPARTMENT OF STATE

Office of the Spokesperson

For Immediate Release

STATEMENT BY SECRETARY ANTONY J. BLINKEN

August 1, 2024

Assessing the Results of Venezuela's Presidential Election

The United States applauds the Venezuelan people for their participation in the July 28 presidential election despite significant challenges. At least 12 million Venezuelans peacefully went to the polls and exercised one of the most powerful rights given to people in any democracy: the right to vote. Unfortunately, the processing of those votes and the announcement of results by the Maduro-controlled National Electoral Council (CNE) were deeply flawed, yielding an announced outcome that does not represent the will of the Venezuelan people.

The CNE's rapid declaration of Nicolás Maduro as the winner of the presidential election came with no supporting evidence. The CNE still has not published disaggregated data or any of the vote tally sheets, despite repeated calls from Venezuelans and the international community to do so. As the independent Carter Center's observation mission reported, the CNE's failure to provide the precinct-level official results, as well as irregularities throughout the process, have stripped the CNE's announced outcome of any credibility.

Meanwhile, the democratic opposition has published more than 80 percent of the tally sheets received directly from polling stations throughout Venezuela. Those tally sheets indicate that Edmundo González Urrutia received the most votes in this election by an insurmountable margin. Independent observers have corroborated these facts, and this outcome was also supported by election day exit polls and quick counts. In the days since the election, we have consulted widely with partners and allies around the world, and while countries have taken different approaches in responding, none have concluded that Nicolás Maduro received the most votes this election.

Given the overwhelming evidence, it is clear to the United States and, most importantly, to the Venezuelan people that Edmundo González Urrutia won the most votes in Venezuela's July 28 presidential election.

In addition, the United States rejects Maduro's unsubstantiated allegations against opposition leaders. Maduro and his representatives' threats to arrest opposition leaders, including Edmundo González and María Corina Machado, are an undemocratic attempt to repress political participation and retain power. The safety and security of the democratic opposition leaders and members must be protected. All Venezuelans arrested while peacefully exercising their right to participate in the electoral process or demand transparency in the tabulation and announcement of results should be released immediately. Law enforcement and security forces should not become an instrument of political violence used against citizens exercising their democratic rights.

We congratulate Edmundo González Urrutia on his successful campaign. Now is the time for the Venezuelan parties to begin discussions on a respectful, peaceful transition in accordance with Venezuelan electoral law and the wishes of the Venezuelan people. We fully support the process of re-establishing democratic norms in Venezuela and stand ready to consider ways to bolster it jointly with our international partners.



Mario Nawfal 
@MarioNawfal

Subscribe

BREAKING: US DECLARES GONZÁLEZ VICTOR IN VENEZUELA ELECTION, REJECTS MADURO'S CLAIM

Secretary of State Antony J. Blinken has issued a statement challenging Venezuela's official election results, declaring opposition candidate Edmundo González Urrutia as the true winner of the July 28 presidential election.

Blinken states that the National Electoral Council's declaration of Maduro's victory is "deeply flawed" and lacks credibility.

He cites opposition-published tally sheets from over 80% of polling stations, indicating González won by an "insurmountable margin," corroborated by independent observers and exit polls.

The U.S. applauds the 12 million Venezuelans who voted despite challenges and rejects Maduro's allegations against opposition leaders.

Blinken calls for the release of those arrested for peaceful participation and urges a peaceful transition.

Source: U.S. Department of State



Elon Musk

@elonmusk

Subscribe

Good



Mario Nawfal @MarioNawfal · 1h

BREAKING: US DECLARES GONZÁLEZ VICTOR IN VENEZUELA ELECTION, REJECTS MADURO'S CLAIM

Secretary of State Antony J. Blinken has issued a statement challenging Venezuela's official election results, declaring opposition candidate Edmund...

Show more



U.S. DEPARTMENT OF STATE
Office of the Spokesperson

For Immediate Release

STATEMENT BY SECRETARY ANTONY J. BLINKEN

August 1, 2024

Assessing the Results of Venezuela's Presidential Election

The United States applauds the Venezuelan people for their participation in the July 28 presidential election despite significant challenges. At least 12 million Venezuelans peacefully went to the polls and exercised one of the most powerful rights given to people in any democracy: the right to vote. Unfortunately, the processing of those votes and the announcement of results by the Maduro-controlled National Electoral Council (CNE) were deeply flawed, yielding an announced outcome that does not represent the will of the Venezuelan people.

The CNE's rapid declaration of Nicolás Maduro as the winner of the presidential election came with no supporting evidence. The CNE still has not published disaggregated data or any of the vote tally sheets, despite repeated calls from Venezuelans and the international community to do so. As the independent Carter Center's observation mission reported, the CNE's failure to provide the precinct-level official results, as well as irregularities throughout the process, have stripped the CNE's announced outcome of any credibility.

Meanwhile, the democratic opposition has published more than 30 percent of the tally sheets received directly from polling stations throughout Venezuela. Those tally sheets indicate that Edmundo González Urdula received the most votes in this election by an insurmountable margin. Independent observers have corroborated these facts, and this outcome was also supported by election day exit polls and quick counts. In the days since the election, we have consulted widely with partners and allies around the world, and while countries have taken different approaches in responding, none have concluded that Nicolás Maduro received the most votes in this election.

Given the overwhelming evidence, it is clear to the United States and, most importantly, to the Venezuelan people that Edmundo González Urdula won the most votes in Venezuela's July 28 presidential election.

In addition, the United States rejects Maduro's unsubstantiated allegations against opposition leaders. Maduro and his representatives threaten to arrest opposition leaders, including Edmundo González and María Corina Machado, in an undemocratic attempt to repress political participation and retain power. The safety and security of the democratic opposition leaders and members must be protected. All Venezuelans aroused while peacefully exercising their right to participate in the electoral process or demand transparency in the tabulation and announcement of results should be released immediately. Law enforcement and security forces should not become an instrument of political violence used against citizens exercising their democratic rights.

We congratulate Edmundo González Urdula on his successful campaign. Now is the time for the Venezuelan parties to begin discussions on a respectful, peaceful transition in accordance with Venezuelan electoral law and the wishes of the Venezuelan people. We fully support the process of re-establishing democratic norms in Venezuela and stand ready to consider ways to bolster it jointly with our international partners.



• [Live: Massive prisoner swap](#) [Simone Biles](#) [Kamala Harris](#) [Israel-Hamas war](#) [Olympics 2024](#)

EVEN WHEN THE NEWS IS FREE, JOURNALISM IS NOT.
SUPPORT INDEPENDENT, FACT-BASED JOURNALISM.

WORLD NEWS

Venezuela's Maduro asks top court to audit the presidential election, but observers cry foul

August 1, 2024







NCERT

LIMITED OFFER
REGISTRATION START



FOUNDATION BATCH

2

OFFER
FEE

4999 Rs

शुरू होने जा रही है
WORLD MAPPING

(1-10 August)

FOR UPSC & VARIOUS STATE PSC EXAM

BY ANKIT AVASTHI SIR





NCERT

**OFFER
FEE**



FOUNDATION BATCH

4999 Rs

REOPEN

**LIMITED OFFER
REGISTRATION START**

1. SUBJECTS TO BE TAUGHT (NCERTS FROM CLASS 6TH-12TH)
2. SUBJECTS: GEOGRAPHY, POLITY, HISTORY, INDIAN ECONOMY,
3. LIVE LECTURES DELIVERED IN HINGLISH LANGUAGE BY ANKIT AVASTHI SIR.
4. SPECIAL EMPHASIS ON CONCEPTUAL CLARITY IN CLASSES.
5. ALIGNMENT WITH UPSC AND STATE PSC PATTERN:
6. UNIT WISE WEEKLY TESTS THROUGH UNIQUE WORK BOOK STYLE

BY ANKIT AVASTHI SIR

FOR UPSC & VARIOUS STATE PSC EXAM

2024

GA FOUNDATION

RECORDED BATCH

Apni
Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Subject

HISTORY ,POLITY

GEOGRAPHY

ECONOMICS

Price

1499 /-

**Validity
1 Year**

By Ankit Avasthi Sir





UPPSC RO ARO



सत्यमेव जयते

**Bihar Public Service
Commission**



LAUNCHING



BIHAR PSC
TEST SERIES

299/- ONE
YEAR



475 POST

By Ankit Avasthi Sir





BIHAR PSC
TEST SERIES

299/- ONE
YEAR

Why ?

- **Exam-centric Robust Quality Content**
- **Increase Selection Chances by 16X**
- **Performance Analysis with State & All India Rank**
- **Most Relevant Exam Questions**



By Ankit Avasthi Sir



BIHAR PSC
TEST SERIES

299/- ONE
YEAR

Features

- **50+ Mock Test**
- **10+ Topic wise test**
- **30+ PYQ's**
- **65 + Current Affairs**



By Ankit Avasthi Sir

₹ PRICE



BIHAR PSC
TEST SERIES

Buy Now!

299/-
One Year

By Ankit Avasthi Sir



HOW TO BUY

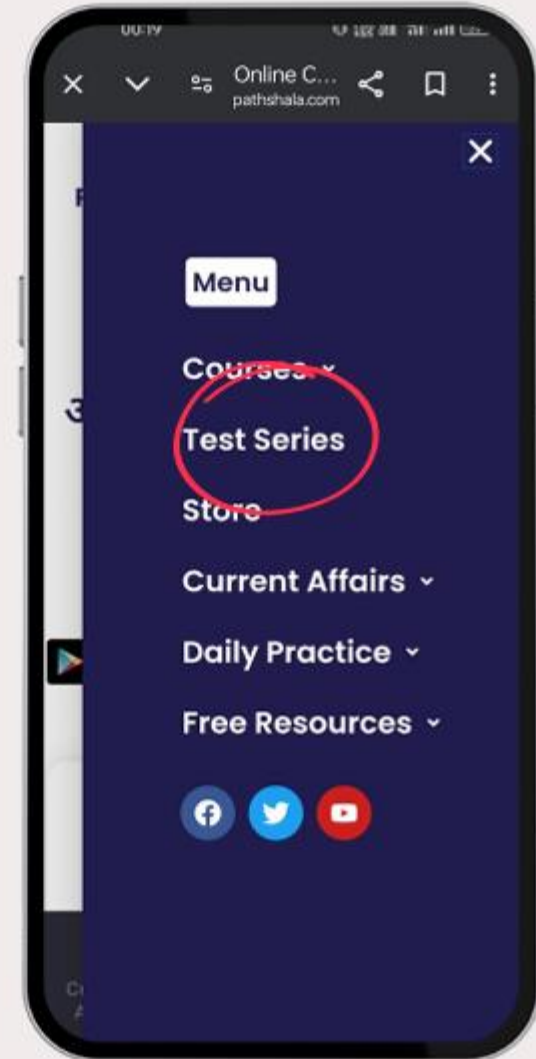
Step 1

Open the website
apnipathshala.com



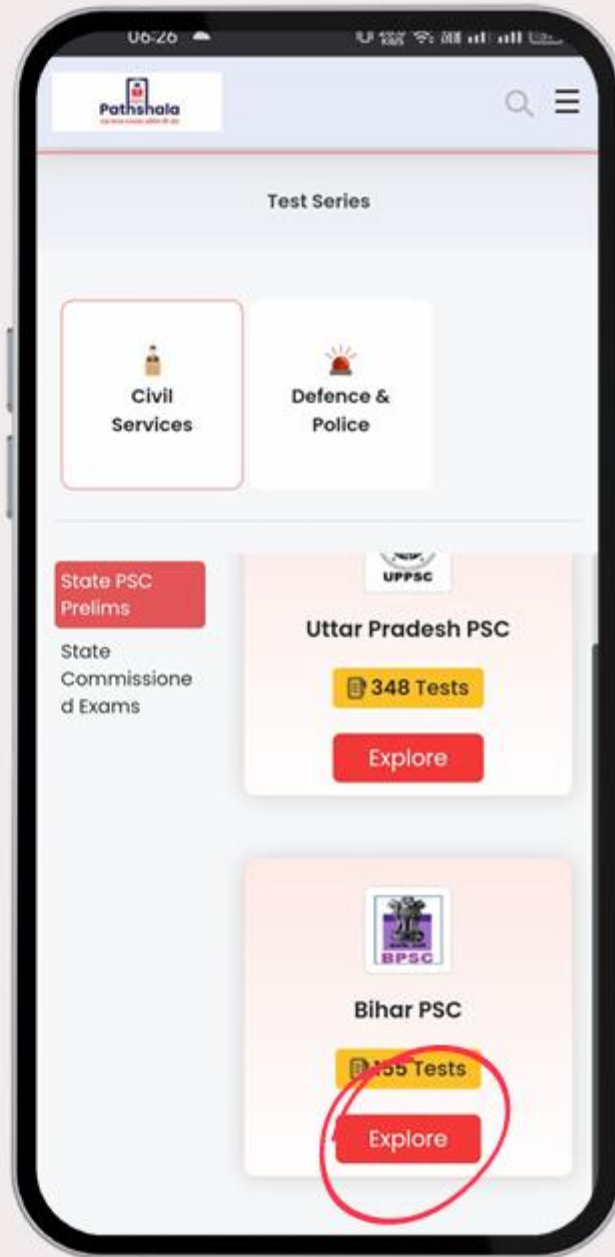
Step 2

Click on
Navigation Bar



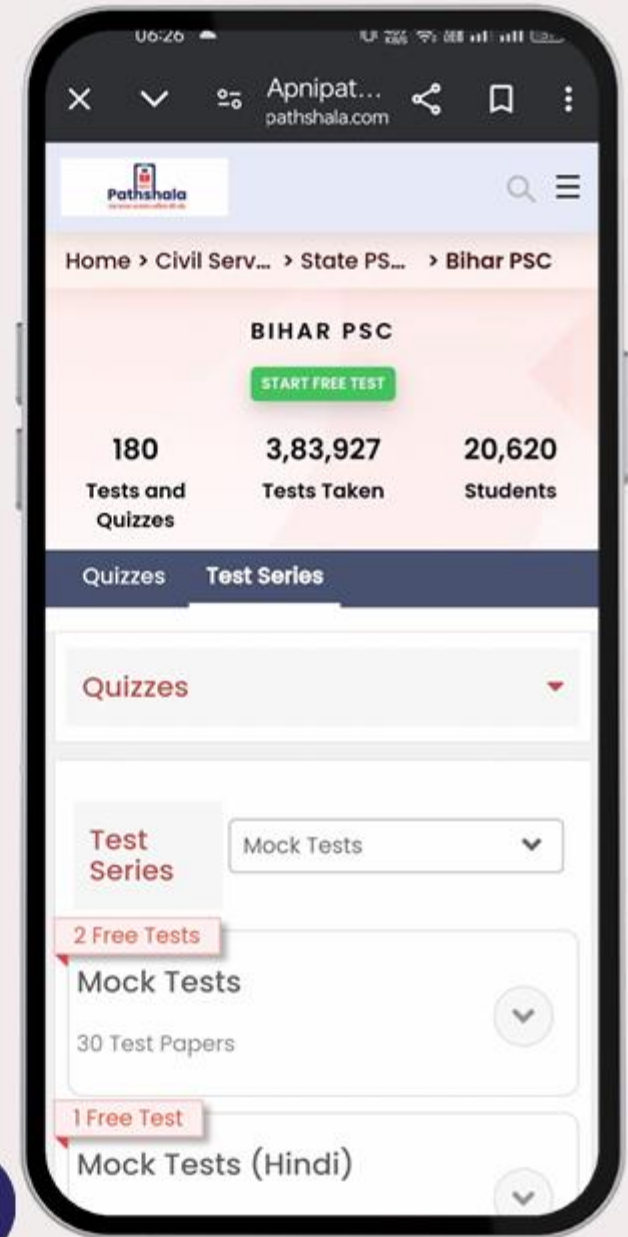
Step 3

Click on
Explore Now



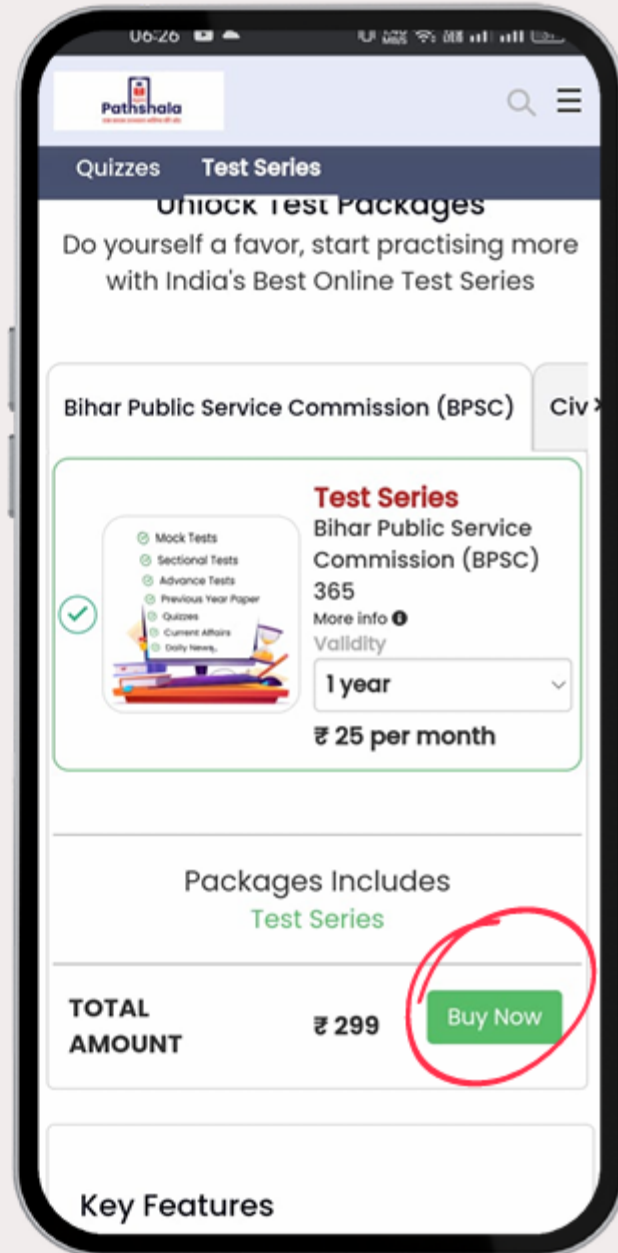
Step 4

Scroll
Down



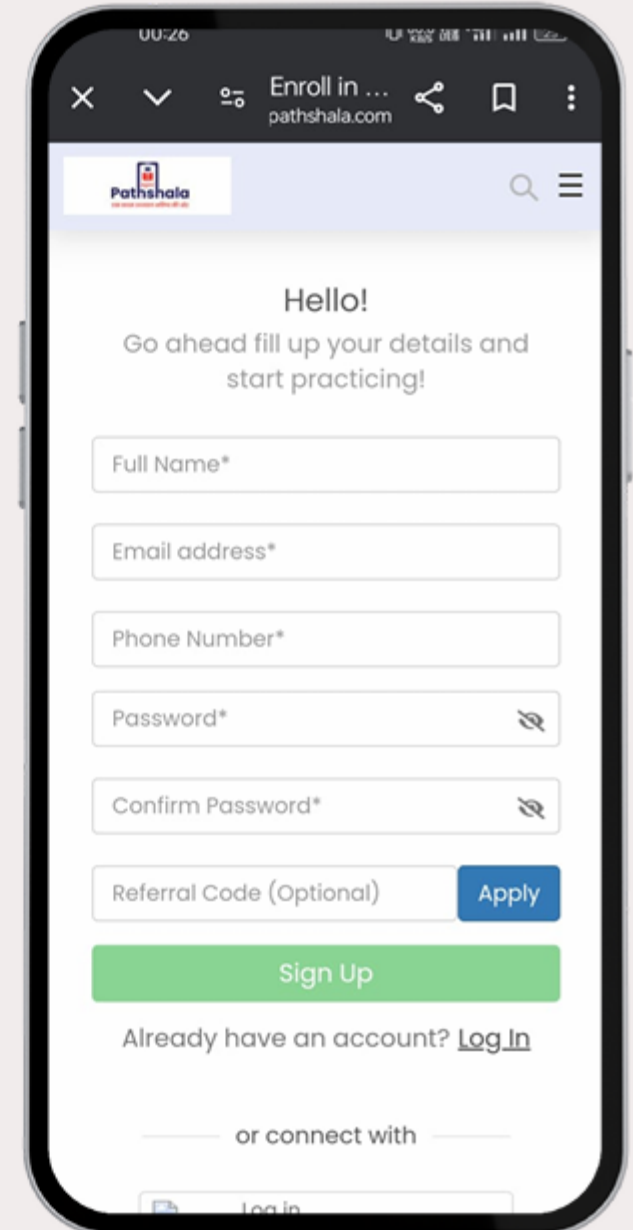
Step 5

Click on
Explore Now



Step 6

Fill the details
Pay Now!





LAUNCHING



BPSC

TEST SERIES

299/- ONE YEAR

- 50+ Mock Test
- 10+ Topic wise test
- 30+ PYQ's
- 65 + Current Affairs

Buy Now!

By Ankit Avasthi Sir





LAUNCHING



RO/ARO
TEST SERIES

299/- ONE
YEAR

- 30+ Mock Test
- 13+ Sectional test
- 8+ PYQ's
- 60 + Current Affairs

Buy Now!

By Ankit Avasthi Sir





UP POLICE बनने का सपना होगा साकार !



Test Series

UP POLICE EXAM

PRICE
99/- One Year

VACANCY: 60,244
EXAM. DATE : 23RD AUGUST
24TH AUGUST, 25TH AUGUST,
30TH AUGUST, 31ST AUGUST

By Ankit Avasthi Sir





UP POLICE बनने का सपना होगा साकार !

NEW

LAUNCHING



Test Series

UP POLICE EXAM



FEATURES

- ⇒ 20 Mock Test
- ⇒ 21 Sectional Test
- ⇒ 10 Practice Test
- ⇒ 25+ Topic Wise Test
- ⇒ 8+ PYQ's
- ⇒ 65+ Current Affairs Test

BUY NOW!

99/-

for ONE YEAR

By Ankit Avasthi Sir

CALL CENTRE

7878158882



HOW MAY I HELP YOU



AnkitInspiresIndia

➔ Download "Apni Pathshsla" app now!

Follow us:





RESERVATION







The Economic Times

<https://m.economictimes.com> > News > India

Supreme Court allows sub-classification in SC, ST for quota ✓

19 hours ago — On Thursday, the Supreme Court ruled that states can **sub-classify Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs)** to provide additional quotas ...



The Hindu

<https://www.thehindu.com> > News > India

State Governments can sub-classify SCs for quota, rules ... ✓

19 hours ago — Supreme Court allows State Governments to **sub-classify Scheduled Castes** for reservation, overruling previous verdict, subject to judicial ...



Bar and Bench

<https://www.barandbench.com> > News

Supreme Court holds sub-classification of Scheduled Castes ✓

19 hours ago — The Supreme Court on Thursday upheld the power of States to sub-classify reserved category groups, viz. the **Scheduled Castes** and Scheduled ...



News on AIR

<https://www.newsonair.gov.in> > supreme-court-permits-s...

Supreme Court permits sub-classification of SC and ST ... ✓

8 hours ago — Supreme Court permits **sub-classification** of SC and ST **reservations** to grant separate quotas for more backwards within the **categories** · Most Read.

राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति, यानी SC के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (1 अगस्त) को इस बारे में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा है। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह हैं, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकतीं।



इसके लिए दो शर्तें होंगी...

पहली: अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकतीं।

दूसरी: अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए।

फैसला **सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का है।** इसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद-341 के खिलाफ नहीं है।

RESERVATION



Constitution Article

Article 341 in Constitution of India

341. Scheduled Castes

- (1) The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the castes, races or tribes or parts of or group within castes, races or tribes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes in relation to that State or Union territory, as the case may be.
- (2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Castes specified in a notification issued under clause (1) any caste, race or tribe or part of or group within any caste, race or tribe, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.

Ankit Kumar Avasthi ✓

@kaankit

1:12 PM · Aug 1, 2024



सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।

सुप्रीमकोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों में उप-वर्गीकरण(sub-classification) के लिए मंजूरी दे दी है।

मतलब SC/ST वर्गों में पिछड़े समूहों की पहचान कर उन्हें अलग से कोटा दिया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की 7 बेंचों की पीठ ने यह फैसला 6:1 के बहुमत से सुनाया। केवल न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने पीठ के इस फैसले से असहमति जताई।

[Translate post](#)



Judge verdicts for permissibility of States sub-classifying Scheduled Castes

● State SC sub-classification is permissible

● Not permissible



CJI D.Y. Chandrachud



B.R. Gavai



Vikram Nath



B.M. Trivedi



Manoj Misra



Pankaj Mithal



S.C. Sharma



**In simple terms,
reservation in India is all
about reserving access to
seats in government
jobs, educational
institutions, and even
legislatures to certain
sections of the
population.**

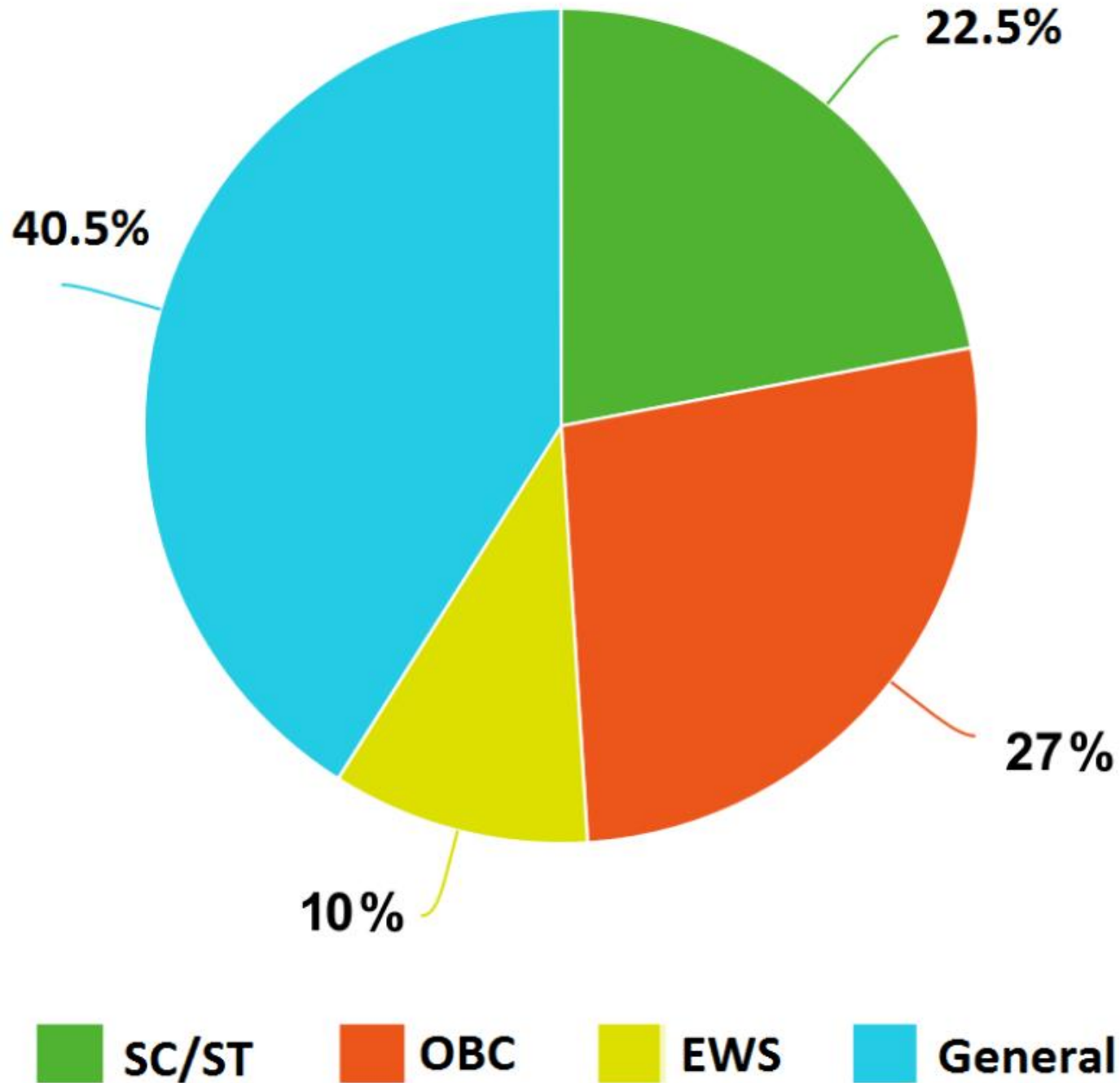




Reservation



Caste reservations in universities and jobs of the Central Govt.



आरक्षण की आवश्यकता क्यों?

- देश में पिछड़ी जातियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करना ।
- पिछड़े वर्ग के लिए समान अवसर प्रदान करना क्योंकि वे उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते जिनके पास सदियों से संसाधनों और साधनों तक पहुंच है।
- राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना ।
- पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए .
- योग्यता के आधार पर समानता सुनिश्चित करने के लिए यानी सभी लोगों को योग्यता के आधार पर आंकने से पहले उन्हें समान स्तर पर लाया जाना चाहिए।

CASE STUDY

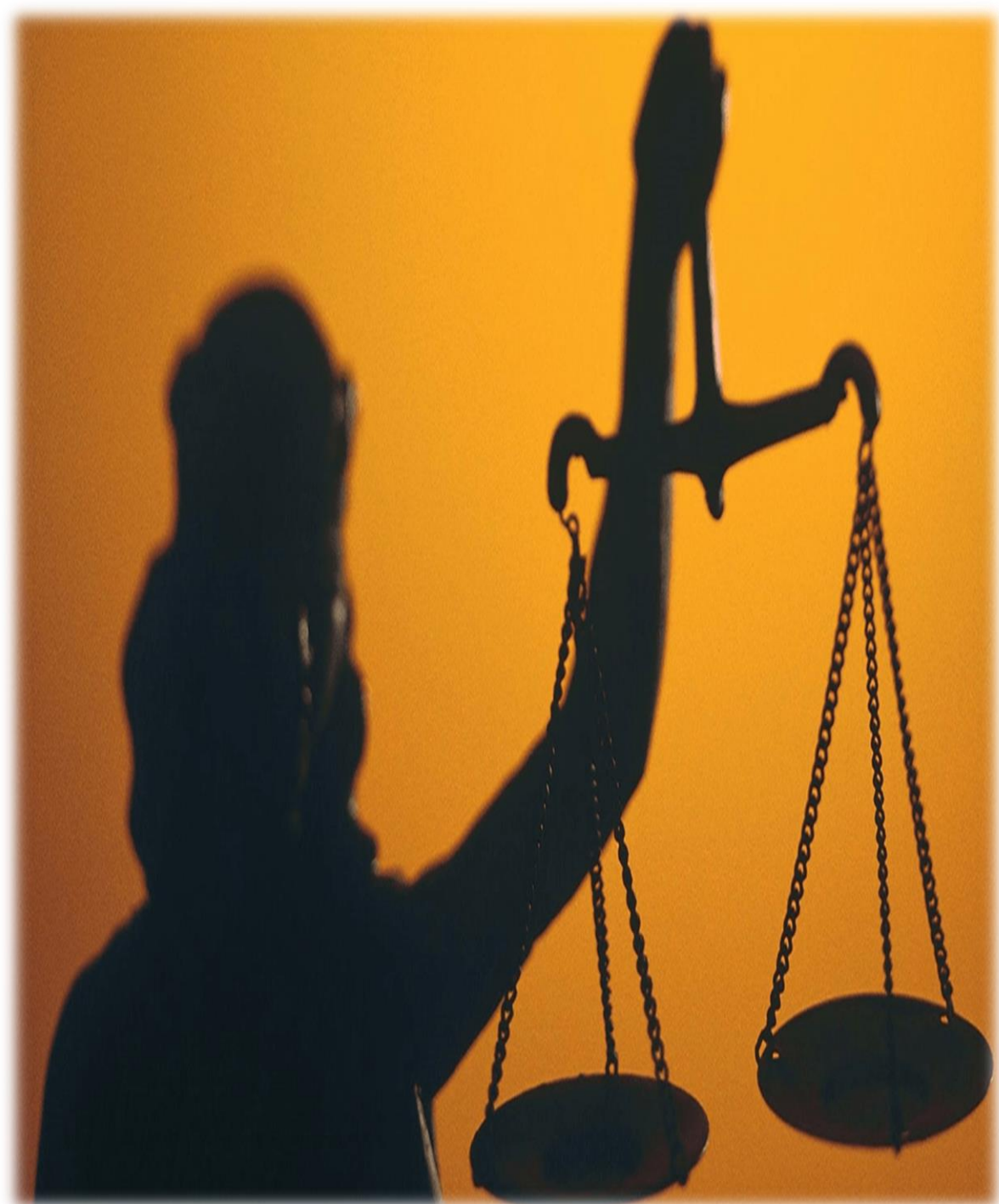


1975 में पंजाब सरकार ने आरक्षित सीटों को दो श्रेणियों में विभाजित करके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति पेश की थी. एक बाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए और दूसरी बाकी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए. 30 साल तक ये नियम लागू रहा. उसके बाद 2006 में ये मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा और ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले का हवाला दिया गया. पंजाब सरकार को झटका लगा और इस नीति को रद्द कर दिया गया. चिन्नैया फैसले में कहा गया था कि एससी श्रेणी के भीतर सब कैटेगिरी की अनुमति नहीं है. क्योंकि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है.

Supreme
Court
ORDER

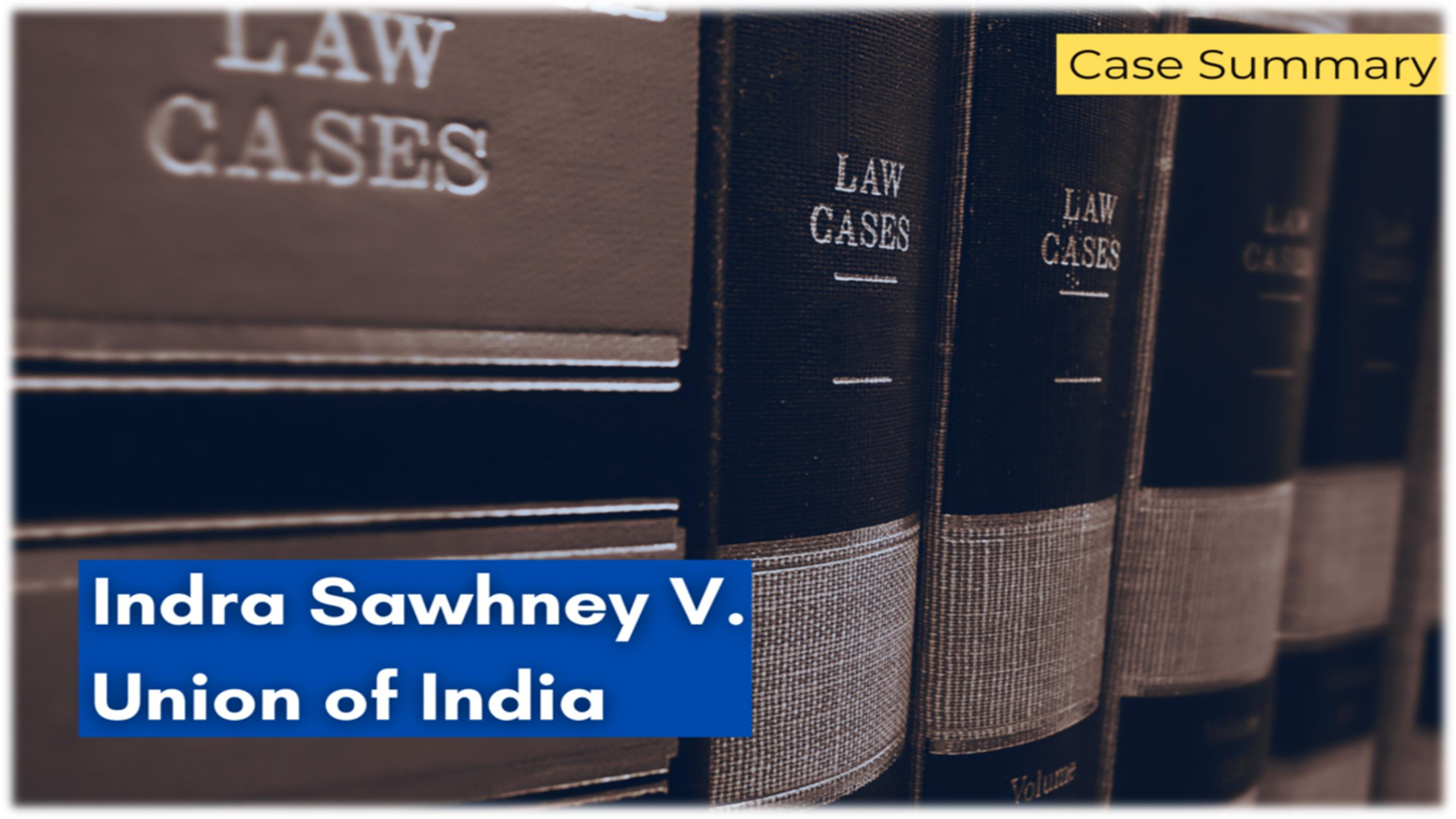


बाद में पंजाब सरकार ने 2006 में बाल्मीकि और मजहबी सिखों को फिर से कोटा दिए जाने को लेकर एक नया कानून बनाया, जिसे 2010 में फिर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. हाई कोर्ट ने इस नीति को भी रद्द कर दिया. ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले के तहत यह स्वीकार्य था, जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के भीतर सब कैटेगिरी की अनुमति दी थी. पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि अनुसूचित जाति के भीतर भी इसकी अनुमति दी जानी चाहिए.



Case Summary

**Indra Sawhney V.
Union of India**



Indra Sawhney & Others v. Union of India was a landmark public interest litigation (PIL) case in 1992 that challenged the government's decision to implement the Mandal Commission's recommendations for reservations for socially and economically backward classes (SEBCs). The case was heard by a nine-judge constitution bench of the Supreme Court of India, also known as the Mandal verdict. The judgment established several important legal principles, including:

- **Limits of state power**

- The state's powers are limited, and quotas cannot exceed 50%.

- **Social backwardness**

- The concept of "social backwardness" was emphasized, and 11 indicators were established to determine backwardness.

- **Qualitative exclusion**

- The concept of "creamy layer" was established, which applies to Other Backward Castes (OBCs) but not to Scheduled Castes (SCs) or Scheduled Tribes (STs). The creamy layer criterion was initially set at Rs 100,000 in 1993 and has been revised several times since.

- **Reservations for disadvantaged groups**

- Reservations for SEBCs are a legitimate means of achieving social justice. However, reservations beyond a certain limit can lead to merit being ignored and disrupt the administration.

2020 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने पाया कि ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले पर एक बड़ी बेंच द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि एससी श्रेणी के भीतर सब कैटेगिरी की अनुमति नहीं है. उसके बाद सीजेआई के नेतृत्व में सात जजों की बेंच का गठन किया गया, जिसने जनवरी 2024 में तीन दिनों तक मामले में दलीलें सुनीं और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.





Bar and Bench

@barandbench



Chief Justice of India DY Chandrachud-led 7-judge Constitution Bench to hear from January 17 case regarding validity of sub-classification among reserved categories.

[#SupremeCourt](#) [#SupremeCourtofIndia](#)

SUPREME COURT OF INDIA
NOTICE

Dated: 09.01.2024

The following Seven-Judge Bench matters are listed on Wednesday, the 17th January, 2024, before the Constitution Bench comprising Hon'ble The Chief Justice of India, Hon'ble Sanjiv Khanna, Hon'ble Vikram Nath, Hon'ble J.B.Pardiwala, Hon'ble Dipankar Datta, Hon'ble Manoj Misra and Hon'ble Satish Chandra Sharma, JJ.

S.No.	Case No.	Cause Title	Group Count
1.	C.A. NO. 2317/2011 ETC.	State of Punjab & Ors. Vs. Davinder Singh & Ors.	23

Learned Advocates/Parties-in-person are requested to get ready to present their cases before the Court.

News

Supreme Court allows sub-classification of Scheduled Castes for reservation

The majority in the 7-judge bench held that some castes within marginalised categorisations need more affirmative action, but some judges also made problematic remarks about 'creamy layer' and removing them from the SC categorisation.



अदालत का कहना है कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटा के भीतर कोटा तर्कसंगत अंतर पर आधार पर होगा. इसे लेकर राज्य मनमर्जी से काम नहीं कर सकते. इसके साथ ही राज्यों की गतिविधियां न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी. इसके साथ ही अदालत ने 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के फैसले को पलट दिया है. मौजूदा पीठ ने 2004 में दिये उस फैसले को दरकिनार कर दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसी/एसटी जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती है.

CREATE



SUB CATEGORY

कोर्ट ने कहा कि हालांकि, आरक्षण के बावजूद निचले तबके के लोगों को अपना पेशा छोड़ने में कठिनाई होती है. जस्टिस भूषण आर गवई ने सामाजिक लोकतंत्र की जरूरत पर दिए गए बीआर आंबेडकर के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं. लेकिन जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि एससी/एसटी के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है.





“

आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही मिलना चाहिए। अगर कोई पहली पीढ़ी आरक्षण लेकर हाईलेवल तक पहुंच गई है, तो दूसरी पीढ़ी को इसका हकदार नहीं होना चाहिए।

जस्टिस पंकज मिथल

असहमति जताने वाले जजों का बयान...

- जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इस फैसले में असहमति जताने वाली इकलौती जज रहीं। उन्होंने कहा कि यह देखा गया कि आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में स्टेटवाइज रिजर्वेशन के कानूनों को हाईकोर्ट्स ने असंवैधानिक बताया है। आर्टिकल 341 को लेकर यह कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना अंतिम मानी जाती है। केवल संसद ही कानून बनाकर सूची के भीतर किसी वर्ग को शामिल या बाहर करती है।
- अनुसूचित जाति कोई साधारण जाति नहीं है, यह केवल आर्टिकल 341 की अधिसूचना के जरिए अस्तित्व में आई है। अनुसूचित जाति वर्गों, जनजातियों का एक मिश्रण है और एक बार अधिसूचित होने के बाद एक समरूप समूह बन जाती है। राज्यों का सब-क्लासिफिकेशन आर्टिकल 341(2) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ करने जैसा होगा।
- इंदिरा साहनी ने पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों के नजरिए से नहीं देखा है। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल एक नया बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है जो संविधान में पहले से मौजूद नहीं थी। कभी-कभी सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों और संविधान में कई तरह से मतभेद होते हैं।
- इन नीतियों को समानता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मेरा मानना है कि ईवी चिन्नैया मामले में निर्धारित कानून सही है और इसकी पुष्टि होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के फैसले में क्या कहा था?

2004 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सब कैटेगिरी करने का अधिकार नहीं है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य मुद्दा एससी और एसटी कैटेगिरी के भीतर सब-कैटेगिरी (कोटे के भीतर कोटा) का है. अब कोर्ट यह बताएगा कि क्या अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणियों को सब-कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं? क्या राज्य विधानसभाओं के पास कोटा के भीतर कोटा लागू करने का अधिकार है या नहीं?



Constitution Article

Article 341 in Constitution of India

341. Scheduled Castes

- (1) The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the castes, races or tribes or parts of or group within castes, races or tribes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes in relation to that State or Union territory, as the case may be.
- (2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Castes specified in a notification issued under clause (1) any caste, race or tribe or part of or group within any caste, race or tribe, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.

Constitution Article

Article 142 in Constitution of India

142. Enforcement of decrees and orders of Supreme Court and orders as to discovery, etc

- (1) The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, in such manner as the President may by order prescribe.
- (2) Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Supreme Court shall, as respects the whole of the territory of India, have all and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person, the discovery or production of any documents, or the investigation or punishment of any contempt of itself.



Ankit Kumar Avasthi ✓

@kaankit



SC-ST के लिए सब-कैटेगरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी दी गई है।

Twitter(X) पर यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है, लोगों की राय बंटी हुई है। समर्थन और विरोध दोनों हो रहा है।

एक पोल करके देखते हैं, आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर!!

SC-ST समूह को,

[Translate post](#)

सब-कैटेगरी करना सही है

72%

सब-कैटेगरी करना गलत है ✓

28%

2,521 votes · 15 hours left

11:03 PM · Aug 1, 2024 · **7,060** Views



क्या अब SC कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर बनाकर उनमें शामिल कुछ जातियों को रिजर्वेशन से बाहर किया जा सकेगा?

जवाब: सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक, 1990 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद OBC के आरक्षण में क्रीमी लेयर फार्मूले को लागू किया गया था। उसी तर्ज पर SC कैटेगरी में भी सुप्रीम कोर्ट ने जातियों के वर्गीकरण के लिए राज्यों को अधिकार दिए हैं। जस्टिस गवई के अनुसार इस वर्गीकरण में किसी एक सब-कैटेगरी को 100 फीसदी आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

क्रीमी लेयर व्यक्तियों पर लागू होता है, जातियों पर नहीं। ऐसे में किसी एक व्यक्ति को क्रीमी लेयर बताकर उसे आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा सकता है। हालांकि, क्रीमी लेयर फार्मूले के अनुसार किसी जाति को एससी आरक्षण के दायरे से बाहर करना मुश्किल होगा।

लीगल एक्सपर्ट सचिन कुमार लोहिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 7 में से 4 जजों ने इस मामले में अपने फैसले में लिखा है कि राज्य OBC की तरह SC रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए फैसले ले सकती है। मतलब साफ है कि अब राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वो कोटा में कोटा जारी करने के लिए अनुसूचित जातियों को क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में बांटना चाहती है या नहीं।

जस्टिस पंकज मिथल ने अपने फैसले में जस्टिस बीआर गवई को कोट करते हुए कहा कि अगर कोई पिछड़ा IAS या IPS बन जाता है तो समाज में उसका स्टेटस बढ़ने के बावजूद उसके बच्चों को रिजर्वेशन के पूरे फायदे मिलेंगे। क्योंकि कुछ लोगों की तरक्की से पूरी कास्ट का पिछड़ापन दूर नहीं होता। पूरी जाति को आरक्षण से दूर नहीं किया जा सकता।

जस्टिस पंकज ने कहा कि जिस परिवार ने एक बार आरक्षण का फायदा उठा लिया है, उसे अगली पीढ़ी में आरक्षण का फायदा नहीं लेने देना चाहिए। ऐसे परिवारों के लिए आरक्षण सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। भविष्य में SC रिजर्वेशन का लाभ एक पीढ़ी को ही मिले इसको लेकर भी सरकार को नीति बनाना चाहिए। हालांकि, फैसले में शामिल इस हिस्से को लागू करना सरकारों के लिए आसान नहीं होगा।



यह आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए ही है या फिर एडमिशन और संसद में भी इसका असर होगा?

जवाब: विराग के मुताबिक सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर देश में आरक्षण दिए जाते हैं। जजों ने अपने फैसले में कहा है कि SC समुदाय में पिछड़े हुए वर्ग को प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण देने से संविधान की समानता के लक्ष्य को जल्द हासिल किया जा सकता है।

क्रीमी लेयर के फार्मूले से आर्थिक स्थिति सुधरने का पता चलता है। ऐसे में क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाले लोगों को नौकरियों के आरक्षण से वंचित किया जा सकता है। लेकिन, संसद और विधानसभा में SC/ST के आरक्षण में इस फैसले का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वहीं, लीगल एक्सपर्ट सचिन लोहिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ सरकारी नौकरियों को लेकर दिया गया है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन और संसद को लेकर इस फैसले में कुछ नहीं कहा गया है।



POLITICAL PARTIES IN INDIA



C
M
P



सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के राजनीतिक मायने और असर क्या है?

जवाब: पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दो तरह से राजनीतिक तौर पर असर देखने को मिल सकता है...

1. अनुसूचित जाति के एक वर्ग को अपनी ओर कर सकेंगी राजनीतिक पार्टियां

अनुसूचित जातियों में कुछ समूह इसके खिलाफ जबकि कुछ इसके समर्थन में होगा। अब सारा खेल हर प्रदेश की सरकार पर निर्भर करेगा। जिन लोगों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है वो SC समुदाय के लोग इस तरह के कोटे को लागू करने वाली सरकार के साथ हो जाएगी।

2. दलितों की राजनीति करने वाले दलों को नुकसान

इसे ऐसे समझें कि यूपी में दलितों को अब तक मायावती का वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन कोटे में कोटा लागू होने से ये मिथ टूट सकता है। अगर BJP कोटे में कोटा लागू करती है तो दलितों में जिस वर्ग को इससे फायदा होगा वो BJP के साथ हो सकता है। यह सिर्फ एक उदाहरण है। कुछ इसी तरह का नाजारा बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब हर जगह देखने को मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर किन राज्यों में सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है?

जवाब: पॉलिटिकल एक्सपर्ट किदवई के मुताबिक कोटे में कोटे के इस फैसले का देश के 17 प्रदेशों में देखने को मिलेगा, जहां SC की आबादी 15% या उससे ज्यादा है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब वो राज्य हैं, जहां 20% से ज्यादा अनुसूचित जातियों की आबादी है।

साफ है कि यहां जैसे ही अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले रिजर्वेशन के कोटे में कोटा दिया जाएगा तो राजनीतिक तौर पर इस पूरे समुदाय में उथल-पुथल मच जाएगा।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की कुल 17 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 8 बीजेपी के पास और 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है। यूपी के अलावा बंगाल में 10, तमिलनाडु में 7, बिहार में 6, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 5-5 लोकसभा सीटें हैं। इन राज्यों में देश की सबसे ज्यादा SC आबादी रहती है। साफ है कि कोटा सिस्टम में बदलाव करने पर अनुसूचित जाति दो खेमे में बंटेगा। इससे जिस वर्ग को फायदा मिलेगा वो इसे लागू करने वाले दलों की सरकार का समर्थन करेंगे।



सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अनुसूचित जाति के लोगों पर क्या असर पड़ेगा?

जवाब: JNU में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर सुरिंदर सिंह जोधका कहते हैं कि हर प्रदेश में अनुसूचित जातियों में 30-40 कम्युनिटी होती हैं, जिनमें से कुछ कम्युनिटी को ही ज्यादा फायदा मिलता है। क्लासिफिकेशन अच्छी बात है, क्योंकि इससे रिजर्वेशन का असल मकसद पूरा होगा, यानी हर किसी को फायदा मिलेगा।

इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पंजाब में अनुसूचित जातियों का क्लासिफिकेशन है।

मान लीजिए इस कैटेगरी में 39 जातियां हैं तो इसे दो हिस्सों A और B में बांट दिया जा सकता है। अगर नीचे से डिमांड आती है तो इन A और B कैटेगरी में भी सब-क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। यह कुछ ऐसा ही हो सकता है जैसे OBC को MBC या EBC, क्रीमी लेयर और नॉन-क्रीमी लेयर, लोवर OBC और अपर OBC में बांटा जाता है। मतलब साफ है कि इस तरह के फैसले से रिजर्वेशन का लाभ सही लोगों तक पहुंच सकेगा।





NCERT

**OFFER
FEE**



FOUNDATION BATCH

4999 Rs

REOPEN

**LIMITED OFFER
REGISTRATION START**

1. SUBJECTS TO BE TAUGHT (NCERTS FROM CLASS 6TH-12TH)
2. SUBJECTS: GEOGRAPHY, POLITY, HISTORY, INDIAN ECONOMY,
3. LIVE LECTURES DELIVERED IN HINGLISH LANGUAGE BY ANKIT AVASTHI SIR.
4. SPECIAL EMPHASIS ON CONCEPTUAL CLARITY IN CLASSES.
5. ALIGNMENT WITH UPSC AND STATE PSC PATTERN:
6. UNIT WISE WEEKLY TESTS THROUGH UNIQUE WORK BOOK STYLE

BY ANKIT AVASTHI SIR

FOR UPSC & VARIOUS STATE PSC EXAM

2024

GA FOUNDATION

RECORDED BATCH

Apni
Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Subject

HISTORY ,POLITY

GEOGRAPHY

ECONOMICS

Price

1499 /-

**Validity
1 Year**

By Ankit Avasthi Sir





LAUNCHING



BPSC

TEST SERIES

299/- ONE YEAR

- 50+ Mock Test
- 10+ Topic wise test
- 30+ PYQ's
- 65 + Current Affairs

Buy Now!

By Ankit Avasthi Sir





LAUNCHING



RO/ARO
TEST SERIES

299/- ONE
YEAR

- 30+ Mock Test
- 13+ Sectional test
- 8+ PYQ's
- 60 + Current Affairs

Buy Now!

By Ankit Avasthi Sir





UP POLICE बनने का सपना होगा साकार !

NEW

LAUNCHING



Test Series

UP POLICE EXAM



FEATURES

- ⇒ 20 Mock Test
- ⇒ 21 Sectional Test
- ⇒ 10 Practice Test
- ⇒ 25+ Topic Wise Test
- ⇒ 8+ PYQ's
- ⇒ 65+ Current Affairs Test

BUY NOW!

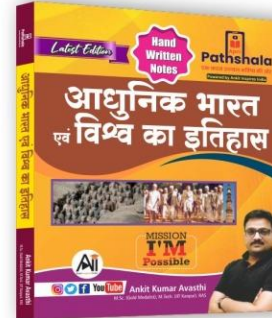
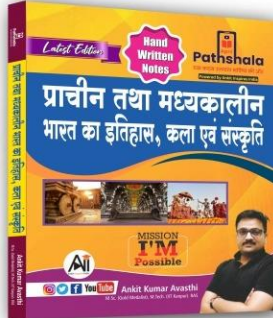
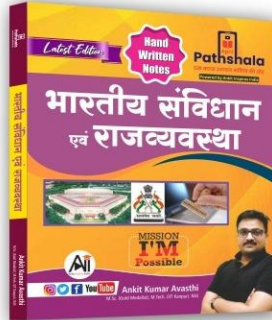
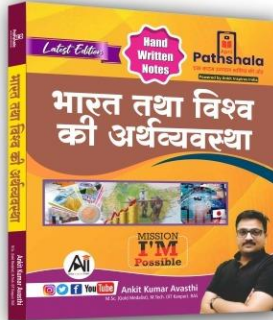
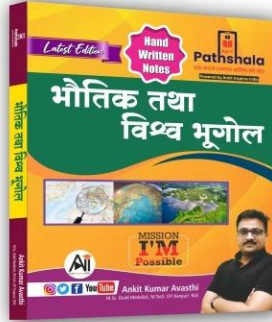
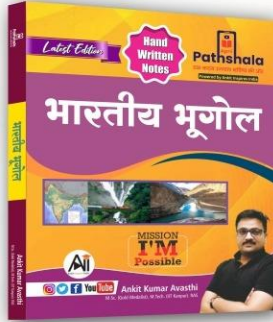
99/-

for ONE YEAR

By Ankit Avasthi Sir

GA FOUNDATION

Hand Written
Notes



₹ Only
1999

6 पुस्तकों
का
सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए
गए नंबर पर संपर्क करें....

 **7878158882**

- सिन्धु नदी का उद्गम किलाश पर्वतीय क्षेत्र में बीखर-सू हिमनद से होता है।
- तिब्बत में इस नदी को सिंगी खंबान कहते हैं।
- यह फमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है।
- यह नदी भारत में लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी के बीच बहती है।
- पाकिस्तान में यह अटक (Attock) नामक स्थानों पर मैदानों में प्रवेश करती है।
- पाकिस्तान में कराँची के पास डेल्टा बनते हुए यह अरब सागर में गिरती है।
- सिंधु नदी की दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदियाँ :- श्योक, नुब्रा, हुनजा, गिलागिट, स्वात, काबुल तथा गोमल
- इसकी प्रमुख बायें हाथ की सहायक नदियाँ झेलम, पिनाब, रावी, व्यास, सतलज, द्रास तथा जास्कर पंचनद
- सिंधु से पंचनद पाक में मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है।
- 'लेट' सिंधु नदी के किनारे स्थित है।

पंचनद

i) झेलम :- इस नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में

- बेरिनाग झील से होता है।
- * यह नदी बल्लर झील का निर्माण करती है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
- इस नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है।
- किशनगंगा इसकी दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदी है।
- इस नदी पर तुलबुल परियोजना प्रस्तावित है। यह एक नवविद्यन परियोजना है।
- यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है।

ii) पिनाब :- पिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बारालच्छा दर्रे के पास चन्द्र तथा भागा नदियों के मिलने (Confluence) से होता है।

- 1962 में इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ स्थित हैं।

उदाहरण :- तुलहस्ती, सलाब, बगलिहार

- यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।

iii) रावी :- रावी नदी का उद्गम शैलांग दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में होता है।

- हिमाचल प्रदेश में इन नदी पर चमेरा बाँध स्थित है।
- पंजाब में इस नदी पर धीन परियोजना स्थित है।

₹ 1999

CALL CENTRE

7878158882



HOW MAY I HELP YOU



AnkitInspiresIndia

➡ Download "Apni Pathshsla" app now!

Follow us:





zomato



BBK Baaten Bazar Ki... **05 Aug**

15 साल में पहली बार जोमैटो को मुनाफा...

zomato

जानिए क्या है कंपनी का Business Model?

BY ANKIT AVASTHI SIR

23:52

15 साल में पहली बार जोमैटो को मुनाफा... जानिए क्या है कंपनी का Business Model? by Ankit...

382K views • Streamed 11 months ago **21x**

bt Market TODAY

News: Zomato shares rise 4%, nears Rs 100 mark. Share price targets suggest further upside.

Zomato shares rise 4%, nears Rs 100 mark. Share price targets suggest further upside

Zomato shares climbed 4% to Rs 98.39 on BSE. This is after Zomato said its food delivery platform reported a net profit of Rs 2 crore for the first time this quarter.

At Rs 2 crore, Zomato turns profitable for first time this quarter

Last Updated: Aug 04, 2023, 11:30 AM IST

Synopsis
The Gurugram-based company reported a net profit of Rs 2 crore for the three-month period ended June 30 as against a net loss of Rs 166 crore in the same period last year. Zomato also reported a 70% year-on-year surge in operating revenue to Rs 2,416 crore.

brokerages rush to

several brokerages after the firm...
brokerages have maintained their ratings

Financial safety tips
Learn how to stay safe online with tips from the government of India [Learn more](#)

15 साल में पहली बार जोमैटो को मुनाफा... जानिए क्या है कंपनी का Business Model? by Ankit Avasthi Sir

फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो को फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली तिमाही में 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यह पहला मौका है जब कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। कंपनी की स्थापना 15 साल पहले 2008 हुई थी।



Financial safety tips

Learn how to stay safe online with tips from the government of India

[Learn more](#)

15 साल में पहली बार जोमैटो को मुनाफा... जानिए क्या है कंपनी का Business Model? by Ankit Avasthi Sir

☰ Top stories :


Zomato's Q1 earnings >



 mint

Zomato Q1 net profit jumps multifold to ₹253 crore as order value soars | Compan...

6 hours ago

 Moneycontrol

Zomato Q1 results: Net profit jumps multi-fold to Rs 253 crore ✓

6 hours ago



 The Economic Times

Zomato Q1 Results: Profit jumps multifold to Rs 253 cr; revenue soars 74% YoY ✓

4 hours ago




Zomato to launch new app called District >

 Inc42

Zomato To Launch New App 'District' For Going-Out Business ✓

5 hours ago



 Hindustan Times

Zomato to launch new app called District for 'going-out' business: What is it? ✓

5 hours ago



फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो का अप्रैल-जून तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 126.5 गुना बढ़कर 253 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2 करोड़ रुपए था।

जोमैटो ने गुरुवार, 1 अगस्त को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी की पहली तिमाही में आय (रेवेन्यू) 74% बढ़कर 4,206 करोड़ हो गई। एक साल पहले की समान तिमाही में रेवेन्यू 2,416 करोड़ रुपए था।

FY25 की पहली तिमाही में जोमैटो का मुनाफा 12,550% बढ़ा

सालाना आधार पर

जोमैटो	FY25 (अप्रैल-जून)	FY24 (अप्रैल-जून)	चेंज
ऑपरेशनल रेवेन्यू	₹4,206	₹2,416	74.09%
अदर इनकम	₹236	₹181	30.39%
टोटल इनकम	₹4,442	₹2,597	71.04%
टोटल खर्च	₹4,203	₹2,612	60.91%
नेट प्रॉफिट	₹253	₹2	12550%

तिमाही आधार पर

जोमैटो	FY25 (जनवरी-मार्च)	FY24 (अप्रैल-जून)	चेंज
ऑपरेशनल रेवेन्यू	₹4,206	₹3,562	18.08%
अदर इनकम	₹236	₹235	0.42%
टोटल इनकम	₹4,442	₹3,797	16.99%
टोटल खर्च	₹4,203	₹3,636	15.59%
नेट प्रॉफिट	₹253	₹175	44.57%

नोट - आंकड़े करोड़ रुपए में...



Deepinder Goyal

@deepigoyal



Out now - our Q1FY25 Report: blog.zomato.com/q1fy25

If you have any further questions or feedback, please email us at shareholders@zomato.com. Always listening!

Quick snapshots of how we're powering India's changing lifestyles

ato
shareholders' Letter
results
AUGUST 1, 2024

blog.zomato.com
Q1FY25 shareholders' letter and results

The image shows a social media post from Deepinder Goyal, CEO of Zomato. The post is a thread starting with a link to the Q1FY25 report. The main text asks for feedback and provides an email address. Below is a thread preview for the report, which includes a thumbnail with the Zomato logo, the text 'ato shareholders' Letter results AUGUST 1, 2024', and the URL 'blog.zomato.com Q1FY25 shareholders' letter and results'. The thread icon is a purple square with a white thread symbol.

3:49 PM · Aug 1, 2024 · **24.3K** Views

Deepinder Goyal  @deepigoyal · ...
[#Performance](#)
Our bottomline continues to grow with Adjusted EBITDA expanding to INR 299 crore - from INR 194 crore in the previous quarter.

Happy to share that our quick commerce business sustained Adjusted EBITDA break-even (achieved in March) despite new store openings.
(2/7)

1 2 16 1.7K

Deepinder Goyal  @deepigoyal · ...
[#Growth](#)
YoY topline growth remained steady at 62% while GOV growth accelerated to 53%.

Across our B2C businesses, the YoY growth in GOV stood at 27%, 130%, and 106% for the food delivery (@zomato), quick commerce (@letsblinkit), and going-out verticals, respectively.
(3/7)

1 1 15 1.4K

Deepinder Goyal  @deepigoyal · ...
[#QuickCommerce](#)
Average selection available to customers has increased 4-5x over the last 8 quarters. In some locations, we're now offering up to 25k unique SKUs!

Our plan is to get to 2,000 stores (from 639 currently) by the end of 2026 while remaining profitable.
(4/7)

1 1 14 1.3K

Deepinder Goyal  @deepigoyal · ...
[#GoingOut](#)
We see an opportunity to further expand our going-out offering than just dining-out, with use cases like movies, sports, shopping, staycations, etc.

Our new app, District (by Zomato), will be a one-stop destination for all things going-out. But more on that soon 😊
[Show more](#)

1 3 22 1.6K

Deepinder Goyal  @deepigoyal · ...
[#ESG](#)
Our emissions per km have reduced by 9.4% compared to FY22 - with a 4x YoY increase in orders delivered via EVs.

Meanwhile, The Shelter Project has scaled to 600 rest points across the country, set up in partnership with fuel stations and restaurant partners.

Under our
[Show more](#)

1 3 14 3.6K

Deepinder Goyal  @deepigoyal · ...
[#ThankYou](#)
That's all for now. However, as always, we are just 1% done. We're excited about the path we're on and grateful for your continued support.
(7/7)

3 2 14 3.2K

EBITDA

[ˈē-bit-,dä]

A widely used measure of corporate profitability, which stands for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization.



EBITDA

*Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation, and Amortization*

EBITDA measures earnings without the impact of debt costs, taxes, and the non-cash items depreciation and amortization.

Formula

EBITDA = net income + taxes + interest
expenses + depreciation
and amortization



**जोमैटो का शेयर 3.68% चढ़ा, 237.90
रुपए पर बंद**

रिजल्ट आने के बाद जोमैटो का शेयर **3.68% बढ़कर 237.90 रुपए पर बंद हुआ**। बीते 6 महीने में कंपनी का शेयर **69.26%** बढ़ा है। वहीं बीते एक साल में कंपनी के शेयर ने **180%** का रिटर्न दिया है। 1 अगस्त 2023 को जोमैटो 84.75 रुपए पर था।



Market Summary > Zomato Ltd

237.90 INR

+8.45 (3.68%) ↑ today

1 Aug, 3:30 pm IST • Disclaimer

+ Follow

1D | 5D | 1M | 6M | YTD | 1Y | 5Y | Max

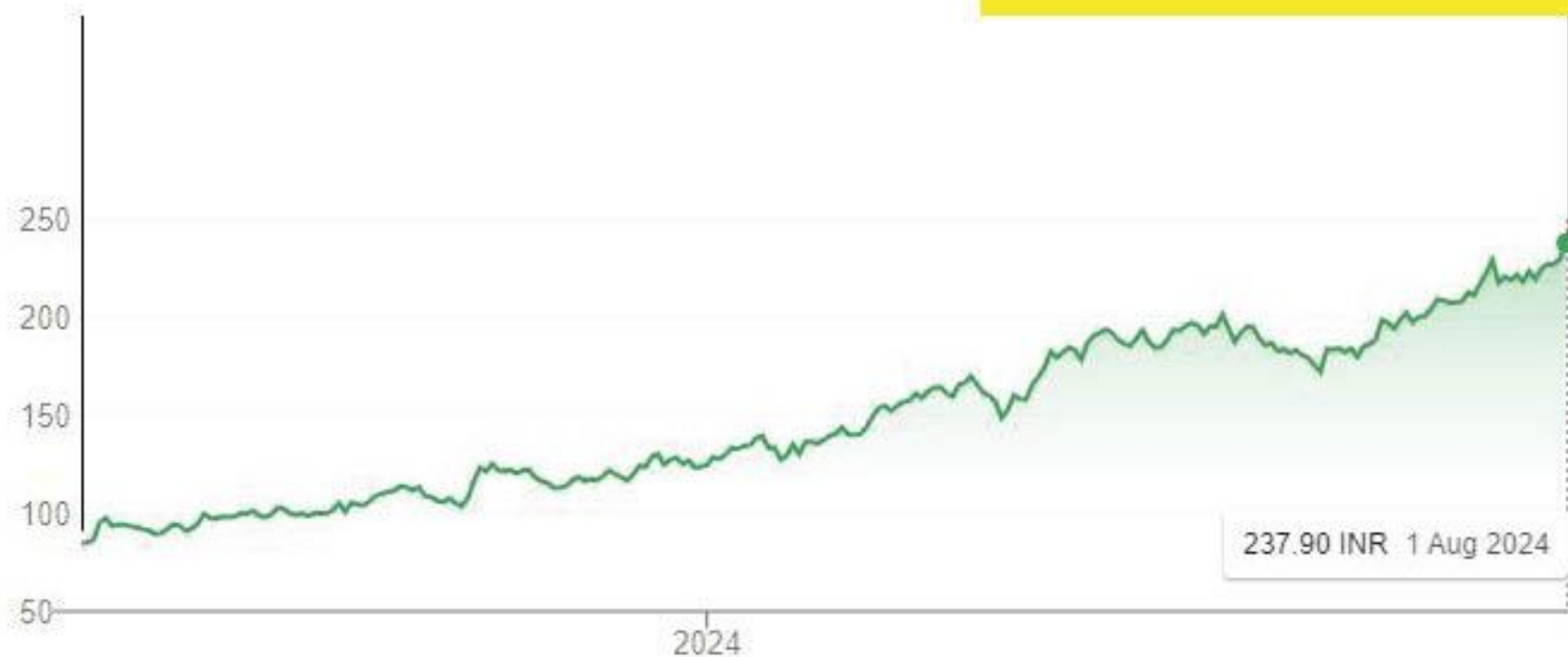


Open	231.00	Mkt cap	2.04LCr	52-wk high	238.00
High	238.00	P/E ratio	594.75	52-wk low	81.60
Low	228.00	Div yield	-		

एक साल में 180% चढ़ा जोमैटो का शेयर

1 अगस्त 2023- ₹84

1 अगस्त 2024- ₹237



डेढ़ साल में 400% चढ़ गए जोमैटो के शेयर

फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो के शेयर पिछले डेढ़ साल में 400 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। जोमैटो के शेयर 27 जनवरी 2023 को 46.95 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 1 अगस्त 2024 को 238 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वहीं, पिछले एक साल में जोमैटो के शेयरों में 179 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 1 अगस्त 2023 को 84.70 रुपये पर थे। जोमैटो के शेयर 1 अगस्त 2024 को 238 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस साल अब तक जोमैटो के शेयरों में 90 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2024 को कंपनी के शेयर 124.50 रुपये पर थे, जो कि अब 238 रुपये पर जा पहुंचे हैं।



कैसे हुई जोमैटो की शुरुआत ?



इस कंपनी की शुरुआत **2008** में हरियाणा के गुरुग्राम से हुई थी। तब इसका नाम जोमैटो नहीं बल्कि **Foodiebay** था, जो ebay से प्रेरित था। इसकी स्थापना **दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा** ने की थी। 2008 में जोमैटो फूड डिलीवरी नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट डिस्कवरी सर्विस थी, यानी इसका काम शहर के अलग-अलग रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी देना था।

ये सर्विस काफी सफल रही और 2 साल से भी कम समय में Foodiebay से 20 लाख कस्टमर्स और 8,000 रेस्टोरेंट्स जुड़ गए। **2010** के आखिर में कंपनी के फाउंडर ने इसे जोमैटो नाम से री-लॉन्च किया। इसके साथ ही कंपनी ने फूड डिलीवरी सर्विस भी शुरू कर दी।

इस तरह फूडीबे बना जोमैटो

2010 में इंफोएज के फाउंडर संजीव बिखचंदानी ने कंपनी में एक मिलियन डॉलर का निवेश किया. इसके बाद दूसरी कंपनियों ने भी इसमें निवेश की इच्छा जताई. नाम एक जैसा होने के कारण **2010 में ई-कॉमर्स कंपनी ईबे फूडीबे को लीगल नोटिस दिया तो नाम बदलने की बात कही.**

इस नोटिस के बाद **फूडीबे का नाम जोमैटो रखा गया.** इसका नाम बदलते ही कंपनी पूरी तरह से बदल गई. भारत में सफलता का इतिहास रच दिया. यह एक फूड एग्रीगेटर कंपनी बन गई यानी ऐसी कंपनी जिसका अपना कुछ नहीं है और रेस्तरां से फूड लेकर लोगों को डिलीवरी करने का काम करती है.

Legal Notice



कंपनी को मिलने लगी फंडिंग

एक समय जोमैटो केवल अपनी वेबसाइट पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना राजस्व कमा रहा था. **2012** में कंपनी टर्की और ब्राजील पहुंची. नवंबर **2013** तक सिकोइया कैपिटल इंडिया ने कंपनी के लिए **37 मिलियन डॉलर के फंडिंग** राउंड का नेतृत्व किया था. उस समय दोनों निवेशकों, सिकोइया और मौजूदा निवेशक इंफो एज ने जोमैटो को देखते हुए केवल \$150 मिलियन का मूल्यांकन देखा. भारत में सफलता मिलने के बाद फाउंडर दीपिंदर ने इसे दूसरे देशों तक ले जाने की योजना बनाई.

24 देशों में पहुंची जोमैटो

पिछले 10 सालों में यह कंपनी 24 देशों में अपना विस्तार कर चुकी है. इनमें न्यूजीलैंड, फिलिपींस, यूएई, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, कतर और इंडोनेशिया शामिल हैं. जोमैटो ने न सिर्फ कंपनी का विस्तार किया बल्कि कई देशी-विदेशी कंपनियों को भी खरीदा. इनमें **ऊबर ईट्स** और **ग्रोसरी वेंचर बिलंकिट फिटसो** शामिल हैं.



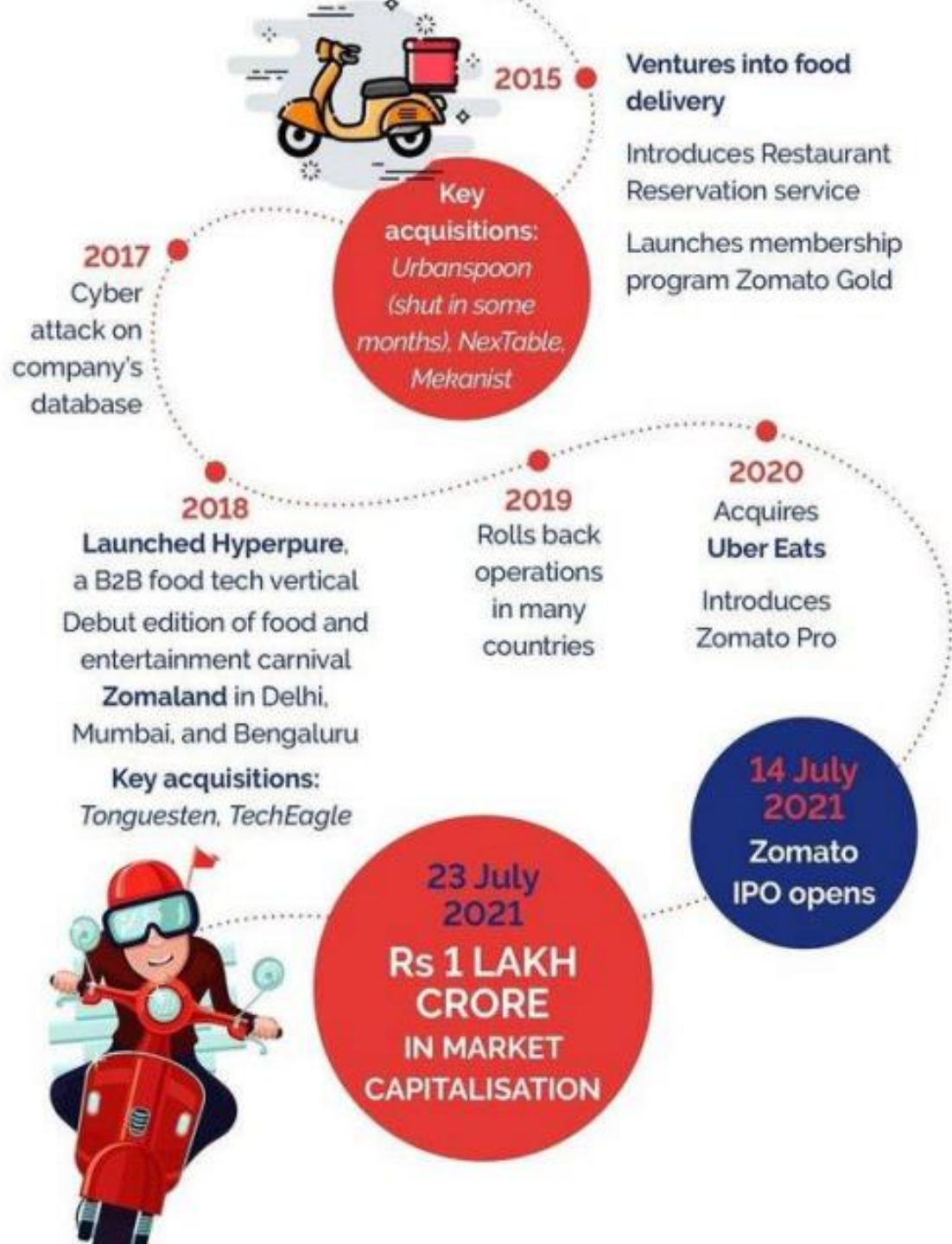


2014

Key acquisitions:
*Lunchtime, Obedovat,
Cibando, Menumania,
Gastronauci*

2013

Launched in New
Zealand, Turkey,
and Brazil



SHARES PRICED AT ₹72-76 A PIECE

- The price band for the Zomato IPO is set at ₹72-76, according to exchange filings
- Due to strong demand for its shares from large institutional investors, Zomato has upped the IPO size from about ₹7,500cr
- Info Edge India, which has a large stake in the food delivery co, has also halved its offer for sale from ₹750cr



Zomato IPO
(expected timeline)



Opens on | July 14

Closes on | July 16

Lists on | July 27

IPO size |
₹9,375 crore

Post-listing valuation | \$8-10bn

At Rs 2 crore, Zomato turns profitable for first time this quarter

Synopsis
 The Gurgaon-based company reported a net profit of Rs 2 crore for the three-month period ended June 30 as against a net loss of Rs 186 crore in the same period last year. Zomato also reported a 70% year-on-year surge in operating revenue to Rs 2,416 crore.



Zomato's CEO Deepinder Goyal

Food and grocery delivery platform [Zomato](#) reported its first ever consolidated net profit and a 71% increase in operating revenue in the seasonally strong fiscal first quarter, when the company benefitted also from a "higher frequency of ordering" by subscribers of its recently relaunched loyalty programme.

Amazon Top Deals powered by amazon.in

<p>19% OFF</p> <p>IFB 8 Kg 5 Star AI Powered Fully...</p> <p>₹36,890</p> <p>Buy Now</p>	<p>30% OFF</p> <p>Crompton Ozone Desert Air Cooler...</p> <p>₹10,990</p> <p>Buy Now</p>
---	---

VIEW TODAY'S TOP DEALS ON AMAZON »

BBK Baaten Bazar Ki... **05 Aug**

15 साल में पहली बार जोमैटो को मुनाफा...

zomato

जानिए क्या है कंपनी का Business Model?

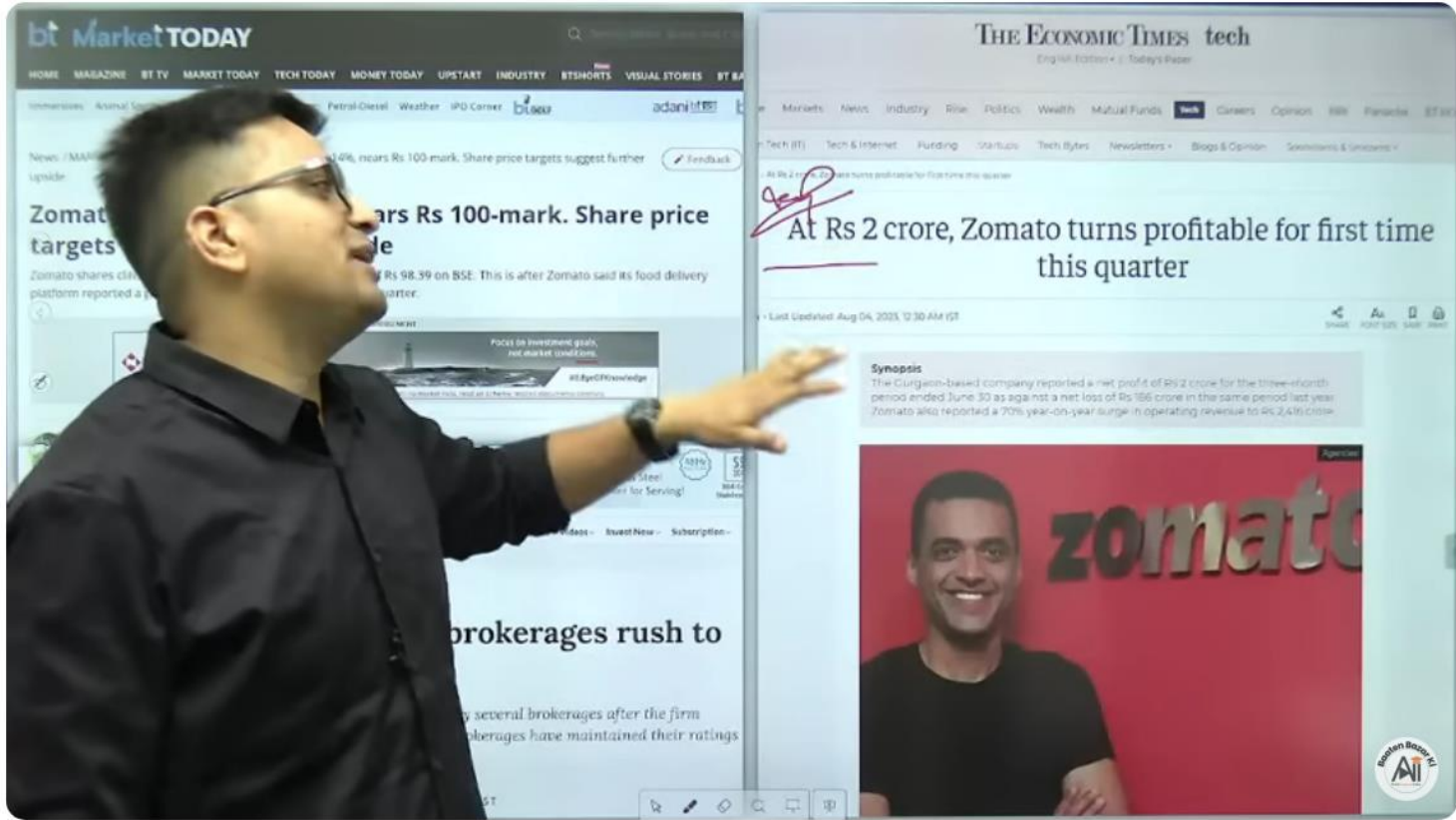
BY ANKIT AVASTHI SIR

23:52



15 साल में पहली बार जोमैटो को मुनाफा... जानिए क्या है कंपनी का Business Model? by Ankit...

382K views • Streamed 11 months ago **21x**



The screen shows two news articles. The left article from 'bt Market TODAY' is titled 'Zomato shares rise to Rs 100-mark. Share price targets suggest further upside'. The right article from 'THE ECONOMIC TIMES tech' is titled 'At Rs 2 crore, Zomato turns profitable for first time this quarter'. A handwritten signature is visible over the right article. Below the articles is a video thumbnail of a man in a Zomato uniform.

Financial safety tips
Learn how to stay safe online with tips from the government of India [Learn more](#)

15 साल में पहली बार जोमैटो को मुनाफा... जानिए क्या है कंपनी का Business Model? by Ankit Avasthi Sir

Zomato approves Blinkit acquisition for ₹4,447 crore

China's Ant Group-backed Zomato already owns a more than 9% stake in Blinkit

Livemint

Published • 24 Jun 2022, 07:18 PM IST

Up to 10 Lakhs

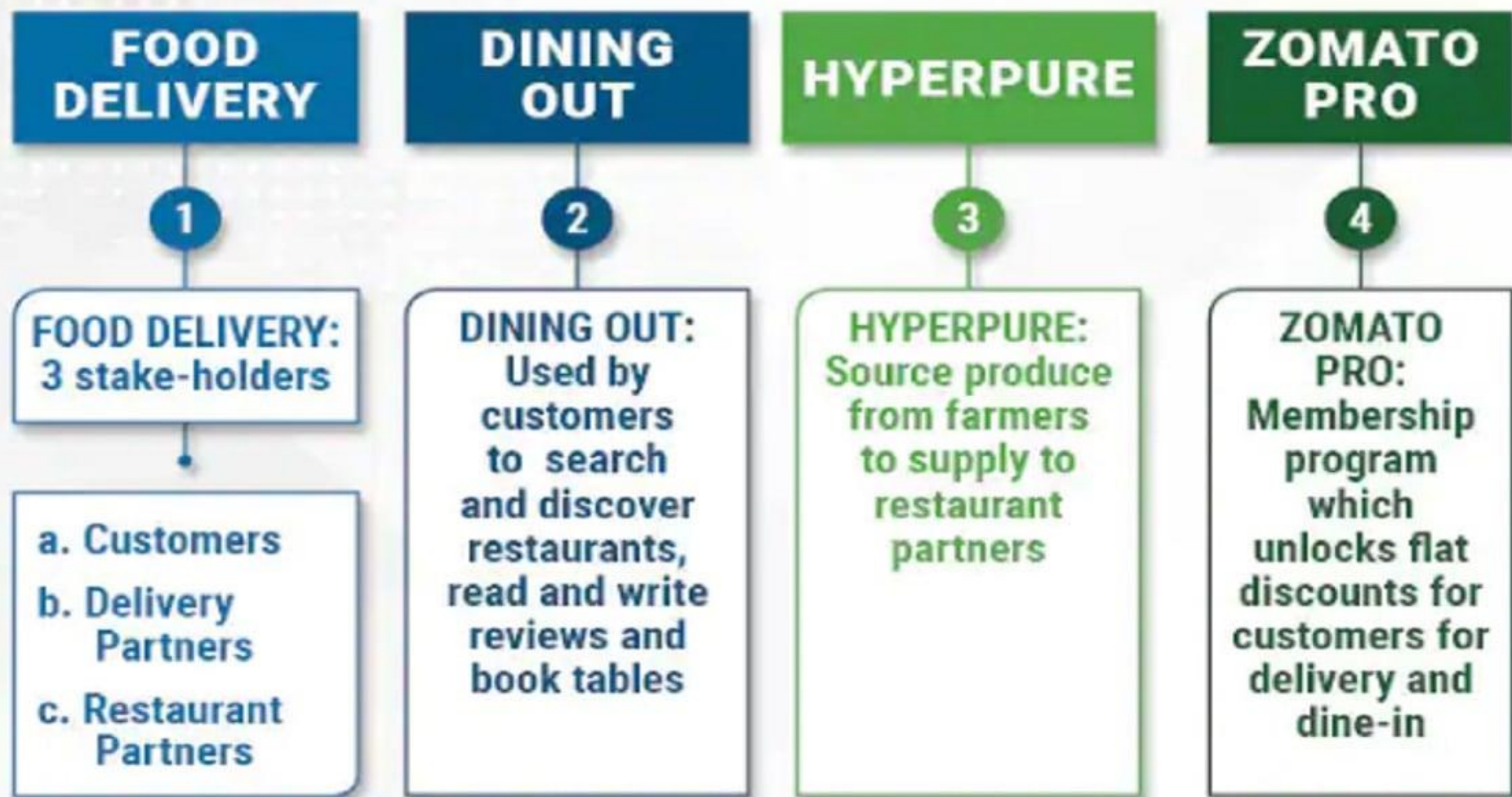




zomato **Business & Revenue Model Explained.**



HERE'S HOW ZOMATO MAKES MONEY



क्या है जोमैटो का बिजनेस मॉडल?

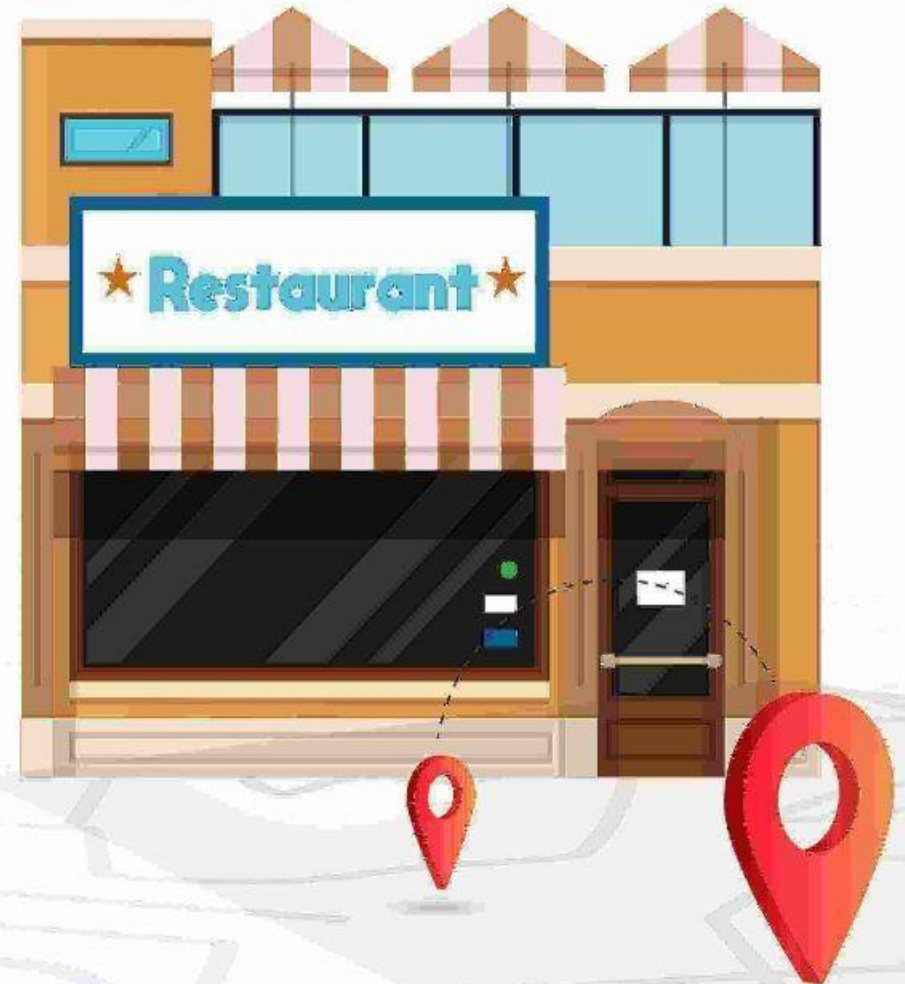
कंपनी एक-दो नहीं बल्कि कई तरीकों से पैसे कमाती है. पिछले कई सालों से कंपनी मुनाफा नहीं कमा पा रही थी, लेकिन अब कंपनी फायदे में आ गई है. आइए जानते हैं किन-किन तरीकों से कंपनी की होती है कमाई.





Register with

zomato



1- रेस्टोरेंट लिस्ट कराना

जोमैटो की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा कंपनी के ऐप पर रेस्टोरेंट लिस्ट कराने से आता है. एक रेस्टोरेंट की लिस्टिंग के लिए कंपनी करीब 1000 रुपये चार्ज करती है. यह वन टाइम फीस है, जो रेस्टोरेंट को चुकानी होती है, भले ही उसे ऑर्डर आएँ या ना आएँ.





2- विज्ञापन से होती है तगड़ी कमाई

ऐप पर ही कंपनी कई रेस्टोरेंट के विज्ञापन दिखाती है और बदले में उनसे पैसे चार्ज करती है. जिस रेस्टोरेंट को जोमैटो जितनी ज्यादा विजिबिलिटी देता है, उससे उतनी ही ज्यादा फीस वसूलता है और कमाई करता है. विज्ञापन के जोमैटो के अलग-अलग पैकेज हैं, जो अलग-अलग फायदे ऑफर करते हैं.

3- डिलीवरी फीस भी कमाई का तरीका

जब आप जोमैटो से कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो उस पर तीन तरह का चार्ज चुकाते हैं. पहला प्रोडक्ट यानी खाने की कीमत. दूसरा रेस्टोरेंट हैंडलिंग चार्ज. वहीं तीसरे नंबर पर आता है डिलीवरी चार्ज, जो जोमैटो आपसे चार्ज करता है किसी भी प्रोडक्ट को डिलीवर कराने के लिए.

4- रेस्टोरेंट से कमीशन

कई बार आपने देखा होगा कि किसी रेस्टोरेंट का खाना जोमैटो पर महंगा दिखता है. ऐसा इसलिए क्योंकि तमाम रेस्टोरेंट को जोमैटो के ऐप का इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोडक्ट बेचने पर एक कमीशन चुकाना होता है. ऐसे में जोमैटो से खाना मंगवाने पर यह चार्ज भी रेस्टोरेंट ग्राहकों से ही वसूलते हैं. यह चार्ज भी 2-3 पैकेज में दिया जाता है, जो आपकी ऑर्डर वैल्यू का 23% से लेकर 27% तक होता है.

5- लॉयल्टी प्रोग्राम से भी कमाता है जोमैटो

जोमैटो ने अपने लॉयल्टी प्रोग्राम से अधिक से अधिक ग्राहकों को खुद से जोड़ने की कोशिश की है. तमाम कंपनियों की तरह जोमैटो भी एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलाता है, जिससे वह अधिक से अधिक ग्राहकों को खुद से जोड़ता है. इसके तहत कंपनी जोमैटो गोल्ड का सब्सक्रिप्शन देती है, जिसकी कीमत अलग-अलग अवधि के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. यह भी कंपनी की कमाई का एक जरिया है. हालांकि, कंपनियां इसे कमाई से ज्यादा ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के टूल की तरह देखती हैं और इसके चलते बाकी तरीकों से होने वाली कमाई खुद ही बढ़ जाती है.

6- इवेंट्स टिकट सेल भी कमाई का जरिया

जोमैटो की तरफ से कुछ खास इवेंट की टिकट बेची जाती हैं. इन इवेंट के जरिए ग्राहकों को एक खास रेस्टोरेंट तक पहुंचाया जाता है. इससे उस रेस्टोरेंट की कमाई होती है और उसका एक हिस्सा जोमैटो को मिलता है. यह फीचर जोमैटो पर Zomato Live नाम से मिल सकता है.

blinkit



zomato

7- प्लेटफॉर्म फीस

अगर आप जोमैटो से कुछ ऑर्डर करते हैं तो वहां पर आपको एक प्लेटफॉर्म फीस भी दिखाई देती होगी. अभी यह फीस 5 रुपये है. जोमैटो ने पिछले साल अगस्त में 2 रुपये का प्लेटफॉर्म शुल्क लगाना शुरू किया था. इसके बाद इसे बढ़ाकर 3 रुपये कर दिया था। नए साल की पूर्व संध्या पर इसे बढ़ाकर 4 रुपये कर दिया। इस तरह देखा जाए तो करीब 6-7 महीनों में प्लेटफॉर्म शुल्क में ढाई गुना तक की बढ़ोतरी हो गई है. कंपनी हर साल करीब 1 अरब यानी 100 करोड़ सालाना ऑर्डर के आंकड़े पर पहुंच चुकी है. इस तरह देखें तो सालाना 100 करोड़ ऑर्डर से कंपनी करीब 500 करोड़ रुपये कमा सकती है.

8- क्विक कॉमर्स- ब्लिंकइट

क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकट भी जोमैटो का ही हिस्सा है. इससे सामान मंगवाने में आप जो डिलीवरी फीस, प्लेटफॉर्म फीस या कोई और चार्ज देते हैं, वह भी जोमैटो के ही खाते में जुड़ता है. वहीं ब्लिंकइट पर तमाम वेंडर्स की लिस्टिंग का जो चार्ज लिया जाता है, वह भी जोमैटे को ही मिलता है. Goldman Sachs के अनुसार 2 सालों में ब्लिंकइट की वैल्यू जोमैटो के मूल बिजनेस यानी ऑनलाइन फूड डिलीवरी से भी अधिक हो गई है. ब्लिंकइट का वैल्युएशन करीब 13 अरब डॉलर का हो चुका है, जो मार्च 2023 में महज 2 बिलियन डॉलर का था. बता दें कि जोमैटो का कुल वैल्युएशन करीब 20 अरब डॉलर है, जिसमें से 13 अरब डॉलर तो सिर्फ ब्लिंकइट का वैल्युएशन है.

Zomato approves Blinkit acquisition for ₹4,447 crore

China's Ant Group-backed Zomato already owns a more than 9% stake in Blinkit

Livemint

Published • 24 Jun 2022, 07:18 PM IST

Up to 10 Lakhs



9- हाइपरप्योर से कमाई

जोमैटो का एक और बिजनेस मॉडल है, जिसका नाम है **हाइपरप्योर**. यह बिजनेस खासतौर पर अपने वेंडर्स को थोक में सामान सप्लाई करता है. यानी **आप अगर जोमैटो के वेंडर हैं और आपको आटा, चावल, दाल, सब्जी, फल या कोई पैकेजिंग का सामान चाहिए, तो वह सब आपको हाइपरप्योर से बहुत ही अच्छे दाम पर मिल सकता है. इस तरह कंपनी हाइपरप्योर से भी जो कमाई करती है, वह जोमैटो के ही खाते में जुड़ता है.**

10- जोमालैंड इवेंट का आयोजन

जोमैटो की तरफ से समय-समय पर **जोमालैंड इवेंट** का आयोजन किया जाता है. इस इवेंट में उस शहर के बहुत सारे लोग जमा होते हैं, जिस शहर में यह इवेंट होता है. **यह एक तरह का फूड एंटरटेनमेंट कार्निवल होता है, जिससे कंपनी तगड़ी कमाई करती है. बता दें कि इसका आयोजन Zomato Live की तरफ से कराया जाता है.**





Deepinder Goyal 

@deepigoyal



Coming soon.



3:14 PM · Jul 31, 2024 · 328.9K Views



NCERT

**OFFER
FEE**



FOUNDATION BATCH

4999 Rs

REOPEN

**LIMITED OFFER
REGISTRATION START**

1. SUBJECTS TO BE TAUGHT (NCERTS FROM CLASS 6TH-12TH)
2. SUBJECTS: GEOGRAPHY, POLITY, HISTORY, INDIAN ECONOMY,
3. LIVE LECTURES DELIVERED IN HINGLISH LANGUAGE BY ANKIT AVASTHI SIR.
4. SPECIAL EMPHASIS ON CONCEPTUAL CLARITY IN CLASSES.
5. ALIGNMENT WITH UPSC AND STATE PSC PATTERN:
6. UNIT WISE WEEKLY TESTS THROUGH UNIQUE WORK BOOK STYLE

BY ANKIT AVASTHI SIR

FOR UPSC & VARIOUS STATE PSC EXAM

2024

GA FOUNDATION

RECORDED BATCH

Apni
Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Subject

HISTORY ,POLITY

GEOGRAPHY

ECONOMICS

Price

1499 /-

**Validity
1 Year**

By Ankit Avasthi Sir





LAUNCHING



BPSC

TEST SERIES

299/- ONE YEAR

- 50+ Mock Test
- 10+ Topic wise test
- 30+ PYQ's
- 65 + Current Affairs

Buy Now!

By Ankit Avasthi Sir





LAUNCHING



RO/ARO
TEST SERIES

299/- ONE
YEAR

- 30+ Mock Test
- 13+ Sectional test
- 8+ PYQ's
- 60 + Current Affairs

Buy Now!

By Ankit Avasthi Sir





UP POLICE बनने का सपना होगा साकार !

NEW

LAUNCHING



Test Series

UP POLICE EXAM



FEATURES

- ⇒ 20 Mock Test
- ⇒ 21 Sectional Test
- ⇒ 10 Practice Test
- ⇒ 25+ Topic Wise Test
- ⇒ 8+ PYQ's
- ⇒ 65+ Current Affairs Test

BUY NOW!

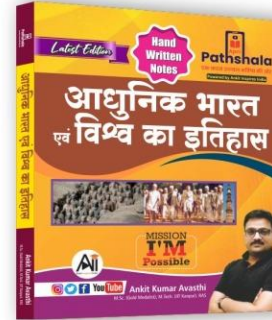
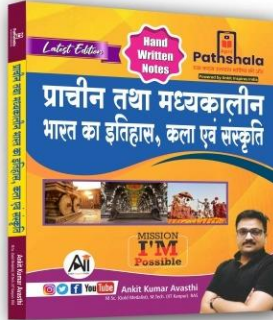
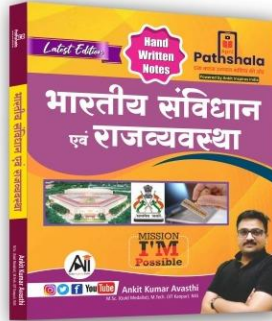
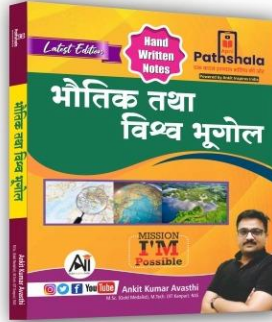
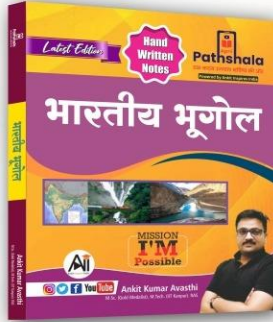
99/-

for ONE YEAR

By Ankit Avasthi Sir

GA FOUNDATION

Hand Written
Notes



₹ Only
1999

6 पुस्तकों
का
सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए
गए नंबर पर संपर्क करें....

 **7878158882**

- सिन्धु नदी का उद्गम किलाश पर्वतीय क्षेत्र में बीखर-सू हिमनद से होता है।
- तिब्बत में इस नदी को सिंगी खंबान कहते हैं।
- यह फमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है।
- यह नदी भारत में लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी के बीच बहती है।
- पाकिस्तान में यह अटक (Attock) नामक स्थानों पर मैदानों में प्रवेश करती है।
- पाकिस्तान में कराँची के पास डेल्टा बनते हुए यह अरब सागर में गिरती है।
- सिन्धु नदी की दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदियाँ :- श्योक, रुद्रा, हुनजा, गिलागिट, स्वात, काबुल तथा गोमल
- इसकी प्रमुख बायें हाथ की सहायक नदियाँ झेलम, पिनाब, रावी, व्यास, सतलज, द्रास तथा जास्कर पंचनद
- सिन्धु से पंचनद पाक में मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है।
- 'लेट' सिन्धु नदी के किनारे स्थित है।

पंचनद

i) झेलम :- इस नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में

- बेरिनाग झील से होता है।
- * यह नदी बल्लर झील का निर्माण करती है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
- इस नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है।
- किशनगंगा इसकी दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदी है।
- इस नदी पर तुलबुल परियोजना प्रस्तावित है। यह एक नवविद्यन परियोजना है।
- यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है।

ii) पिनाब :- पिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बारालच्छा दर्रे के पास चन्द्र तथा भागा नदियों के मिलने (Confluence) से होता है।

- 1962 में इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ स्थित हैं।

उदाहरण :- तुलहस्ती, सलाब, बगलिहार

- यह सिन्धु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।

iii) रावी :- रावी नदी का उद्गम शैलांग दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में होता है।

- हिमाचल प्रदेश में इन नदी पर चमेरा बाँध स्थित है।
- पंजाब में इस नदी पर धीन परियोजना स्थित है।

₹ 1999



3

Li

Lithium

6.941





Why investors did not pick up Jammu and Kashmir lithium block in auction

Ministry of Mines has scrapped the auction for the lithium block in J&K'S Reasi for the second time. Difficulty in extracting and processing...

1 day ago

 Business Standard 

[J&K lithium block fails to secure bids in 2nd attempt as well: Report](#)

The government in February 2023 found its first lithium deposits in Jammu and Kashmir with estimated reserves of 5.9 million metric tons.

1 month ago

 Business Today 

[Jammu and Kashmir lithium blocks to be auctioned again in third tranche](#)

The auction for Jammu and Kashmir lithium blocks will take place as the government received only two bids in the first round.

22 Mar 2024

 The Economic Times 

[India to auction Jammu and Kashmir lithium blocks again after weak 1st round](#)



Kashmir lithium block in auction

Ministry of Mines has scrapped the auction for the lithium block in J&K'S Reasi for the second time.

Difficulty in extracting and processing lithium, and sub-par reporting standards have kept investors away.

India to auction **lithium reserves found** in Jammu and Kashmir by December: Mines secretary

“We have completed the consultation process with stakeholders on the amendment of the offshore Mining Act,” said Vivek Bharadwaj

May 02, 2023 01:12 pm | Updated 03:33 pm IST - New Delhi



PIB

<https://pib.gov.in> > PressReleaseDetailm

Geological Survey of India Finds Lithium and Gold Deposits ✓

9 Feb 2023 — Geological Survey of India has for the first time established **Lithium** inferred resources (G3) of 5.9 million tonnes in Salal-Haimana area of ...

Geological Survey of India Finds Lithium and Gold Deposits

51 Mineral Blocks including Lithium and Gold were handed over to State Governments

Posted On: 09 FEB 2023 7:19PM by PIB Delhi

Geological Survey of India has for the first time established Lithium inferred resources (G3) of 5.9 million tonnes in Salal-Haimana area of Reasi District of Jammu & Kashmir (UT). This report along with 15 other resource bearing geological reports (G2 & G3 stage) and 35 Geological memorandums were handed over to respective state governments during the 62nd Central Geological Programming Board (CGPB) meeting held on 09th February 2023. Out of these 51 mineral blocks, 5 blocks pertain to gold and other blocks pertain to commodities like potash, molybdenum, base metals etc. spread across 11 states of Jammu & Kashmir (UT), Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu and Telangana.. The blocks were prepared based on the work carried out by GSI from field seasons 2018-19 to till date.

Apart from these, 17 reports of Coal and Lignite with a total resource of 7897 million tones were also handed over to Ministry of Coal. Seven Publications on different themes and intervention areas in which GSI operates was also released during the meeting.

The proposed Annual Programme for ensuing Field Season 2023-24 was presented and discussed during the meeting. During the ensuing year 2023-24, GSI is taking up 966 programmes comprising 318 mineral exploration projects including 12 marine mineral investigation projects. Major thrust has been given on the exploration of strategic - critical and fertilizer minerals. A total of 115 projects on strategic & critical minerals including 16 projects on fertilizer minerals have been formulated. In addition, 55 programmes on geoinformatics, 140 programmes on fundamental and multidisciplinary geosciences and 155 programs for training and institutional capacity building have also been taken up.

The Central Geological Programming Board (CGPB) is an important platform of the Geological Survey of India (GSI), Ministry of Mines wherein the Annual Field Season Program (FSP) of GSI is placed for discussion for synergy and to avoid duplication of work. The members of CGPB and other stakeholders like State Governments, Central/ State Government Mineral Exploration Agencies, PSUs and Private Entrepreneurs place their requests for collaborative work with GSI. Based on the priorities set by the Government of India and the importance and urgency of proposals presented by the members and stakeholders, the Annual Programme of GSI is given a final shape.

During his address to the gathering, Shri Vivek Bharadwaj, Secretary, Ministry of Mines and Chairman CGPB, congratulated GSI in realizing the commitment made by Central Government for auction of 500 blocks by submitting 287 geological memorandum and 195 G2&G3 reports to the state government since 2015. However, he asserted that GSI should carry forward this momentum and continue the field programmes with the same vigor.

Lithium reserves found in Jammu and Kashmir

admin · February 10, 2023 · 1 minute read



Lithium reserves found at Reasi, Jammu & Kashmir

Geological Survey of India



भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA



खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारत सरकार | Govt. of India



lithium reserves in jammu and kashmir



All News Images Videos Shopping Maps Books ⋮ More

Tools

5.9 million metric tons

 हिन्दी में

 In English

The government in February 2023 found its first lithium deposits in Jammu and Kashmir with estimated reserves of **5.9 million metric tons**. After it failed to get a required minimum of three bids in its first auctions in November, the block was again put up for auction in March with a May 14 deadline for bids. 3 Jul 2024

Jammu and Kashmir lithium block gets no bids in second attempt

Reuters • Last Updated: Jul 03, 2024, 02:54:00 PM IST

 FOLLOW US  SHARE  FONT SIZE  SAVE  PRINT  COMMENT

Synopsis

India's Jammu and Kashmir failed to attract bids in its second attempt to auction mining rights for newly discovered lithium reserves, estimated at 5.9 million metric tons. The block may now be assigned to a government agency for further exploration. This comes amid India's strategic focus on securing critical minerals for electric vehicle batteries.



Agencies

[India's Jammu and Kashmir](#) did not receive any bids in a second attempt to auction mining rights for [lithium reserves](#) found last year, according to a source with direct knowledge of the

सरकार ने खानों की बिक्री के तीसरे चरण के तहत तीन महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक की नीलामी रद्द कर दी है। इनमें एक जम्मू-कश्मीर की लिथियम खान भी शामिल है।

बोलीकर्ताओं की संख्या निर्धारित से कम होने की वजह से सरकार ने नीलामी रद्द की है। सरकार यह नीलामी स्वच्छ विकल्प और महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए करने जा रही है।

जिन तीन ब्लॉक की नीलामी रद्द की गई है उनमें 1. जम्मू-कश्मीर में सलाल-हैमना लिथियम, टाइटेनियम और बॉक्साइट (एल्युमिनस लेटराइट) ब्लॉक, 2. झारखंड में मस्कानिया-गरेरियाटोला-बारवारी पोटाश ब्लॉक और 3. तमिलनाडु में कुरुंजाकुलम ग्रेफाइट ब्लॉक शामिल हैं।



2023 में जम्मू और कश्मीर में मिला था लिथियम का भंडार :

फरवरी 2023 में सरकार को **जम्मू और कश्मीर में अपना पहला लिथियम भंडार मिला**, जिसका अनुमानित भंडार 5.9 मिलियन मीट्रिक टन है।

नवंबर 2023 में पहली नीलामी :

नवंबर में अपनी पहली नीलामी में आवश्यक न्यूनतम तीन बोलियां प्राप्त करने में असफल रहने के बाद , इस ब्लॉक को मार्च में पुनः नीलामी के लिए रखा गया तथा बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 14 मई थी।

चूकी कोई बोली न लगने के कारण आगे की इस ब्लॉक की खोज के लिए किसी सरकारी एजेंसी को खनन का काम दिए जाने की संभावना है।

भारत के खान मंत्रालय ने टिप्पणी के लिए कोई तुरंत जवाब नहीं दिया।

नीलामी के प्रयास (Auction attempts):

1. पहला प्रयास (First Attempt): नवंबर 2023 में पहली नीलामी हुई थी।

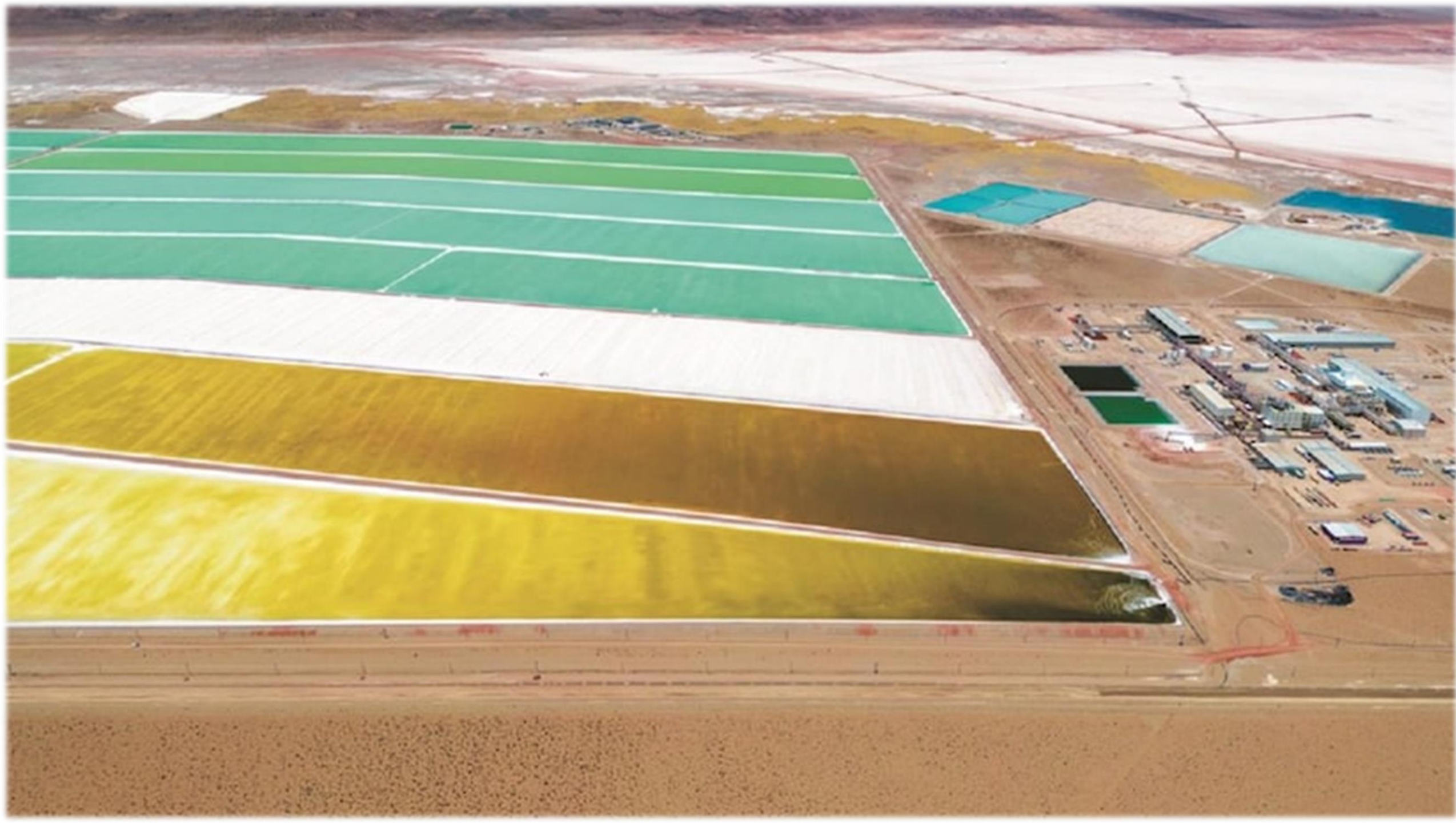
- लेकिन तीन से कम बोलीदाताओं के योग्य(qualify) होने के कारण इसे 13 मार्च को रद्द कर दिया गया था।

2. दूसरा प्रयास: दूसरी नीलामी का प्रयास भी किया गया था।

- लेकिन इस बार भी आवश्यक न्यूनतम तीन बोलियां प्राप्त करने में असफल रहने के बाद , इसे फिर से रद्द कर दिया गया।

विनियामक ढांचा (Regulatory Framework): खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के अनुसार, अगर तीन से कम बोलीदाता (bidders) योग्य (qualify) होते हैं, तो नीलामी दूसरे दौर में जा सकती है।

लेकिन इस मामले में, कोई भी बोलीदाता (bidders) योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं कर सका।



Investors' hesitation:

1. Geological hurdles–

A) The lithium found in **Kashmir** is in the form of **clay deposits mixed with other minerals**, unlike the **commercially viable brine or hard rock deposits** mined globally. **Extracting lithium from such deposits is yet to be tested commercially**, and **India's mining industry lacks the required technical expertise.**

B) Further, **J&K** is **ecologically sensitive** and falls under **seismic zone-V** a classification for the most **seismically active regions**. **These factors make any industrial intervention in the area a challenging task.**

2. Sensitive Location-: The location of the reserves in **Kashmir**, close to the Line of Control and in an ecologically fragile Himalayan region, poses additional challenges due to potential political volatility and local resistance.

3. Mineral Exploration and Classification: Mineral exploration has four stages – G4, G3, G2, and G1 – as per the United Nations Framework Classification for Reserves/Resources (UNFC-1997), starting with G4. Each stage progresses from initial identification to a detailed understanding of the resource. The lithium reserves in Kashmir are currently classified under G3, which is the second preliminary exploration stage. This indicates a low level of confidence in the estimates of quantity, grade, and mineral content.

5. Reserve Price: The reserve price set for the second auction attempt was based on the highest initial bid offer from the previous round. If this reserve price was deemed too high relative to the perceived value or risk of the block, it could have deterred potential bidders.

6. Economic Viability Concerns: The extraction of lithium is expensive, and with global lithium prices falling, investors are wary of potential financial losses.

The current reporting standards do not provide enough clarity on the project's profitability, further deterring investment.

7. Other complaints of prospective bidders:

- **Bid documents have limited information of the block.**
- **Block being too small to apply modern mineral systems-based tools,**
- **No clarity on whether any beneficiation study had been conducted to assess the feasibility of extracting and processing lithium from the resources identified in J&K.**

United Nations Resource Classification Framework (UNFC)

संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण रूपरेखा (UNFC) एक अंतरराष्ट्रीय मानक है जिसका उपयोग खनिज, पेट्रोलियम और अन्य ऊर्जा संसाधनों के मूल्यांकन और वर्गीकरण के लिए किया जाता है। यह रूपरेखा विभिन्न संसाधनों की मात्रा, गुणवत्ता, और संभाव्यता का आकलन करने के लिए एक संगठित दृष्टिकोण प्रदान करती है।

वर्गीकरण को चार चरणों में विभाजित किया गया है:

G4: प्रारंभिक अन्वेषण (Reconnaissance): सबसे प्रारंभिक चरण जहां केवल संभावित क्षेत्रों की पहचान की जाती है।

G3: प्रारंभिक अन्वेषण (Preliminary Exploration): इस चरण में संभावित क्षेत्रों का प्रारंभिक अध्ययन और परीक्षण किया जाता है।

G2: विस्तृत अन्वेषण (Detailed Exploration): विस्तृत अध्ययन और परीक्षण के माध्यम से संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता का अधिक सटीक आकलन किया जाता है।

G1: विस्तृत विकास (Detailed Development): इस चरण में संसाधनों की व्यावसायिक निकासी और विकास के लिए पूर्ण योजना और डिजाइन तैयार किया जाता है।

Category	Definition
G1	Quantities associated with a known deposit that can be estimated with a high level of confidence.
G2	Quantities associated with a known deposit that can be estimated with a moderate level of confidence.
G3	Quantities associated with a known deposit that can be estimated with a low level of confidence.
G4	Estimated quantities associated with a potential deposit, based primarily on indirect evidence.





Lithium

क्या है ?



GROUP																18			
1											13	14	15	16	17	18			
1 H Hydrogen											5 B Boron	6 C Carbon	7 N Nitrogen	8 O Oxygen	9 F Fluorine	10 Ne Neon			
2 Li Lithium	4 Be Beryllium											13 Al Aluminium	14 Si Silicon	15 P Phosphorus	16 S Sulfur	17 Cl Chlorine	18 Ar Argon		
3 Li Lithium	4 Be Beryllium	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al Aluminium	14 Si Silicon	15 P Phosphorus	16 S Sulfur	17 Cl Chlorine	18 Ar Argon		
11 Na Sodium	12 Mg Magnesium	19 K Potassium	20 Ca Calcium	21 Sc Scandium	22 Ti Titanium	23 Va Vanadium	24 Cr Chromium	25 Mn Manganese	26 Fe Iron	27 Co Cobalt	28 Ni Nickel	29 Cu Copper	30 Zn Zinc	31 Ga Gallium	32 Ge Germanium	33 As Arsenic	34 Se Selenium	35 Br Bromine	36 Kr Krypton
37 Rb Rubidium	38 Sr Strontium	39 Y Yttrium	40 Zr Zirconium	41 Nb Niobium	42 Mo Molybdenum	43 Tc Technetium	44 Ru Ruthenium	45 Rh Rhodium	46 Pd Palladium	47 Ag Silver	48 Cd Cadmium	49 In Indium	50 Sn Tin	51 Sb Antimony	52 Te Tellurium	53 I Iodine	54 Xe Xenon		
55 Cs Cesium	56 Ba Barium	57 - 71 lanthanides	72 Hf Hafnium	73 Ta Tantalum	74 W Tungsten	75 Re Rhenium	76 Os Osmium	77 Ir Iridium	78 Pt Platinum	79 Au Gold	80 Hg Mercury	81 Tl Thallium	82 Pb Lead	83 Bi Bismuth	84 Po Polonium	85 At Astatine	86 Rn Radon		
87 Fr Francium	88 Ra Radium	89 - 103 Actinides	104 Rf Rutherfordium	105 Db Dubnium	106 Sg Seaborgium	107 Bh Bohrium	108 Hs Hassium	109 Mt Meitnerium	110 Ds Darmstadtium	111 Rg Roentgenium	112 Cn Copernicium	113 Nh Nihonium	114 Fl Flerovium	115 Mc Moscovium	116 Lv Livermorium	117 Ts Tennessine	118 Og Oganesson		

3 ← Atomic number

Li ← Symbol

Lithium ← Name

[He] 2s¹ ← Electron configuration

Alkali metal

57 La Lanthanum	58 Ce Cerium	59 Pr Praseodymium	60 Nd Neodymium	61 Pm Promethium	62 Sm Samarium	63 Eu Europium	64 Gd Gadolinium	65 Tb Terbium	66 Dy Dysprosium	67 Ho Holmium	68 Er Erbium	69 Tm Thulium	70 Yb Ytterbium	71 Lu Lutetium
89 Ac Actinium	90 Th Thorium	91 Pa Protactinium	92 U Uranium	93 Np Neptunium	94 Pu Plutonium	95 Am Americium	96 Cm Curium	97 Bk Berkelium	98 Cf Californium	99 Es Einsteinium	100 Fm Fermium	101 Md Mendelevium	102 No Nobelium	103 Lr Lawrencium

LITHIUM

01

Third element
in the periodic
table

03

Lightest and
the least
dense metal

02

Grey, shiny,
non-ferrous
alkali metal



04

Dubbed as
'White Gold'

05

Highly reactive

लिथियम क्या है (What is Lithium)?

लिथियम (Li) एक हल्का, चांदी-सफेद धातु (silvery-white metal) है जो अल्कली धातु समूह (alkali metal group) का सदस्य है। यह प्रकृति में पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के खनिजों और नमक के रूप में मौजूद होता है।



लिथियम के उपयोग (Uses of Lithium)

बैटरी निर्माण (Battery manufacturing) :

- **लिथियम-आयन बैटरी:** मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में व्यापक रूप से उपयोग होती हैं।

दवा (Medicine):

- **मनोविकार चिकित्सा (Psychiatric therapy):** लिथियम कार्बोनेट का उपयोग बाइपोलर विकार के उपचार में किया जाता है।

एयरोस्पेस और रक्षा (Aerospace and defense):

- **हल्के धातु मिश्र (Lightweight metal alloys):** लिथियम का उपयोग हल्के, उच्च शक्ति के एल्यूमिनियम मिश्र में किया जाता है।

ग्रहणशील उत्पादन:

- **सिरेमिक और कांच उद्योग (Ceramics and glass industry):** लिथियम का उपयोग कांच और सिरेमिक के निर्माण में किया जाता है।

पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable energy):

- **सौर और पवन ऊर्जा भंडारण:** ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में लिथियम-आयन बैटरी का उपयोग महत्वपूर्ण है।

लिथियम का महत्व (Importance of Lithium)

इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रसार (Importance of Lithium):

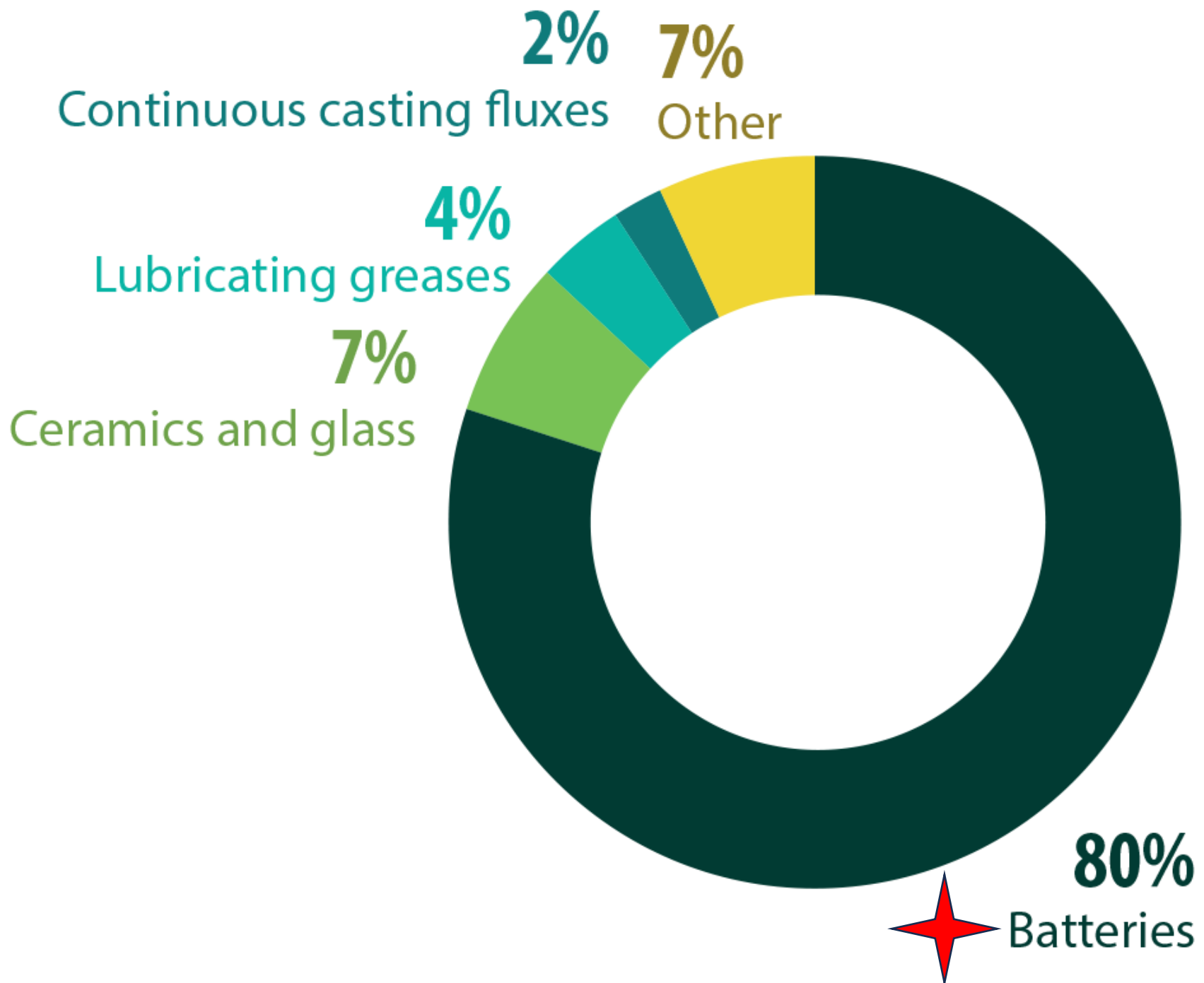
- **स्वच्छ ऊर्जा:** इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रसार पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता को कम करेगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी।

ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security):

- **आत्मनिर्भरता:** लिथियम भंडार का दोहन करने से भारत अपनी बैटरी आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भरता कम कर सकता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा।

आर्थिक विकास (Economic Growth):

- **नई उद्योगों का विकास:** लिथियम के दोहन से संबंधित उद्योगों का विकास, जैसे कि बैटरी निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में मदद करेगा।





India signs an agreement to acquire five lithium mines in Argentina

This is the first ever lithium exploration and mining project by a government company of India

Advertisement

Last Updated : Jan 16 2024 | 7:54 AM IST



The Centre on Monday signed an agreement to acquire five lithium brine blocks for exploration and development in Argentina. The agreement was signed between Khanij Bidesh India Ltd (KABIL) and Catamarca Minera Y Energética Sociedad Del Estado (CAMYEN), a state-owned mining and energy company in the Argentine province of Catamarca.

This is the first ever lithium exploration and mining project by a state-owned company. KABIL will start exploration and development of five lithium brine blocks — Cortadera-I, Cortadera-VII, Cortadera-VIII, Cateo-2022-01810132 and Cortadera-VI — covering an area of about 15,703 hectares in the Catamarca province.

The exploration and development agreement for five lithium blocks will aid India's objective to attain net-zero emissions by 2070 and establish itself as a manufacturing hub for electric vehicles.

Significance of Lithium for India

- India has pledged to reduce its emissions towards net-zero by 2070, requiring lithium as a critical component in EV batteries, and renewable energy storage systems.
- India needs 27 GW of grid-scale battery energy storage systems by 2030, requiring massive amounts of lithium.
- The World Economic Forum warns of global lithium shortages due to rising demand for EVs and rechargeable batteries, estimated to reach 2 billion by 2050. The world's lithium supply is under strain, with 54% of reserves in Argentina, Bolivia, and Chile.
- Lithium's role in green technologies and energy storage makes it a vital resource as countries aim to meet climate goals and transition to cleaner energy.
- India imports 70–80% of its lithium and 70% of its lithium-ion from China, which could put its growth and domestic industries at risk if tensions between the countries continue.

where does india import lithium from



All

News

Images

Books

Videos

Shopping

Maps

: More

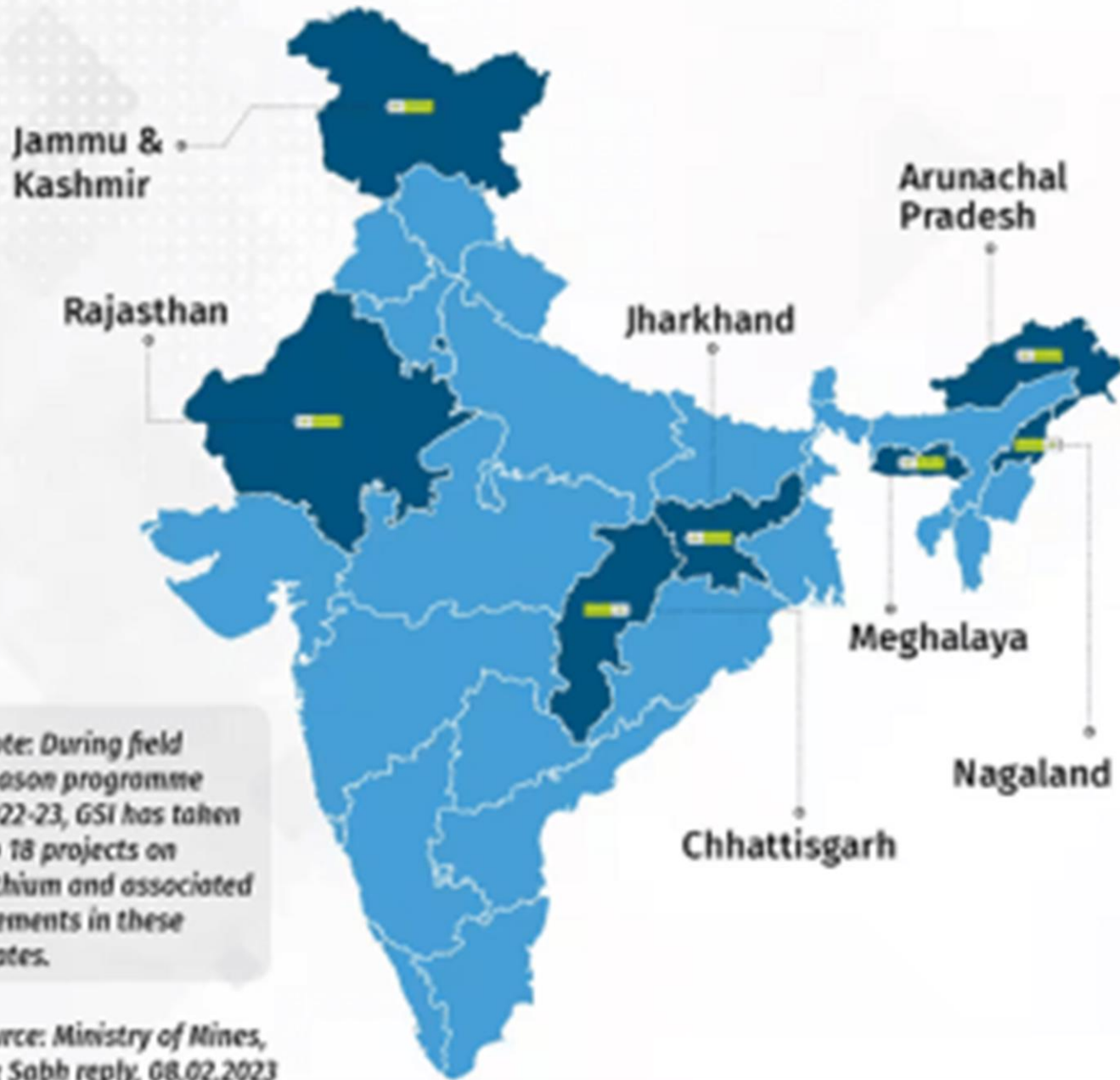
Tools

 हिन्दी में

 In English

India's lithium requirements are primarily met through imports. It is the world's largest processed lithium importer, with most of it coming from **Hong Kong and China**. India imported lithium worth more than 722.5 million USD during 2020-2021. 31 Jan 2024

IN LITHIUM SEARCH



Note: During field season programme 2022-23, GSI has taken up 18 projects on Lithium and associated elements in these states.

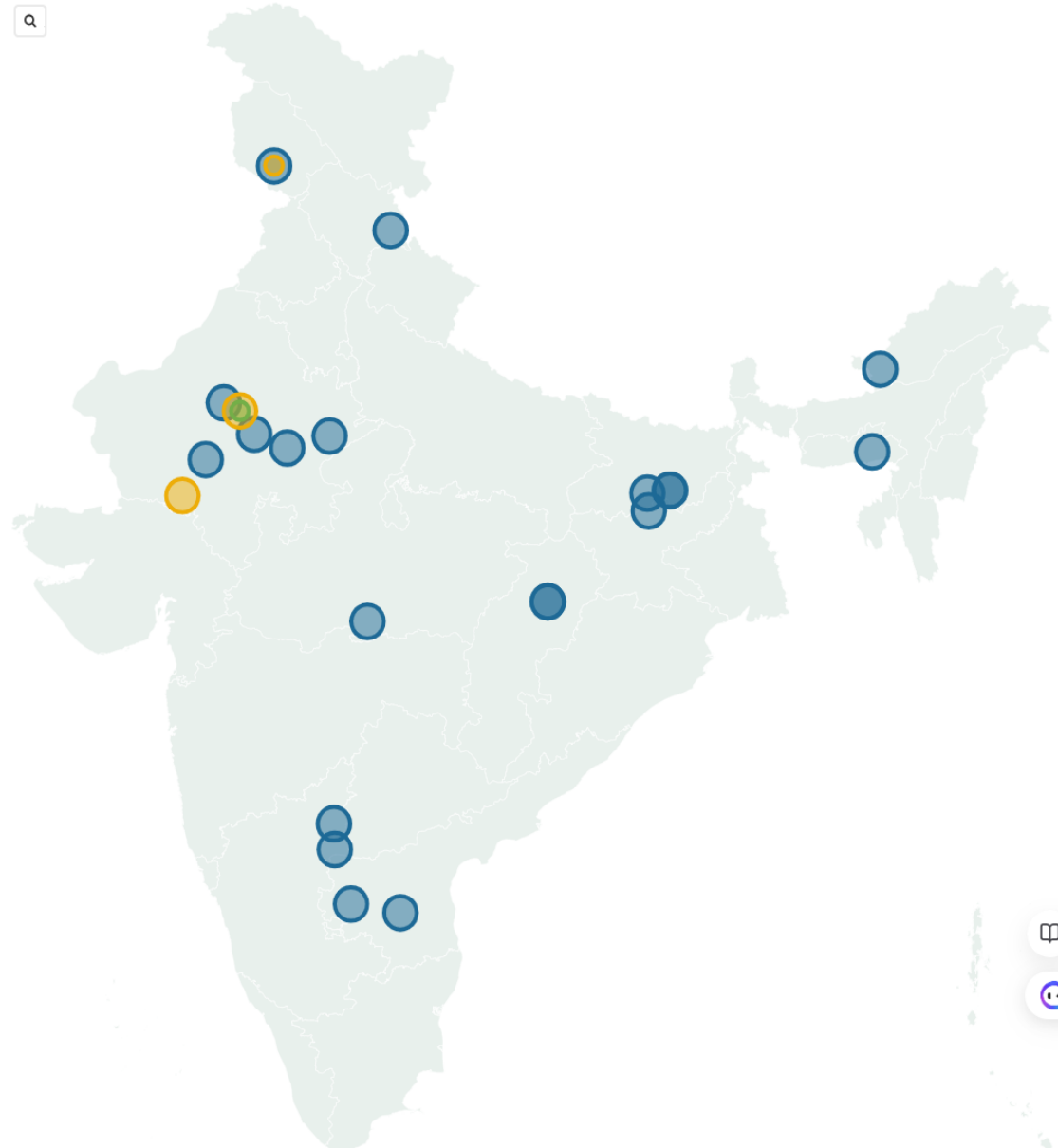
Source: Ministry of Mines, Lok Sabh reply, 08.02.2023

Lithium exploration

Between Field Season (FS) 2016-17 to FS 2021-22, the Geological Survey of India has explored 19 mineral blocks/belts for lithium. Of these, 15 are in the G4 stage, 3 in the G3 stage and one in the G2 stage as of March 2022.

**Locations approximate*

■ G4 ■ G3 ■ G2



Lithium Reserves in India:

1. Jammu and Kashmir:

Reserves: The primary lithium reserves in India are found in the Reasi district of Jammu and Kashmir.

Exploration Stage: Classified under G3 (preliminary exploration stage), indicating a low level of confidence in the quantity, grade, and mineral content estimates.

2. Rajasthan's:

Months after India's first lithium reserves, the GSI has found another reserve of the crucial mineral in **Degana in Rajasthan's Nagaur district.**

These reserves are believed to be much bigger in quantity (than found in J&K) and **can meet 80% of the total country's demand.**

What is the Status of Lithium Exploration in India?

Successful Auction in Chhattisgarh: India's first successful lithium auction took place in Korba district, Chhattisgarh. The block was auctioned to Maiki South Mining Pvt Ltd in June 2024.

Additional Findings in Korba (Chhattisgarh): A private exploration company funded by the National Mineral Exploration Trust (NMET) has identified hard rock lithium deposits in Korba, with concentrations ranging from 168 to 295 parts per million (ppm).

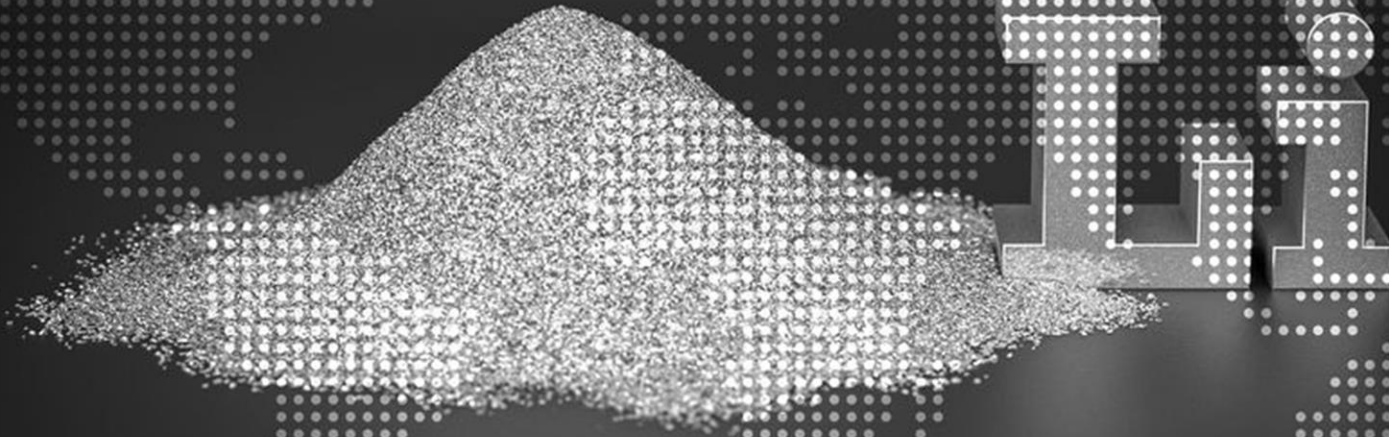
Challenges in Other States:

Manipur: Lithium exploration efforts in Kamjong district have been stalled due to local resistance. The NMET committee has decided to pause further actions in this area.

Ladakh: Exploration in the Merak block near the India-China border has yielded disappointing results, leading the NMET committee to suggest dropping the exploration efforts there.

Assam: Exploration in Dhubri and Kokrajhar districts has not been promising, with the NMET recommending against further upgrades or exploration in these areas.

Lithium Production & Reserves in World:












Lithium Reserves in World:

Major Producers:

- 1. Australia:** The largest producer of lithium, primarily through hard rock mining (spodumene).
- 2. Chile:** Holds significant lithium reserves in brine deposits in the Atacama Desert.
- 3. China:** Major producer with both hard rock and brine resources.
- 4. Argentina:** Another key player with extensive lithium brine resources in the Lithium Triangle.

Global Reserves:

- 1. Chile:** Has the largest lithium reserves, estimated at around 9.2 million tonnes.
- 2. Australia:** Holds approximately 4.8 million tonnes of lithium reserves.
- 3. Argentina:** Has about 3.6 million tonnes of reserves.
- 4. China:** Holds around 3 million tonnes of reserves.

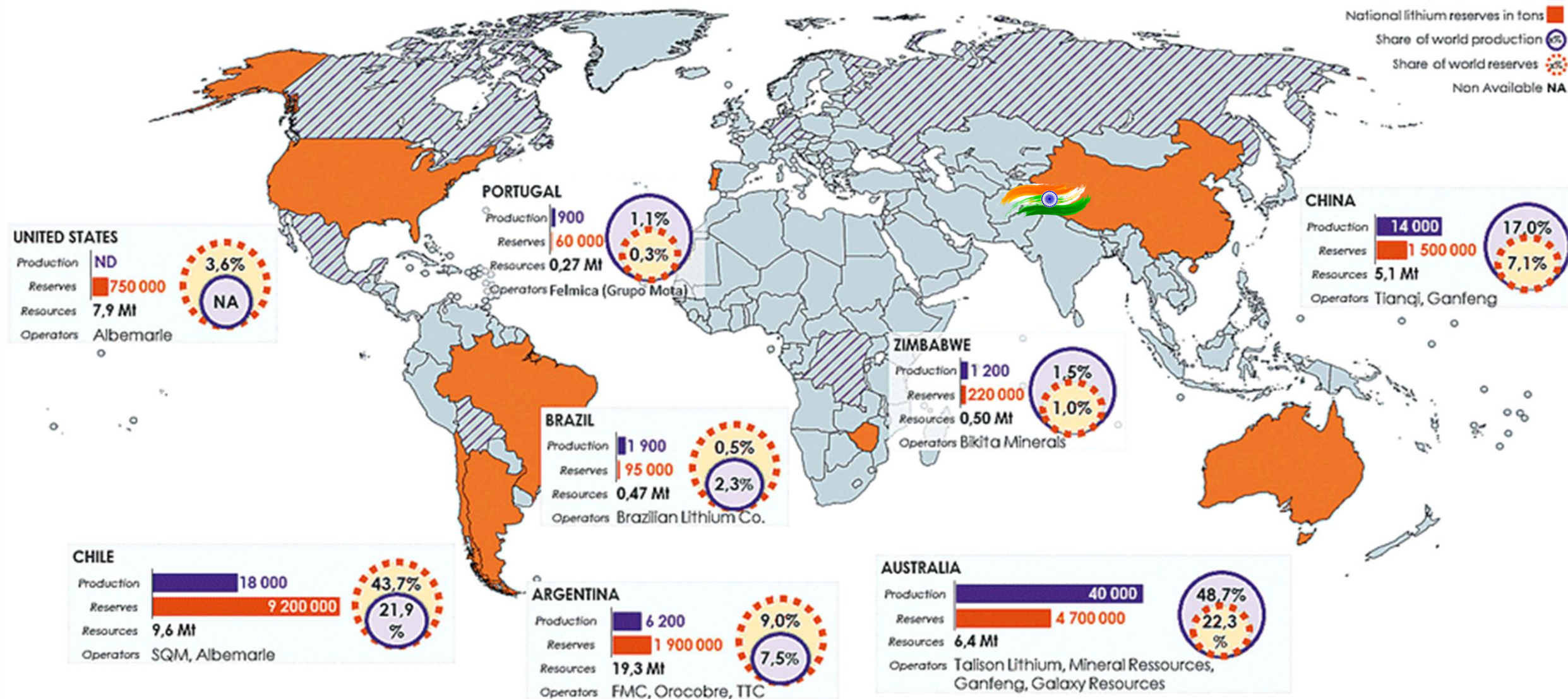
Rank	Country	Lithium <u>production</u> 2023E (metric tons)
1	 Australia	86,000
2	 Chile	44,000
3	 China	33,000
4	 Argentina	9,600
5	 Brazil	4,900
6	 Canada	3,400
7	 Zimbabwe	3,400
8	 Portugal	380
	 World Total	184,680



 Top 8 lithium producing countries

GLOBAL LITHIUM PRODUCTION AND RESERVES IN 2020 (t)

- The 8 lithium producers
- ▨ Non-producing countries with resources > 1 Mt
- Domestic lithium production in tons
- National lithium reserves in tons
- % Share of world production
- % Share of world reserves
- NA Non Available



What is the need and significance of the domestic production of Lithium for India?

1) Meeting Growing Lithium-ion Battery Demand:-India's lithium demand is projected to increase because more people will be using things like phones, renewable energy batteries, and electric cars in future. The demand for lithium in India is predicted to increase from 1,634 tonnes in 2022 to between 60,000 and 93,000 tonnes by 2050.

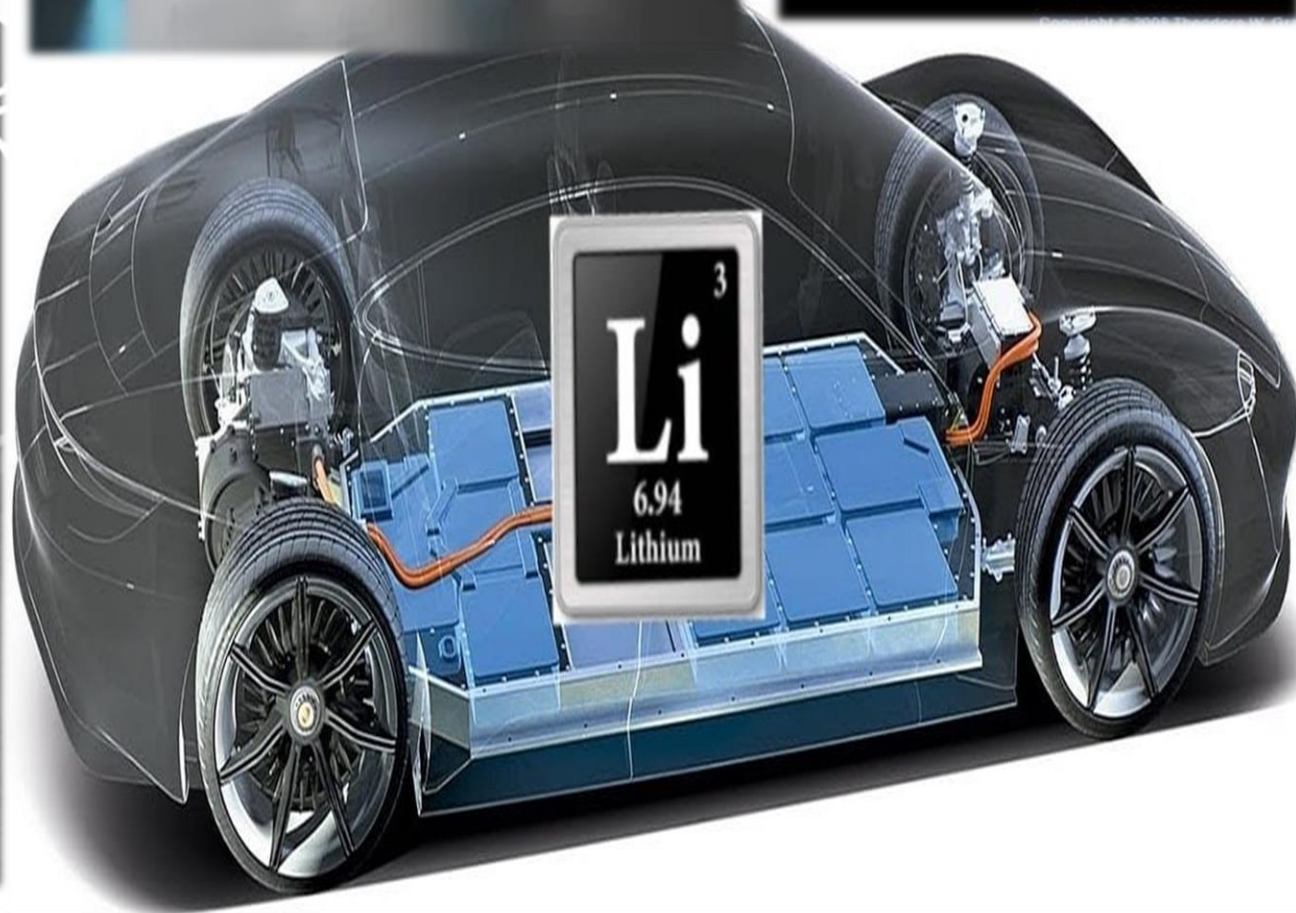
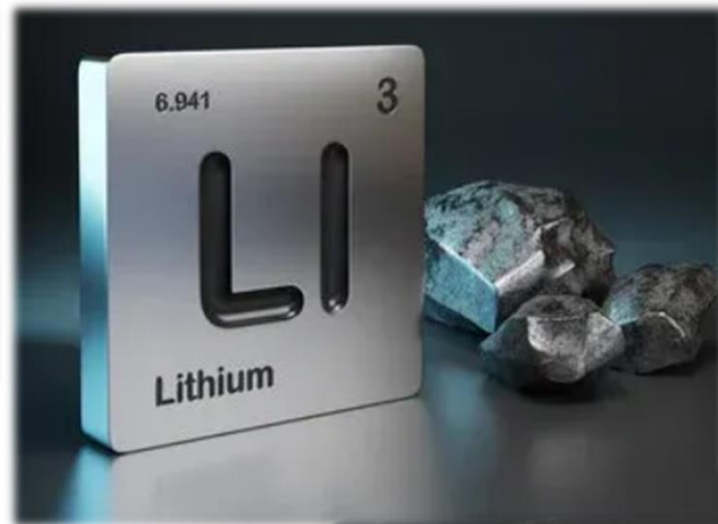
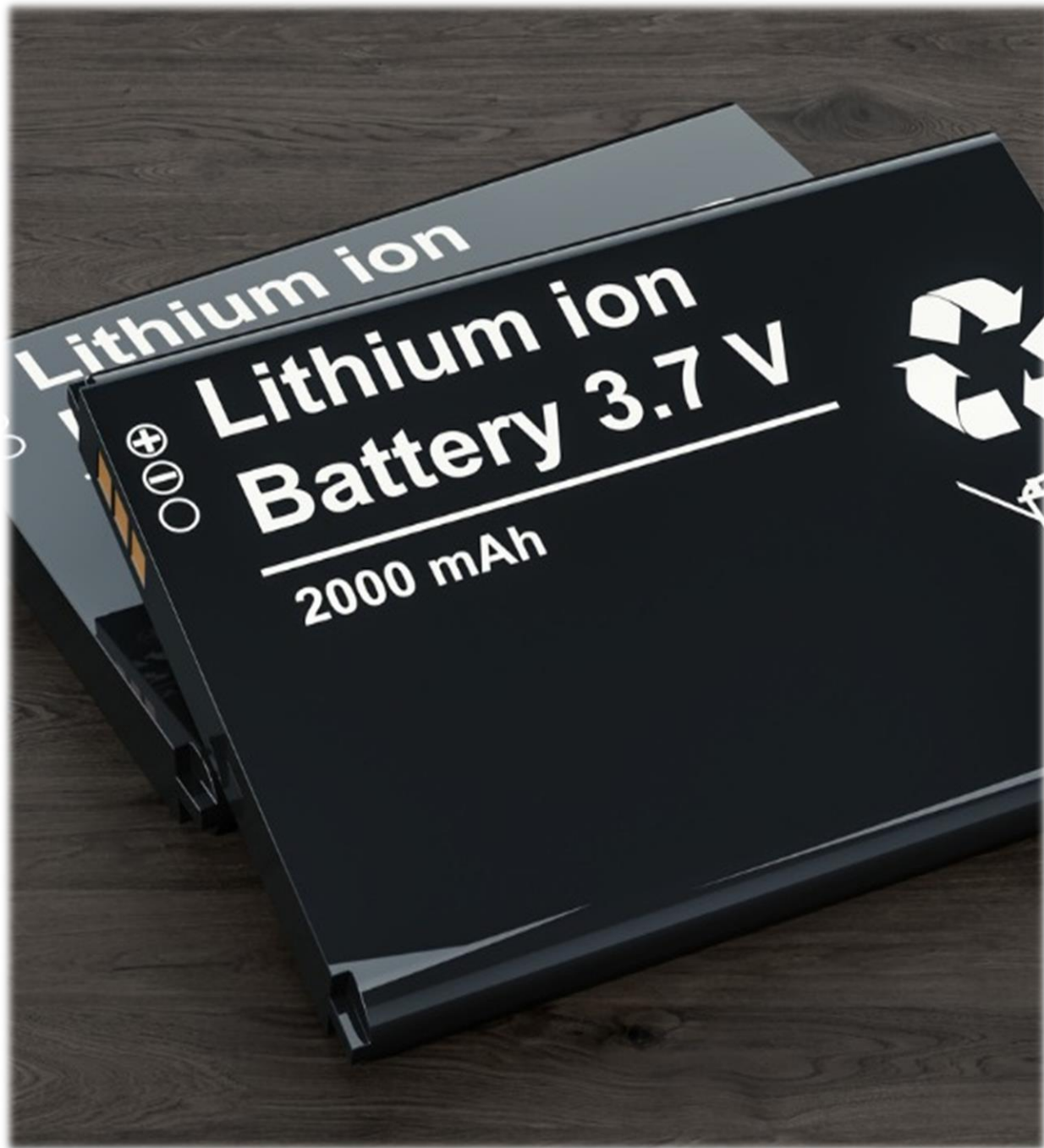
2) Reducing Import Dependence:-India currently has no lithium production and relies heavily on lithium-ion imports, which have surged from \$94 million in 2014-15 to nearly \$3 billion in 2023-24. For ex-India imports almost 70-80 per cent of its lithium and 70 per cent of its lithium-ion from China. Developing domestic lithium reserves could help reduce India's import dependence and associated costs.

3) Supporting Clean Energy Transition:- Lithium is important for lithium-ion batteries, which are key for storing energy from sources like solar and wind power. Access to lithium reserves can help India switch to cleaner energy and keep the power grid stable.

4) Enabling Electric Vehicle Adoption:- Ensuring a stable lithium supply can ensure the adoption of EVs in India and contribute to reducing greenhouse gas emissions from the transportation sector.

5) Strategic Importance- China has mines in the lithium triangle and has refining capacity for more than half of the world's lithium. China has previously exerted its dominance, such as in 2010 when it stopped Rare Earth Elements (REE) exports to Japan during a disagreement. This highlights the importance for India to boost its domestic production to reduce its dependence on China for lithium and other critical minerals.





What steps have been taken by the government to explore lithium reserves in India?

1) Geological Surveys: The Geological Survey of India (GSI) has been actively involved in conducting geological surveys and explorations to identify potential lithium reserves across different regions of the country.

2) Policy Reforms: The government has introduced policy reforms to encourage exploration and development of lithium and other critical minerals. In 2023, the Ministry of Mines made a list called 'Critical Minerals for India.' This list includes minerals that are crucial for the country's economic growth and national security. Lithium is considered a 'strategic' mineral because India relies entirely on imports for it. This puts lithium at the top of the priority list.

3) Protecting Mining Sector from Foreign Exploitation- **Indian government is committed to protect its mining sector from foreign exploitation by law.** According to the Mines and Minerals Act, only Indian individuals or firms with Indian members can get licenses for mining. **This prevents a situation seen in countries like Argentina or Chile, where foreign companies extract lithium, but the benefits mostly is not reaped by the producing country.**

4) Auctions and Licensing: The government has conducted auctions and issued licences for the exploration and extraction of lithium reserves. This includes offering lithium-bearing blocks for bidding to private companies and ensuring partnerships between government agencies and private sector players. For ex-In 2023, 20 blocks of critical and strategic minerals were auctioned to boost the mining process, including two lithium blocks in Jammu and Kashmir and Chhattisgarh.

5) International Collaboration: India has engaged in international collaboration and partnerships to leverage global expertise and technologies in the exploration and development of lithium reserves.

For ex-the Ministry of Mines, through the state-owned Khanij Bidesh India Ltd (KABIL), has entered into a draft exploration and development agreement with Argentinan miner CAMYEN for possible acquisition and development of five-odd lithium blocks.

6) Mineral Security Partnership- India has recently joined an important group called the Mineral Security Partnership (MSP), led by the United States. MSP consists of 13 countries, including Australia, Canada etc, The goal of MSP is to encourage both public and private investment in global supply chains for critical minerals.



What next?

In case the government decides to move ahead with further exploration of the Reasi block, before another auction attempt, new findings may provide more clarity to potential investors on the nature of resource present, which at present is only “inferred”.

Alternatively, the government can choose to skip the auction process and reserve the area for the undertaking of prospecting or mining operations through a government-owned company, as allowed under the Mines and Minerals (Development and Regulation) (MMDR) Act.





NCERT

**OFFER
FEE**



FOUNDATION BATCH

4999 Rs

REOPEN

**LIMITED OFFER
REGISTRATION START**

1. SUBJECTS TO BE TAUGHT (NCERTS FROM CLASS 6TH-12TH)
2. SUBJECTS: GEOGRAPHY, POLITY, HISTORY, INDIAN ECONOMY,
3. LIVE LECTURES DELIVERED IN HINGLISH LANGUAGE BY ANKIT AVASTHI SIR.
4. SPECIAL EMPHASIS ON CONCEPTUAL CLARITY IN CLASSES.
5. ALIGNMENT WITH UPSC AND STATE PSC PATTERN:
6. UNIT WISE WEEKLY TESTS THROUGH UNIQUE WORK BOOK STYLE

BY ANKIT AVASTHI SIR

FOR UPSC & VARIOUS STATE PSC EXAM

2024

GA FOUNDATION

RECORDED BATCH

Apni
Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Subject

HISTORY ,POLITY

GEOGRAPHY

ECONOMICS

Price

1499 /-

**Validity
1 Year**

By Ankit Avasthi Sir





LAUNCHING



BPSC

TEST SERIES

299/- ONE YEAR

- 50+ Mock Test
- 10+ Topic wise test
- 30+ PYQ's
- 65 + Current Affairs

Buy Now!

By Ankit Avasthi Sir





LAUNCHING



RO/ARO
TEST SERIES

299/- ONE
YEAR

- 30+ Mock Test
- 13+ Sectional test
- 8+ PYQ's
- 60 + Current Affairs

Buy Now!

By Ankit Avasthi Sir





UP POLICE बनने का सपना होगा साकार !

NEW

LAUNCHING



Test Series

UP POLICE EXAM



FEATURES

- ⇒ 20 Mock Test
- ⇒ 21 Sectional Test
- ⇒ 10 Practice Test
- ⇒ 25+ Topic Wise Test
- ⇒ 8+ PYQ's
- ⇒ 65+ Current Affairs Test

BUY NOW!

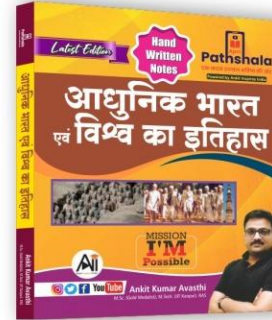
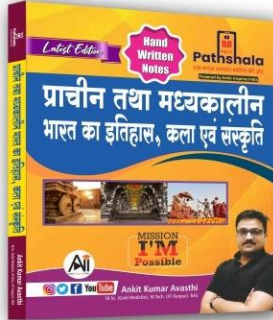
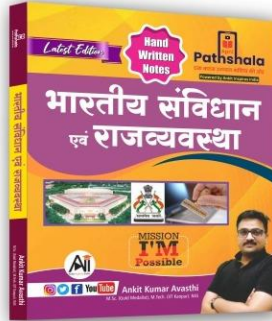
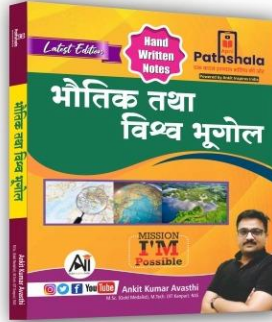
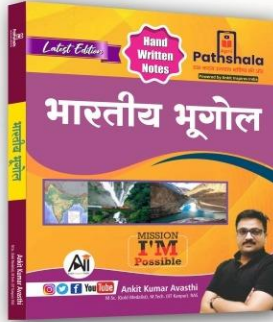
99/-

for ONE YEAR

By Ankit Avasthi Sir

GA FOUNDATION

Hand Written
Notes



₹ Only
1999

6 पुस्तकों
का
सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए
गए नंबर पर संपर्क करें....

 **7878158882**

- सिन्धु नदी का उद्गम किलाश पर्वतीय क्षेत्र में बीखर-सू हिमनद से होता है।
- तिब्बत में इस नदी को सिंगी खंबान कहते हैं।
- यह फमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है।
- यह नदी भारत में लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी के बीच बहती है।
- पाकिस्तान में यह अटक (Attock) नामक स्थानों पर मैदानों में प्रवेश करती है।
- पाकिस्तान में कराँची के पास डेल्टा बनते हुए यह अरब सागर में गिरती है।
- सिन्धु नदी की दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदियाँ :- श्योक, रुद्रा, हुनजा, गिलागिट, स्वात, काबुल तथा गोमल
- इसकी प्रमुख बायें हाथ की सहायक नदियाँ झेलम, पिनाब, रावी, व्यास, सतलज, द्रास तथा जास्कर पंचनद
- सिन्धु से पंचनद पाक में मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है।
- 'लेट' सिन्धु नदी के किनारे स्थित है।

पंचनद

i) झेलम :- इस नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में

- बेरिनाग झील से होता है।
- * यह नदी बल्लर झील का निर्माण करती है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
- इस नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है।
- किशनगंगा इसकी दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदी है।
- इस नदी पर तुलबुल परियोजना प्रस्तावित है। यह एक नवविद्यन परियोजना है।
- यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है।

ii) पिनाब :- पिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बारालच्छा दर्रे के पास चन्द्र तथा भागा नदियों के मिलने (Confluence) से होता है।

- 1962 में इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ स्थित हैं।

उदाहरण :- तुलहस्ती, सलाब, बगलिहार

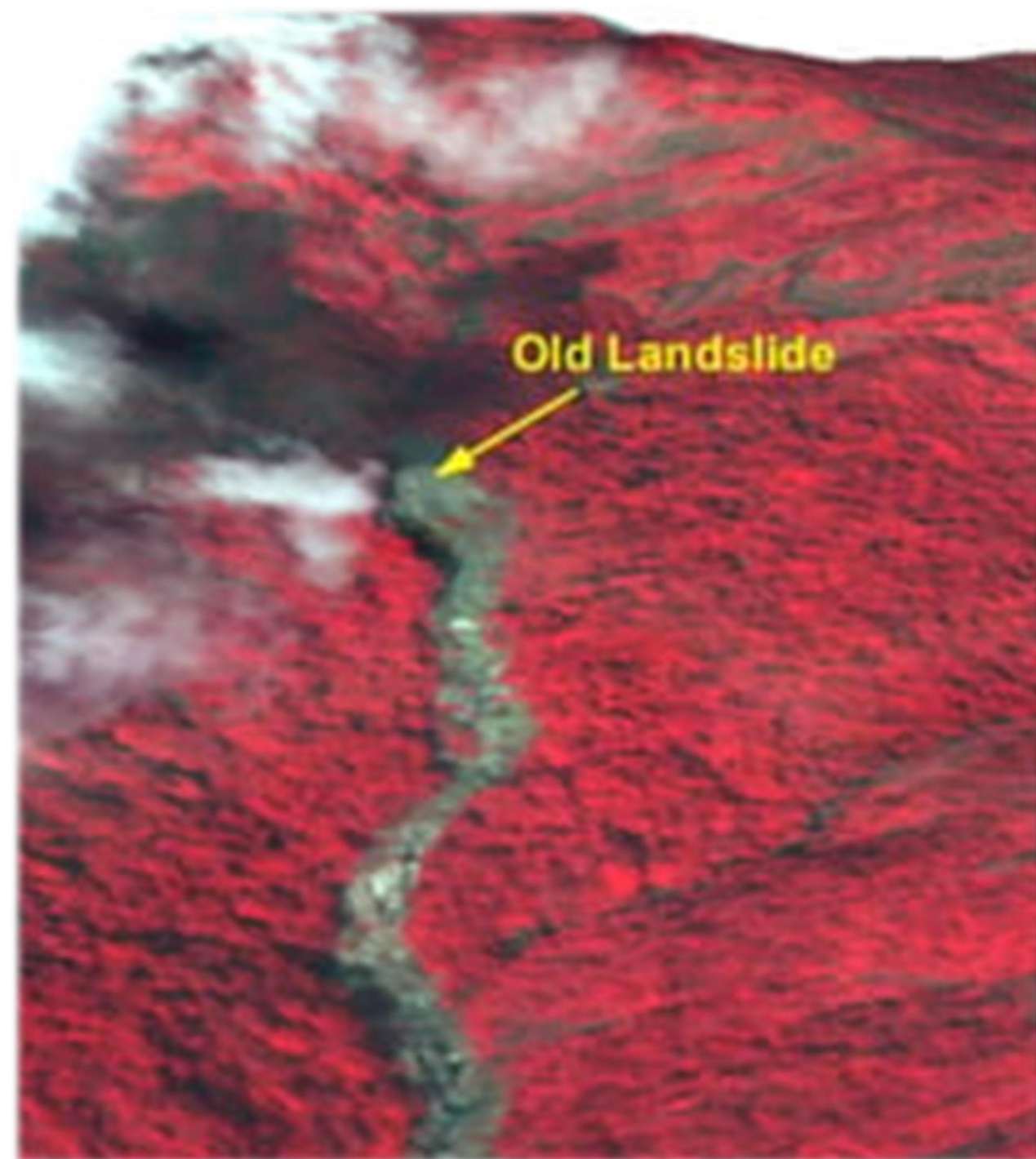
- यह सिन्धु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।

iii) रावी :- रावी नदी का उद्गम शैलांग दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में होता है।

- हिमाचल प्रदेश में इन नदी पर चमेरा बाँध स्थित है।
- पंजाब में इस नदी पर धीन परियोजना स्थित है।

₹ 1999








☰ Top stories ⋮

Massive landslides in Wayanad, Kerala >


1



 India Today

Wayanad landslides toll rises to 289 as massive rescue ops continue in Kerala ✓

19 hours ago

 Onmanorama

Wayanad landslides: 296 dead, volunteers temporarily halt search op | Kerala...




6 hours ago

 The Hindu

Wayanad Landslides Highlights: Rahul Gandhi visits Kerala; CMO puts...

5 hours ago



 NDTV

"We Haven't Even Reached...": Kerala Governor's Grim Warning...

8 hours ago



 Times of India

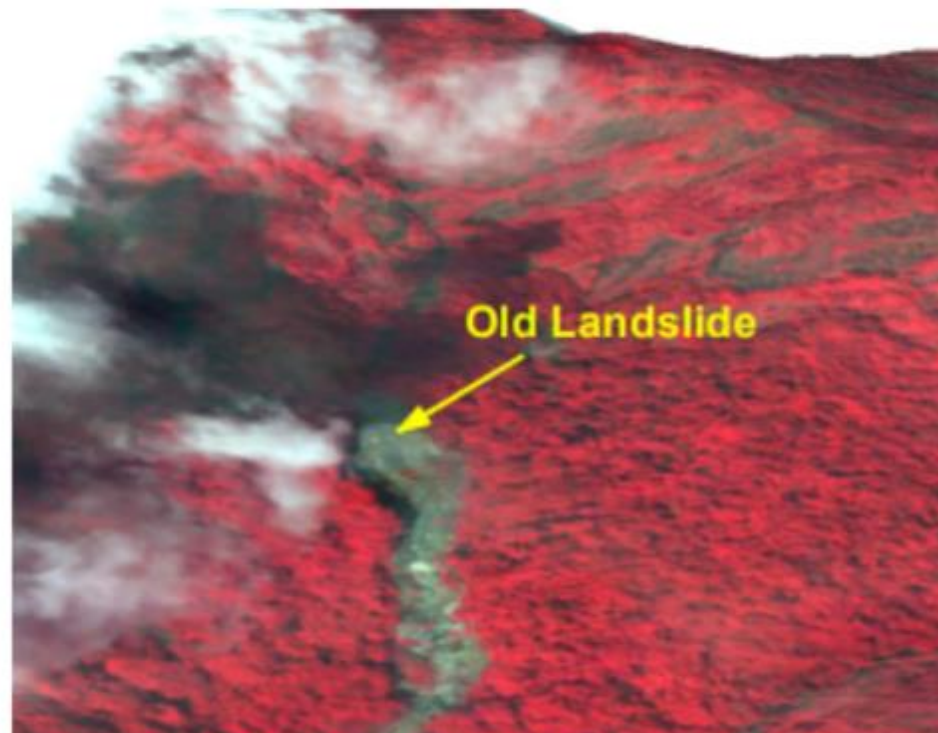
No site visit or statement without permission: Kerala government's gag order fo...

5 hours ago



ISRO releases images before and after Wayanad landslides

According to NRSC, a major debris flow was triggered by heavy rainfall in and around the Chooralmala town and very high resolution satellite images taken on July 31, 2024, shows that the length of the landslide flow was approximately 8 kms.



Top stories

2

The Hindu

[Disaster Management Bill 2024: Centre Set to Introduce New Amendments in Lok Sabha](#) ✓

15 hours ago



BS Business Standard

[Govt introduces bill in Lok Sabha to amend disaster management law](#) ✓

8 hours ago



ET The Economic Times

[Govt seeks to amend disaster management act, aims to strengthen efficient working of authorities](#) ✓

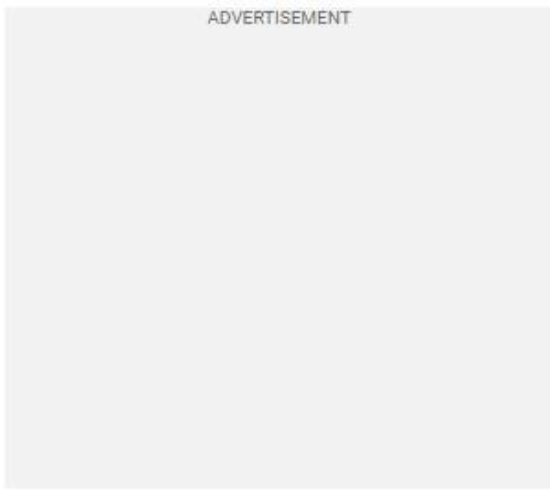
9 hours ago



Wayanad landslides: PM Modi announces Rs 2 lakh compensation for deceased's kin; Rahul Gandhi urges UDF workers to assist rescue ops

Massive landslides struck the hilly areas near Meppadi in Kerala's Wayanad district on Tuesday morning.

By: **Express Web Desk**
New Delhi | Updated: July 30, 2024 12:24 IST



Wayanad Landslide: Death Toll Rises To 291, 200 Still Missing; Rahul, Priyanka Gandhi Reach Ground Zero | Top Updates

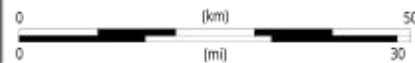
• Curated By: [Shobhit Gupta](#) • [News18.com](#) • Last Updated: AUGUST 01, 2024, 19:30 IST • Wayanad, India



Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi with AICC General Secretary Priyanka Gandhi Vadra visits a relief camp for people affected by the landslides, at Meppadi in Wayanad district. (Image: PTI)

The massive landslides which struck Wayanad on Tuesday claimed the lives of at least 173 people and left hundreds injured.

• Follow us: [Whatsapp](#) [Facebook](#) [Twitter](#)
[Telegram](#) [Google News](#)





Landslide alert

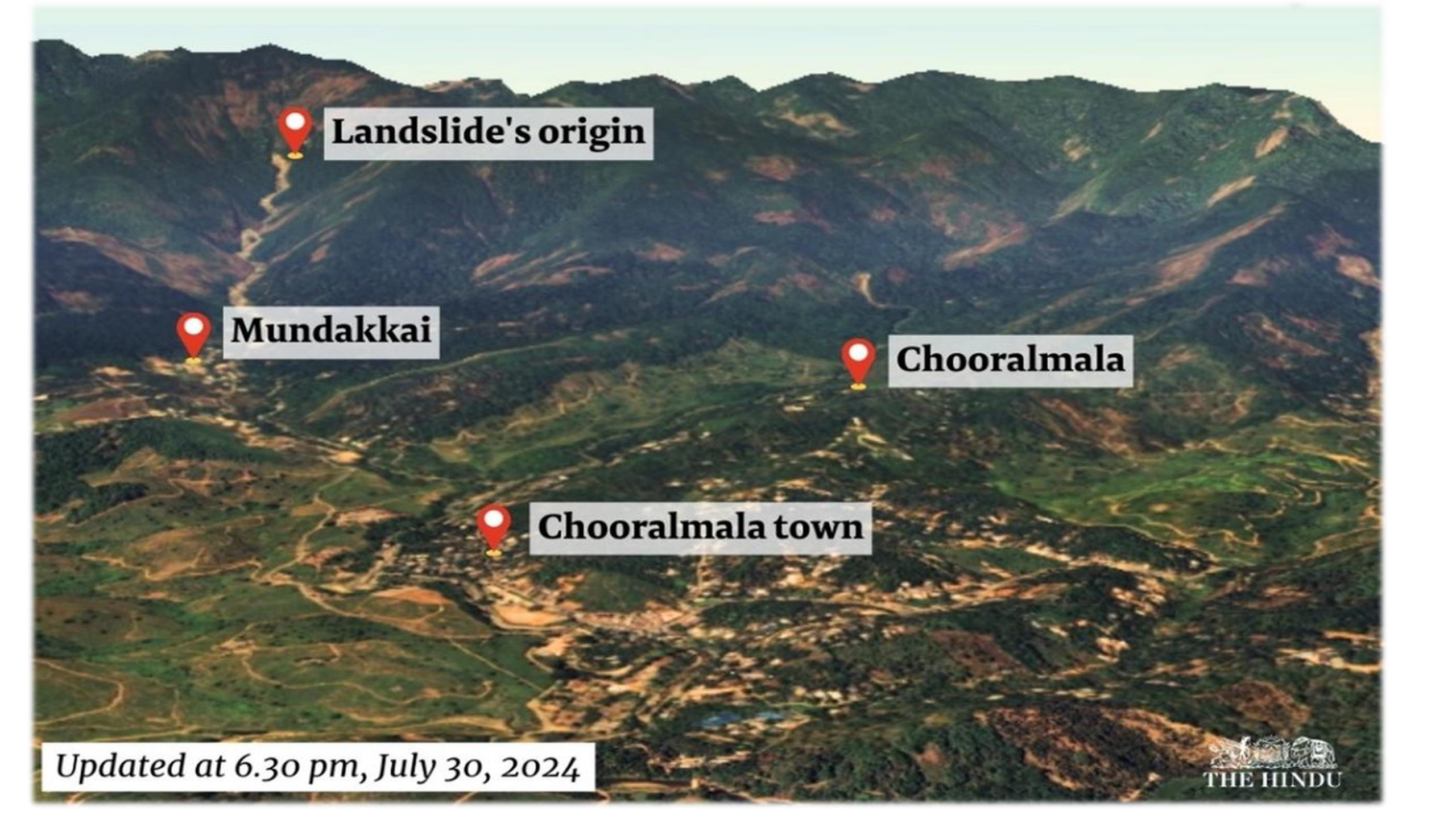
Wayanad landslides

Kerala, India







An aerial photograph of a mountainous region, likely in the Western Ghats of India. The terrain is rugged, with steep slopes and deep valleys. Several paths of brown earth, indicating landslides, are visible on the slopes. Four red location pins are placed on the image, each with a corresponding text label in a grey box. The labels are: 'Landslide's origin' (top left), 'Mundakkai' (middle left), 'Chooralmala' (middle right), and 'Chooralmala town' (bottom center). The sky is clear and blue.

Landslide's origin

Mundakkai

Chooralmala

Chooralmala town

Updated at 6.30 pm, July 30, 2024

केरल के वायनाड जिले में लगातार भारी बारिश के कारण भयानक भूस्खलन हुआ है। इस आपदा में अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं और कई अभी भी फंसे हुए हैं। भूस्खलन के बाद वायनाड में पूरे के पूरे चार गांव साफ हो गये हैं।

भारी बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कीचड़, चट्टानों और पेड़ों के बड़े-बड़े टुकड़ों, टूटी सड़कों, और टूटे पुल की वजह से रेस्क्यू करने में बचावकर्मियों को काफी परेशानी हो रही है। इस भूस्खलन ने घरों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं कई नदियां उफान पर हैं। लापता लोगों को खोजने और बचाने के लिए सभी संभव संसाधनों के साथ अभियान जारी है।





वायनाड में भूस्खलन के बाद बचाव अभियान पर भारतीय सेना ने बताया कि भारतीय सेना, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान चला रही है। मुदक्कई गांव से करीब 300 लोगों को बचाया गया है, उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को कहा कि वायनाड के भूस्खलन प्रभावित मुदक्कई क्षेत्र में बचाव अभियान में कुछ और दिन लग सकते हैं, तथा उन्होंने बचाव प्रयासों के समन्वय के लिए चार मंत्रियों की एक कैबिनेट उप-समिति नियुक्त की।



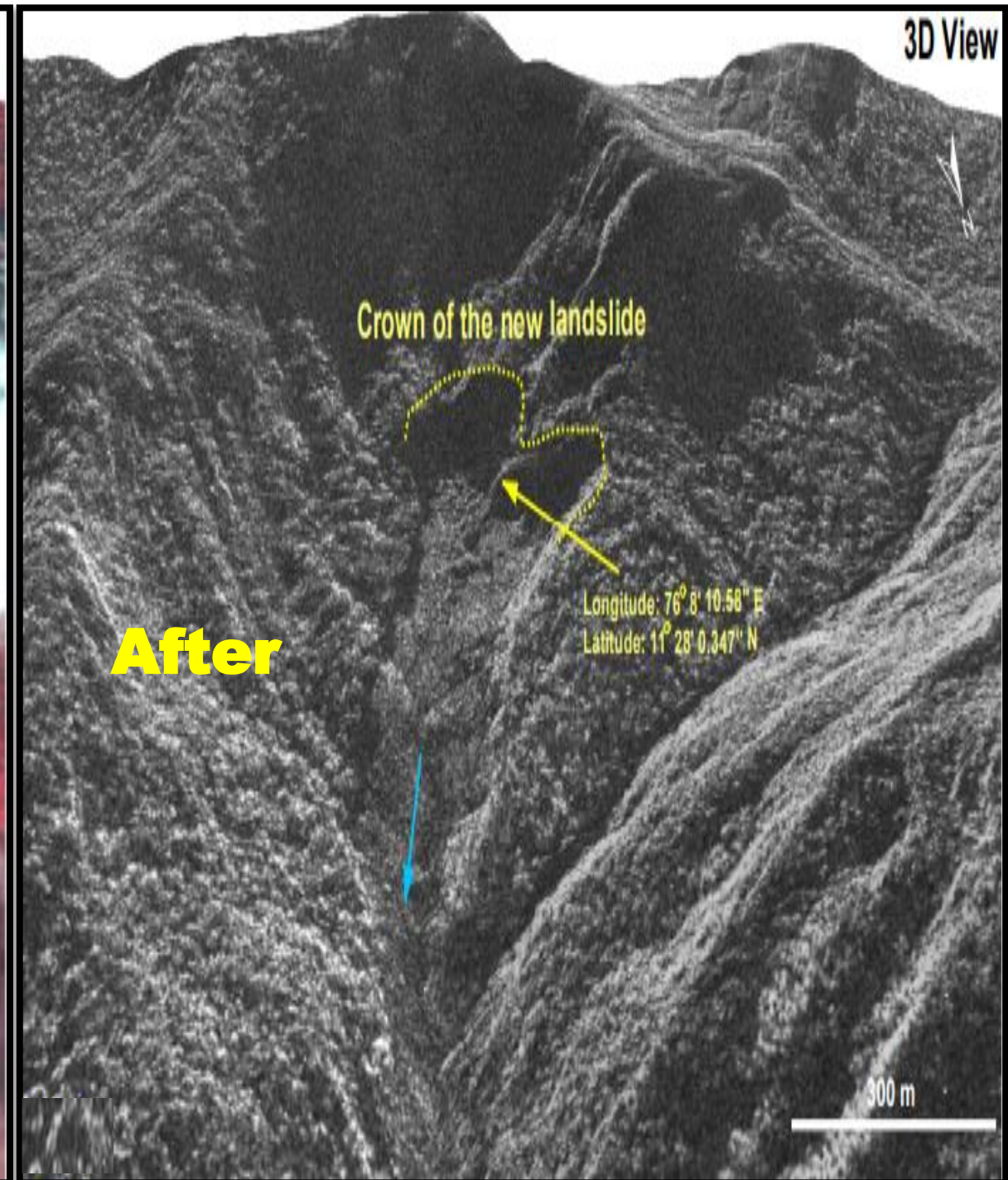
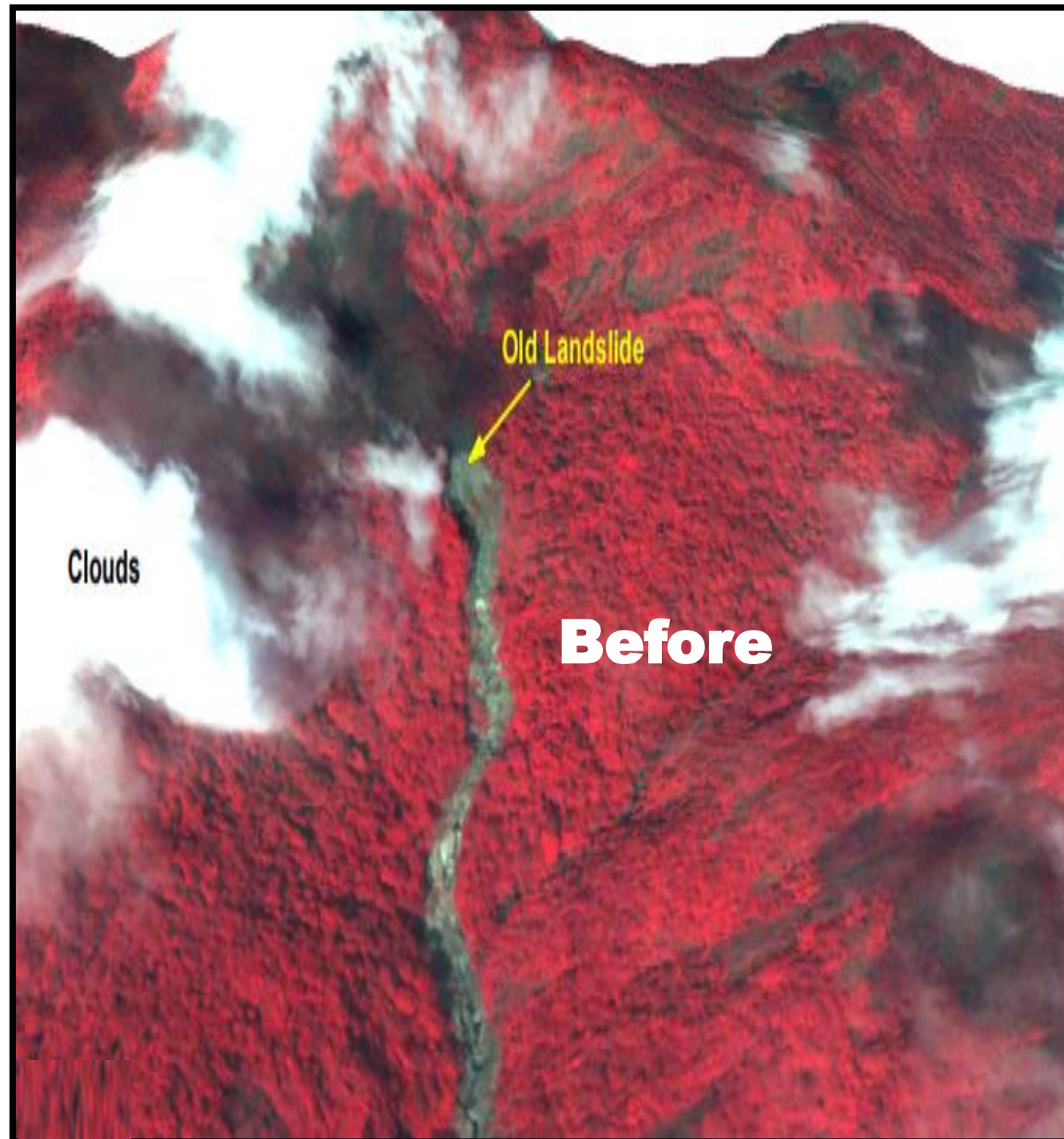


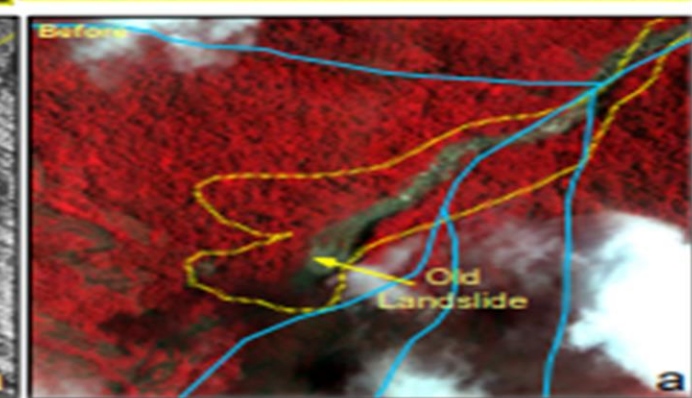
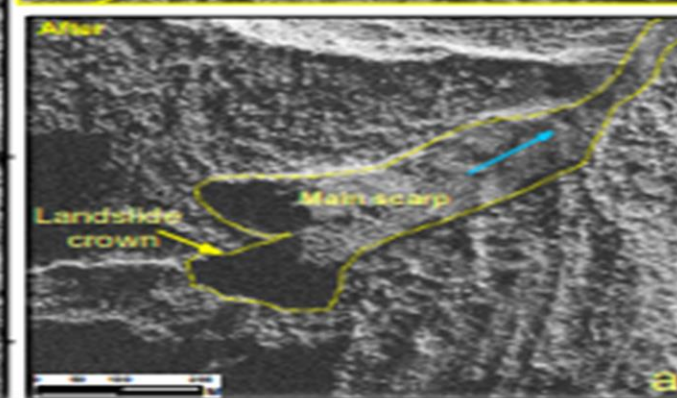
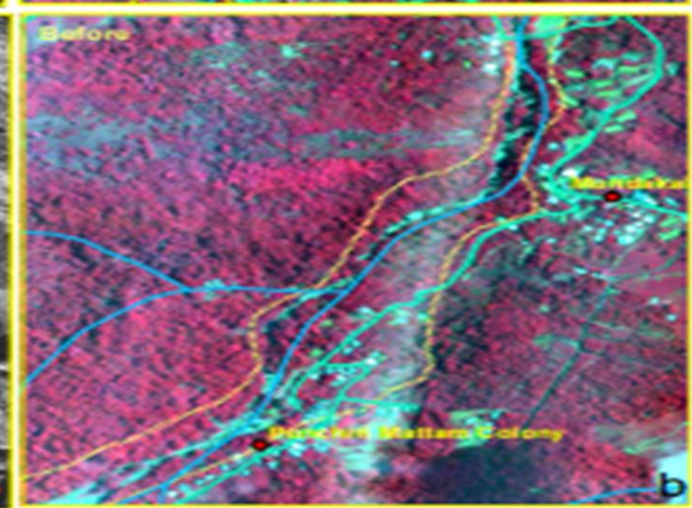
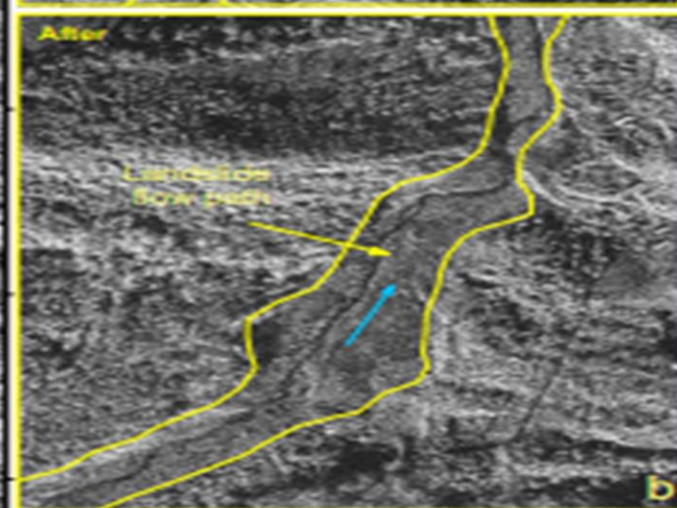
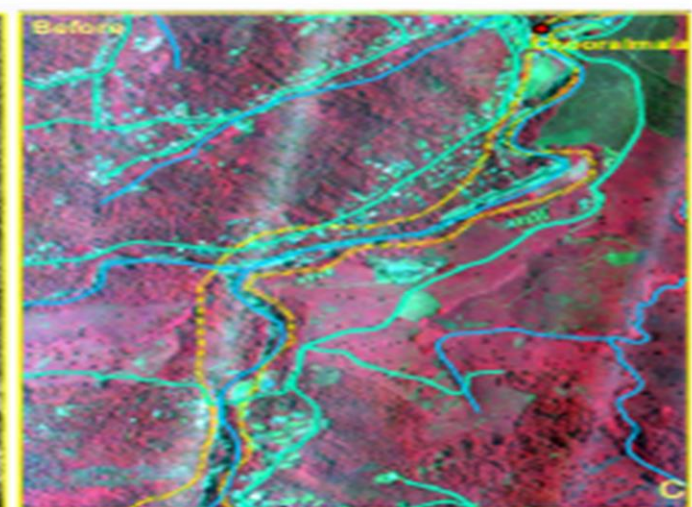
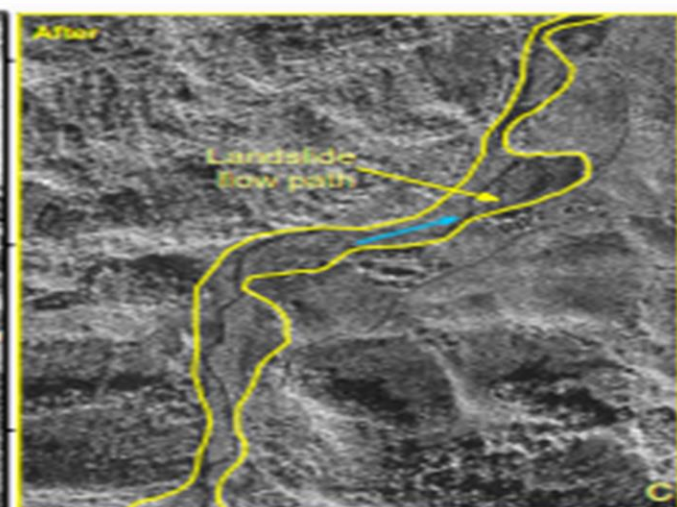
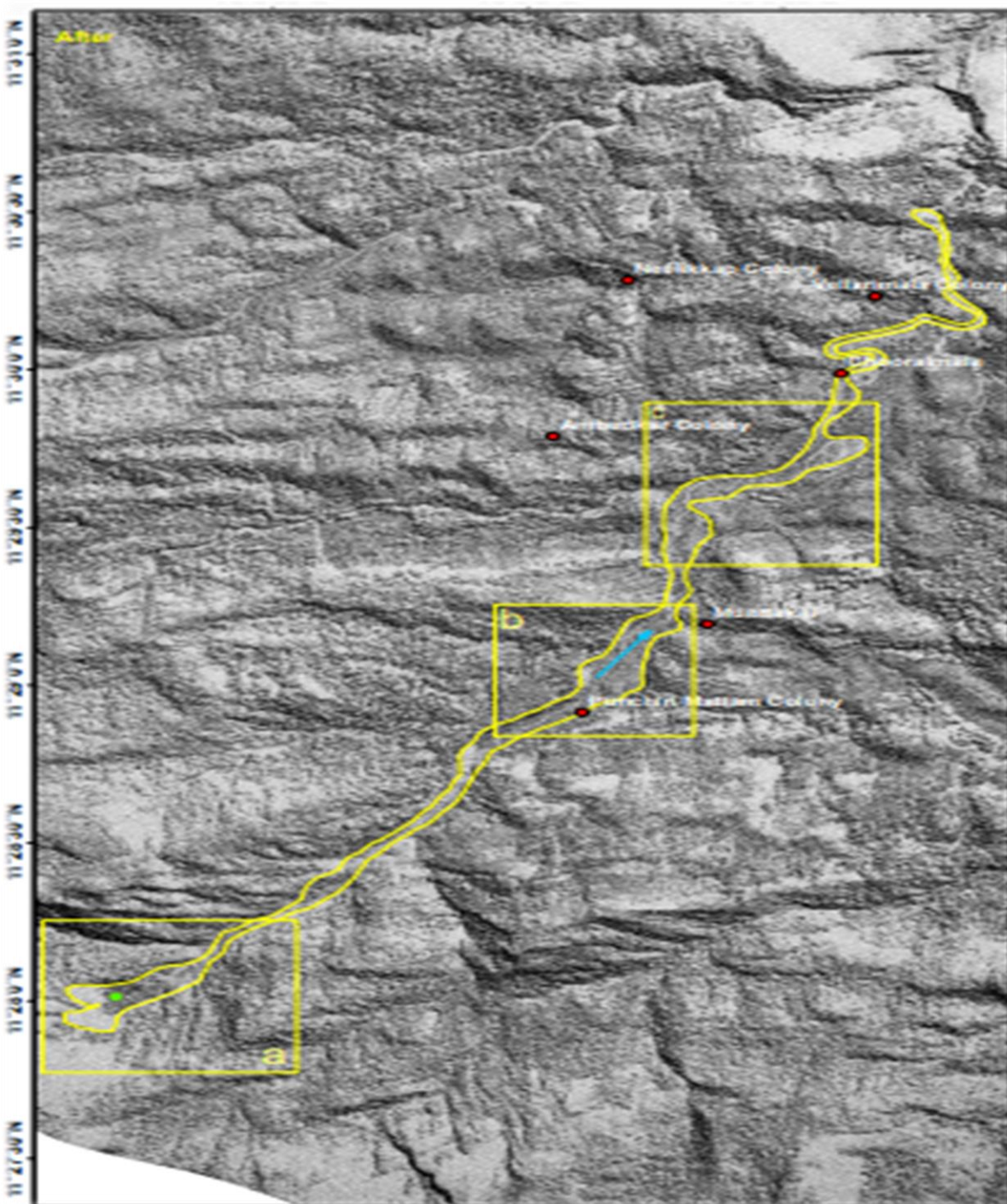
Wayanad Landslide: ISRO's satellite imagery reveals severe destruction, death toll at 293

Last Updated: Aug 01, 2024, 11:31:00 PM IST

 FOLLOW US  SHARE  FONT SIZE !







ISRO Releases Satellite Images Of Large-Scale Destruction :

Two days after the massive landslides that hit the hilly town of Wayanad in Kerala which claimed over 250 lives, the Indian Space Research Organisation (ISRO) released satellite images of the extensive damage caused in the region.

The National Remote Sensing Center (NRSC) in Hyderabad flew ISRO's advanced Cartosat-3 optical satellite and the RISAT satellite to capture the extent of the devastation brought by the landslides in Wayanad.

Triggered by heavy rainfall, the landslide originated at an altitude of 1,550 meters. According to the NRSC report, the landslide was exacerbated by a major debris flow initiated by torrential rains in and around Chooralmala town. The area extent of the landslide is 86,000 square meters.





Narendra Modi ✓

@narendramodi

...

Distressed by the landslides in parts of Wayanad. My thoughts are with all those who have lost their loved ones and prayers with those injured.

Rescue ops are currently underway to assist all those affected. Spoke to Kerala CM Shri [@pinarayivijayan](#) and also assured all possible help from the Centre in the wake of the prevailing situation there.

Last edited 8:48 AM · Jul 30, 2024 · 1.7M Views

1.2K

4.1K

25K

116



Wayanad landslides: PM Modi announces compensation; Rahul Gandhi speaks to Kerala CM, says, 'deeply anguished...'

Wayanad landslide: Early on Tuesday, massive landslides occurred in various hilly areas near Meppadi in Kerala's Wayanad district. Nineteen deaths have been reported and several people were injured. Hundreds of people are feared trapped.

Written By Fareha Naaz

Updated • 30 Jul 2024, 09:34 AM IST

Up to 10 Lakhs



- Prime Minister Narendra Modi has spoken to Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan and assured all help to the LDF government.

- The Prime Minister's Office has announced compensation of ₹ 2 lakh for the families of those killed in the calamity. Those injured would be given ₹ 50,000.



ANI

@ANI · Follow



Wayanad landslide | Kerala CM Pinarayi Vijayan says "Most important is giving psychological support to the survivors. We have to avoid the spread of the epidemic. Not only human beings, but many animals also died in the calamity. Have to bury them all properly. A committee of... [Show more](#)



1:20 PM · Aug 1, 2024



32



Reply



Share

[Read 9 replies](#)

VIDEO



ANI

@ANI · Follow



[#WATCH](#) | Wayanad Landslide | Kerala CM Pinarayi Vijayan travelling to Wayanad from Kozhikode. The chief secretary Dr V Venu and DGP, Shaik Darvesh Sahib are accompanying him

(Source - CMO)





☰ Top stories :

News about Bill • Disaster



TH The Hindu

Disaster Management Bill 2024: Centre Set to Introduce New Amendments in Lok...

14 hours ago

mp MillenniumPost

Govt introduces Bill to amend disaster management law ✓

26 minutes ago



BS Business Standard

Govt introduces bill in Lok Sabha to amend disaster management law ✓

7 hours ago



Govt. introduces Disaster Management (Amendment) Bill, 2024 in Lok Sabha

The Bill seeks to create a “disaster database at national and State level,” and makes provision for constitution of “Urban Disaster Management Authority” for State capitals and large cities having municipal corporations

Updated - August 01, 2024 11:53 pm IST **Published** - August 01, 2024 11:05 am IST - New Delhi



Govt. introduces Disaster Management (Amendment)

Bill, 2024 in Lok Sabha:

On Wednesday, while responding to the Kerala Wayanad landslide case in the Lok Sabha, Union Home Minister Amit Shah had said that the government is bringing the Disaster Management Bill in this session. The very next day it was introduced in the House.

The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024, introduced in Lok Sabha on Thursday, aims to strengthen the efficient working of the national and state disaster management authorities besides bringing more clarity and convergence among stakeholders working in the field of disaster management.

क्या है विधेयक में-

- राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाने का प्रावधान।
- राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्चस्तरीय समिति जैसे संगठनों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाएगा।
- राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति के बजाय राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने के लिए अधिकारियों को सशक्त बनाना।
- राज्य की राजधानियों और नगर निगमों वाले बड़े शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान।
- राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का प्रावधान।
- आपदा प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए जरूरी संस्थागत तंत्र निर्माण।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 (NDMA):

स्थापना: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की स्थापना 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत की गई थी।

मुख्य उद्देश्य: आपदाओं के प्रभाव को कम करना और उनके प्रबंधन में सुधार लाना।

अध्यक्ष: प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।

कार्य: राष्ट्रीय आपदा नीति का निर्माण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) की रणनीतियों का विकास, आपदा प्रबंधन योजनाओं का निरीक्षण और समन्वय, और आपदा प्रतिक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का निर्माण।

कार्यक्रम और परियोजनाएं: विभिन्न आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाएं, आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) का प्रबंधन, और समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन कार्यक्रम।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA):

स्थापना: प्रत्येक राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की स्थापना की गई है।

मुख्य उद्देश्य: राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन की देखरेख और समन्वय।

अध्यक्ष: राज्य के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।

कार्य: राज्य की आपदा नीति का निर्माण, राज्य स्तर की आपदा योजनाओं का विकास और कार्यान्वयन, आपदा प्रतिक्रिया के लिए राज्य स्तर पर मानक संचालन प्रक्रियाओं का निर्माण।

कार्यक्रम और परियोजनाएं: राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) का प्रबंधन, राज्य स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाओं का संचालन, और राज्य के जिलों में आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।



Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi visited Wayanad, Kerala:

Congress leader and former Wayanad MP Rahul Gandhi and his sister Priyanka Gandhi Vadra visited the landslide-affected area of Chooralmala here and a hospital and community health centre in Meppadi on Thursday afternoon.

After reaching Chooralmala, Gandhi and his sister -- donning translucent blue raincoats -- crossed the temporary wooden walkway built there, took a look at the construction of the Bailey bridge and walked around the area braving the rain and muddy terrain.

Thereafter, they headed to Dr Moopen's Medical College and the Community Health Centre in Meppadi where the bodies of the victims were kept in refrigerator coffins. Gandhi and Vadra interacted with the grieving families there.



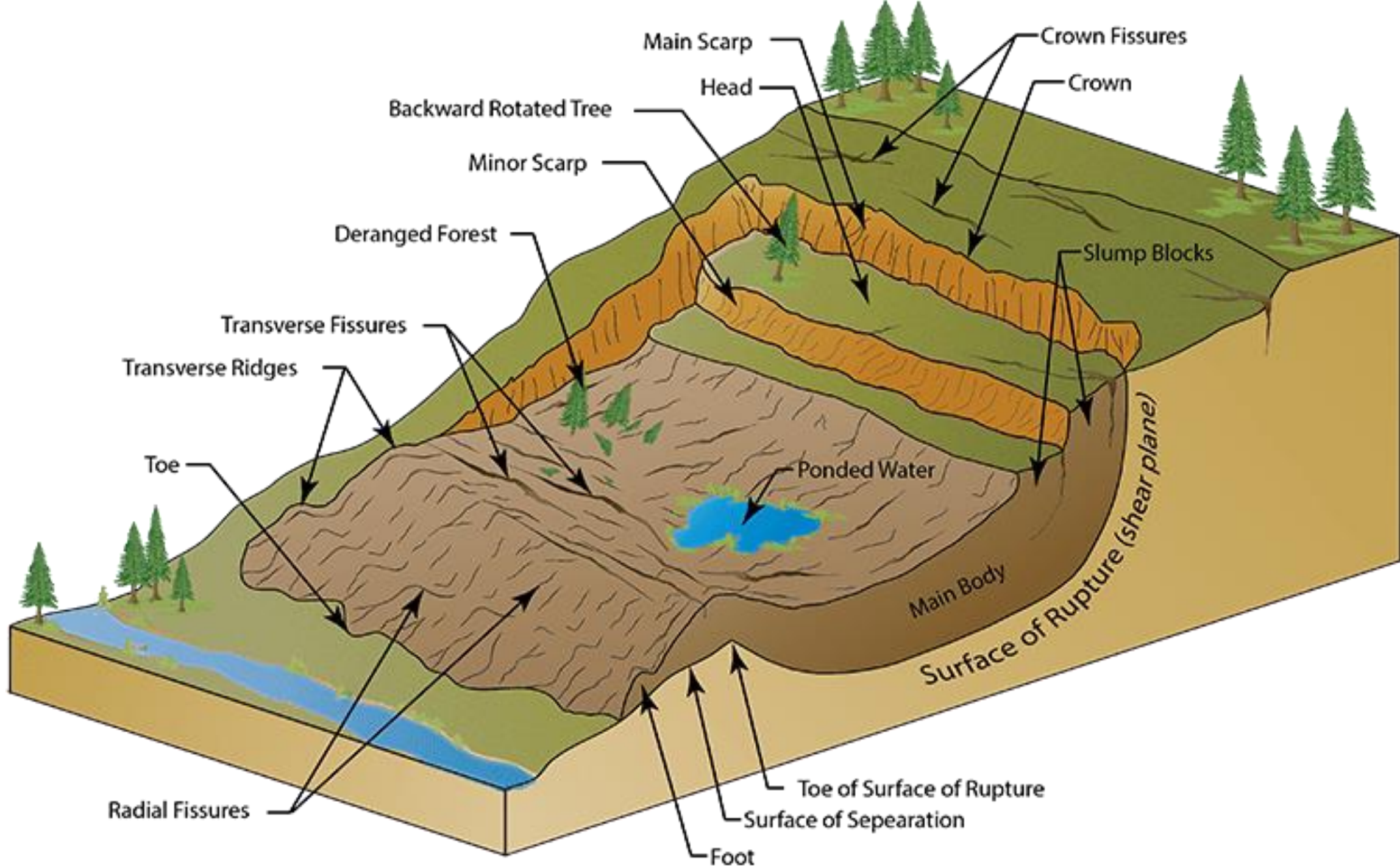
What is Landslides





Landslide:

Landslide is rapid movement of rock, soil and vegetation down the slope under the influence of gravity. These materials may move downwards by falling, toppling, sliding, spreading or flowing. Such movements may occur gradually, but sudden sliding can also occur without warning. **They often take place in conjunction with earthquakes, floods and volcanic eruptions.** The extent and Intensity of landslide depends upon number of factors- Steepness of the slope, amount of vegetation cover, tectonic activity, bedding plane of the rocks etc.

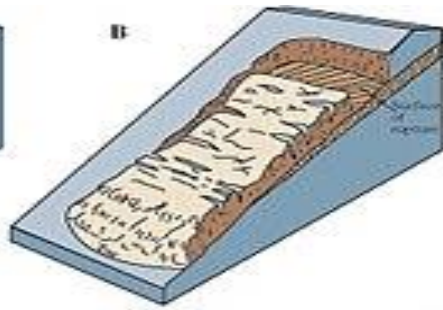




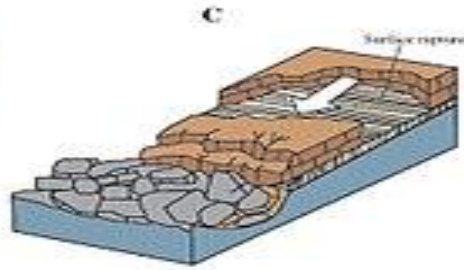
TYPES OF LANDSLIDE



Rotational landslide



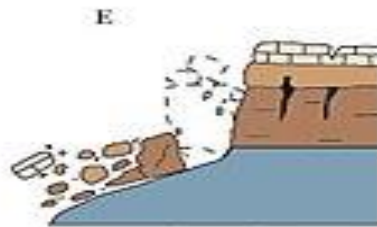
Translational landslide



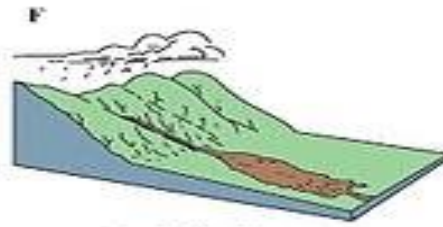
Block slide



Rockfall



Topple



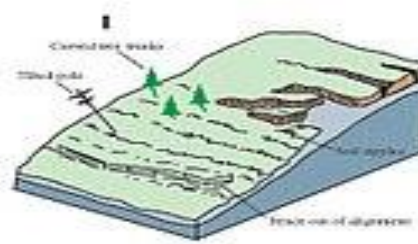
Debris flow



Debris avalanche



Earthflow



Creep



Lateral spread

Types of Landslides:

- 1. Falls:** Abrupt movements of materials that become detached from steep slopes or cliffs, moving by free-fall, bouncing, and rolling.
- 2. Creep:** Slow, steady downslope movement of soil or rock
- 3. Debris flow:** Rapid mass movement in which loose soils, rocks, and organic matter combine with water to form slurry that then flows down slope. Usually associated with steep gullies
- 4. Mudflow:** Rapidly flowing mass of wet material that contains at least 50% sand-, silt-, and clay-sized particles

5. Flows: General term including many types of mass movement, such as creep, debris flow, mudflow etc.

6. Volcanic activity or Lahars : Lahars are specific types of mudflows that are triggered by volcanic activity. They result from the mixing of volcanic ash, debris, and water, forming a fast-moving slurry that can travel long distances from the volcano's source. Lahars pose a significant threat to communities located near active volcanoes.

7. Rotational Slides: Also known as slumps, rotational slides involve the downward and outward movement of a mass along a curved failure plane. These landslides typically occur in cohesive materials, such as clay or silt, where the failure plane is curved due to the rotational movement.

8. Translational Slides: Translational slides occur when a mass moves along a planar failure surface parallel to the slope. They often happen in areas with weak or saturated soils, such as clay or silt, where the failure plane is relatively flat.



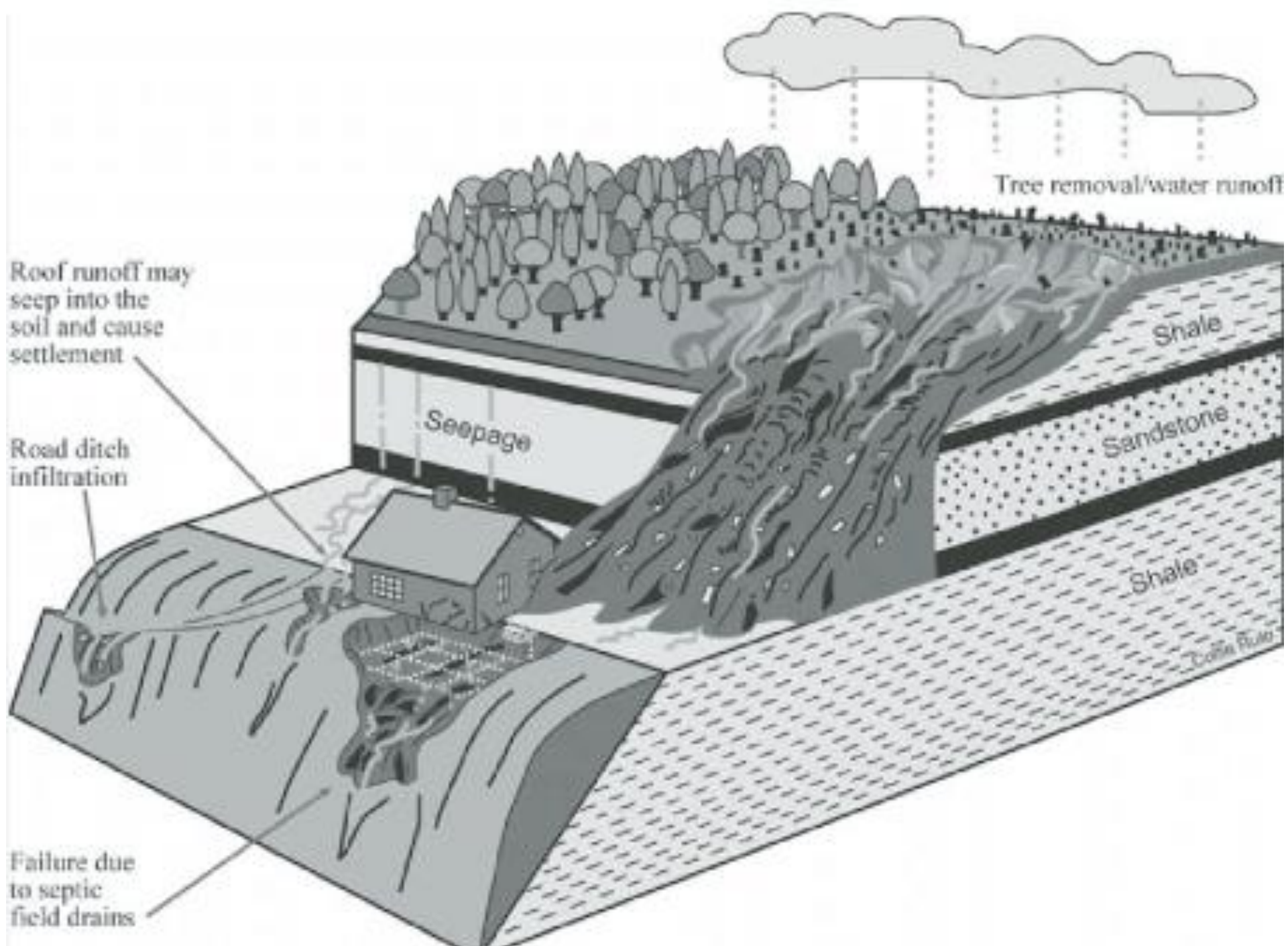
Causes of Landslides

1. Heavy Rainfall – Heavy rainfall is one of the most common triggers of landslides. It increases pore water pressure as well as the weight of soil by making it saturated.

2. Erosion – Clay and vegetation present within the soil or rock act as cohesive elements and help bind particles together. By removing these cohesive elements, erosion makes an area more prone to landslides.

3. Earthquakes – intense ground shaking due to earthquakes causes instability in rocks and soils, thus triggering landslides.

4. Volcanic Eruptions – Ash and debris deposited by volcanic eruptions overload slopes while the accompanied seismic activity causes instability. All these, together, trigger landslides.



Tree removal/water runoff

Roof runoff may seep into the soil and cause settlement

Road ditch infiltration

Failure due to septic field drains

Seepage

Shale

Sandstone

Shale

Coffin Road



Impacts of Landslides

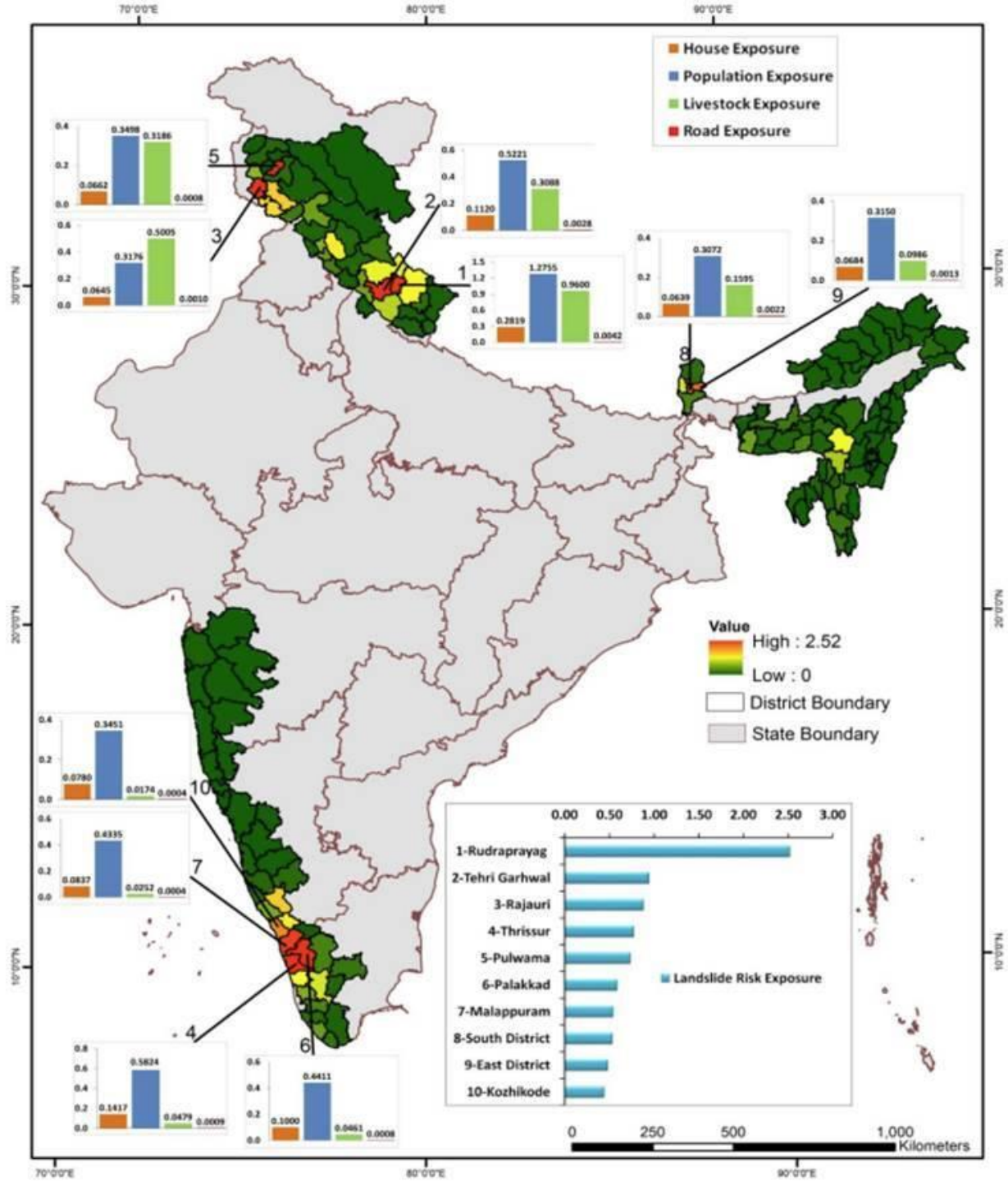
- **Loss of human and animal lives.**
- **Damage to infrastructure and properties such as homes, roads, etc.**
- **They can bury or wash away agricultural land, thus affecting agriculture.**
- **The aftermath of landslides may mean the displacement of local communities.**
- **Landslides, often, block transportation routes such as roads. This, then, has its own repercussions.**
- **The movement of huge mass during landslides can alter the natural landscape of a region. This, in turn, affects the ecosystem, water courses, etc.**



What Are the Landslide Prone States in India?

Some landslide prone states in India are as follows-

Landslide Prone Areas	States & Cities
Western Himalaya	Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh, Uttarakhand
Eastern & North-Eastern Himalaya	West Bengal, Arunachal Pradesh, Sikkim
Naga-Arakan Mountain belts	Tripura, Nagaland, Mizoram, Manipur
Western Ghat region & Nilgiri	Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Goa
Meghalaya Plateau comprising Peninsular India	The north-eastern part of India



NDMA guidelines on Landslides

1. Prevention and Preparedness (रोकथाम और तैयारी)

- **Hazard Mapping (जोखिम मानचित्रण):** संभावित भूस्खलन क्षेत्रों की पहचान और मानचित्रण किया जाना चाहिए।
- **Early Warning Systems (प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली):** भूस्खलन की घटनाओं की पूर्व चेतावनी देने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- **Public Awareness (जन जागरूकता):** स्थानीय समुदायों को भूस्खलन के खतरों और उससे बचाव के उपायों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।
- **Infrastructure Planning (बुनियादी ढांचा योजना):** सड़कों, भवनों और अन्य निर्माण कार्यों की योजना बनाते समय भूस्खलन जोखिमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

2. Mitigation Measures (निवारक उपाय)

- **Afforestation (वनरोपण):** अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाए जाएं ताकि मिट्टी का कटाव रोका जा सके।
- **Drainage Management (जल निकासी प्रबंधन):** पहाड़ी क्षेत्रों में उचित जल निकासी व्यवस्था बनाई जाए ताकि पानी के जमाव से बचा जा सके।
- **Slope Stabilization (ढलान स्थिरीकरण):** ढलानों को स्थिर करने के लिए रिटेनिंग वॉल्स और अन्य संरचनात्मक उपाय किए जाएं।
- **Regular Monitoring (नियमित निगरानी):** भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की नियमित निगरानी की जाए ताकि किसी भी असामान्य गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सके।

3. Response (प्रतिक्रिया)

- **Emergency Response Teams (आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमें):** भूस्खलन के समय त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए विशेष प्रशिक्षित टीमें बनाई जाएं।
- **Evacuation Plans (निकासी योजनाएं):** भूस्खलन के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए निकासी योजनाएं तैयार की जाएं।
- **Communication Systems (संचार प्रणाली):** आपातकालीन स्थिति में प्रभावी संचार के लिए रेडियो, मोबाइल, सैटेलाइट फोन आदि की व्यवस्था की जाए।

4. Rehabilitation and Reconstruction (पुनर्वास और पुनर्निर्माण)

- **Relocation of Affected Communities** (प्रभावित समुदायों का पुनर्वास): भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वासित किया जाए।
- **Infrastructure Rehabilitation** (बुनियादी ढांचे का पुनर्वास): भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़कों, भवनों और अन्य संरचनाओं का पुनर्निर्माण किया जाए।
- **Livelihood Support** (आजीविका समर्थन): प्रभावित लोगों की आजीविका पुनः स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाए।

5. Training and Capacity Building (प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण)

- **Skill Development** (कौशल विकास): स्थानीय समुदायों और आपदा प्रबंधन कर्मियों को भूस्खलन प्रबंधन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाए।
- **Mock Drills** (मॉक ड्रिल्स): भूस्खलन के समय की प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल्स आयोजित की जाएं।







NCERT

LIMITED OFFER
REGISTRATION START



FOUNDATION BATCH

2

OFFER
FEE

4999 Rs

शुरू होने जा रही है
WORLD MAPPING

(1-10 August)

FOR UPSC & VARIOUS STATE PSC EXAM

BY ANKIT AVASTHI SIR





NCERT

**OFFER
FEE**



FOUNDATION BATCH

4999 Rs

REOPEN

**LIMITED OFFER
REGISTRATION START**

1. SUBJECTS TO BE TAUGHT (NCERTS FROM CLASS 6TH-12TH)
2. SUBJECTS: GEOGRAPHY, POLITY, HISTORY, INDIAN ECONOMY,
3. LIVE LECTURES DELIVERED IN HINGLISH LANGUAGE BY ANKIT AVASTHI SIR.
4. SPECIAL EMPHASIS ON CONCEPTUAL CLARITY IN CLASSES.
5. ALIGNMENT WITH UPSC AND STATE PSC PATTERN:
6. UNIT WISE WEEKLY TESTS THROUGH UNIQUE WORK BOOK STYLE

BY ANKIT AVASTHI SIR

FOR UPSC & VARIOUS STATE PSC EXAM

2024

GA FOUNDATION

RECORDED BATCH

Apni
Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Subject

HISTORY ,POLITY

GEOGRAPHY

ECONOMICS

Price

1499 /-

**Validity
1 Year**

By Ankit Avasthi Sir





UPPSC RO ARO



सत्यमेव जयते

**Bihar Public Service
Commission**



LAUNCHING



BIHAR PSC
TEST SERIES

299/- ONE
YEAR



475 POST

By Ankit Avasthi Sir





BIHAR PSC
TEST SERIES

299/- ONE
YEAR

Why ?

- Exam-centric Robust Quality Content
- Increase Selection Chances by 16X
- Performance Analysis with State & All India Rank
- Most Relevant Exam Questions



By Ankit Avasthi Sir



BIHAR PSC
TEST SERIES

299/- ONE
YEAR

Features

- **50+ Mock Test**
- **10+ Topic wise test**
- **30+ PYQ's**
- **65 + Current Affairs**



By Ankit Avasthi Sir

₹ PRICE



BIHAR PSC
TEST SERIES

Buy Now!

299/-
One Year

By Ankit Avasthi Sir



HOW TO BUY

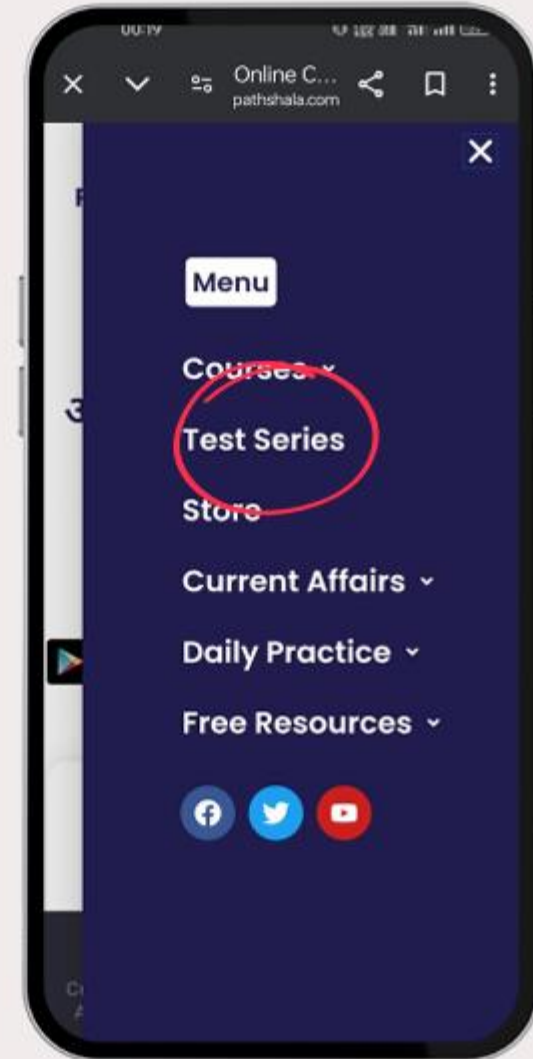
Step 1

Open the website
apnipathshala.com



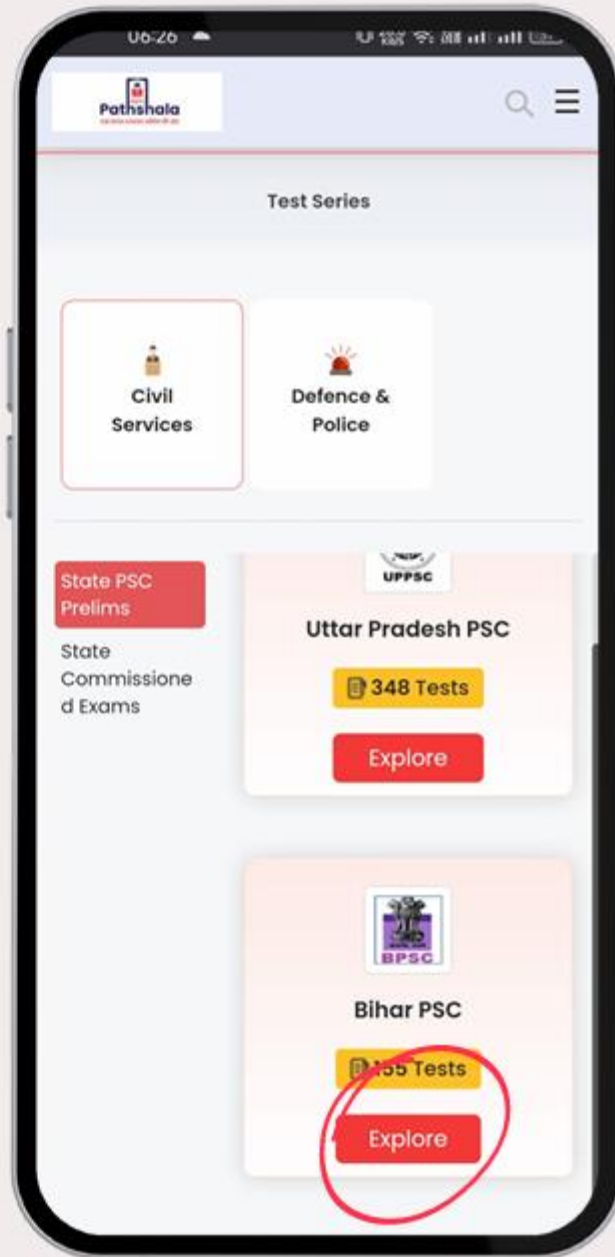
Step 2

Click on
Navigation Bar



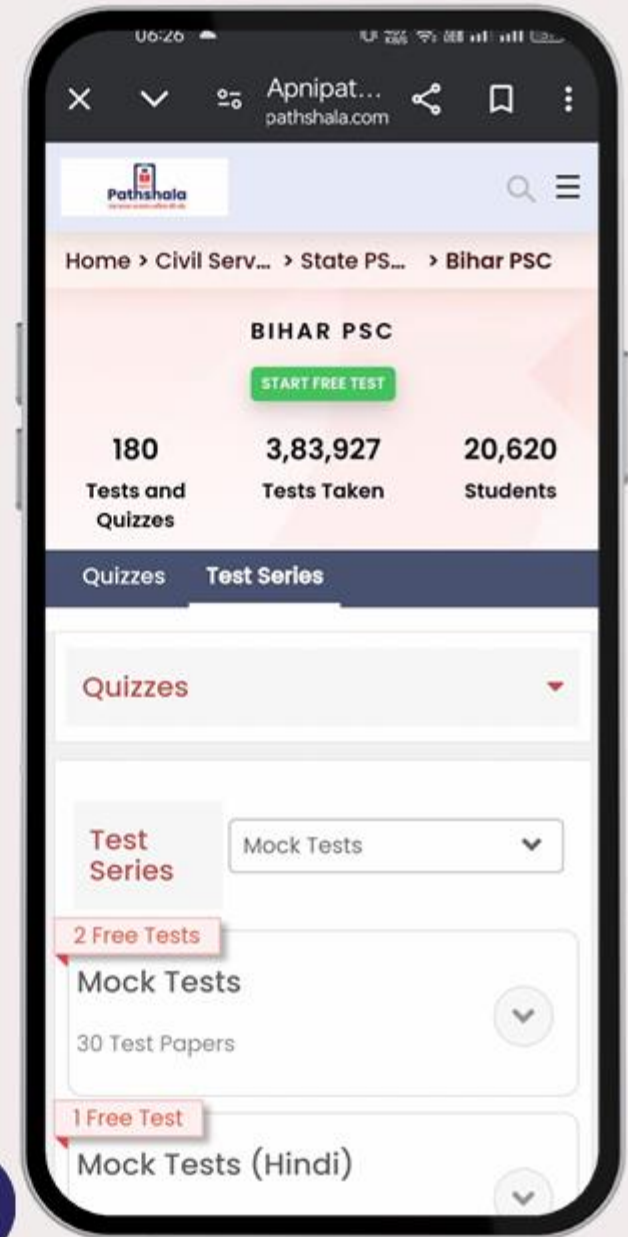
Step 3

Click on
Explore Now



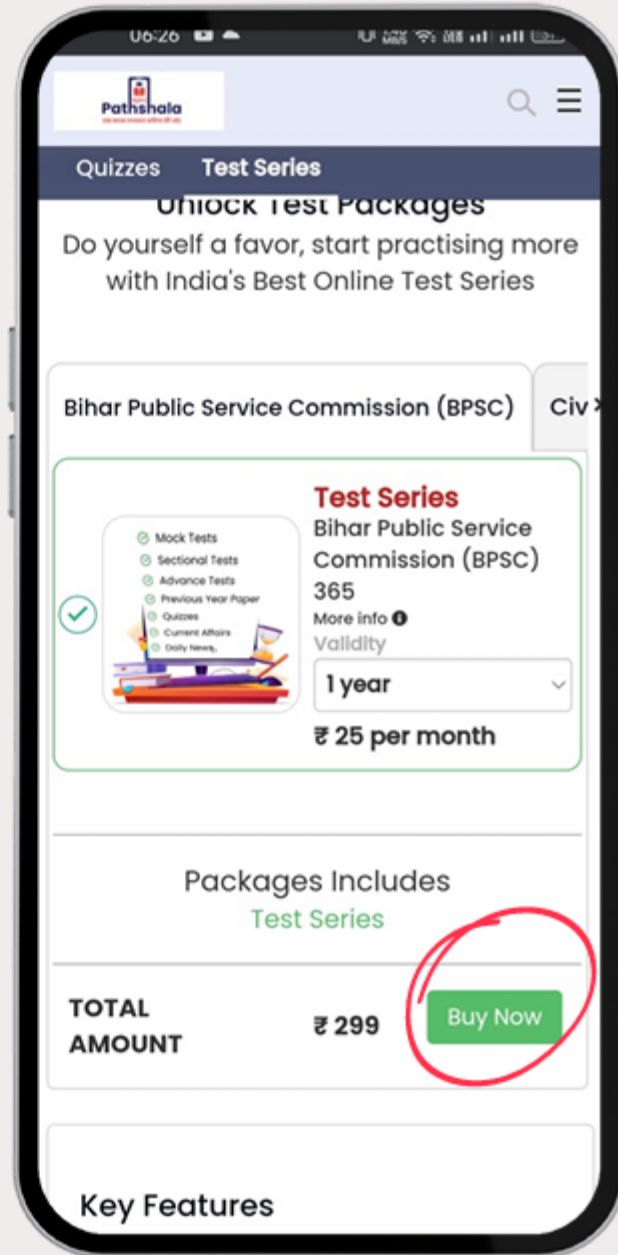
Step 4

Scroll
Down



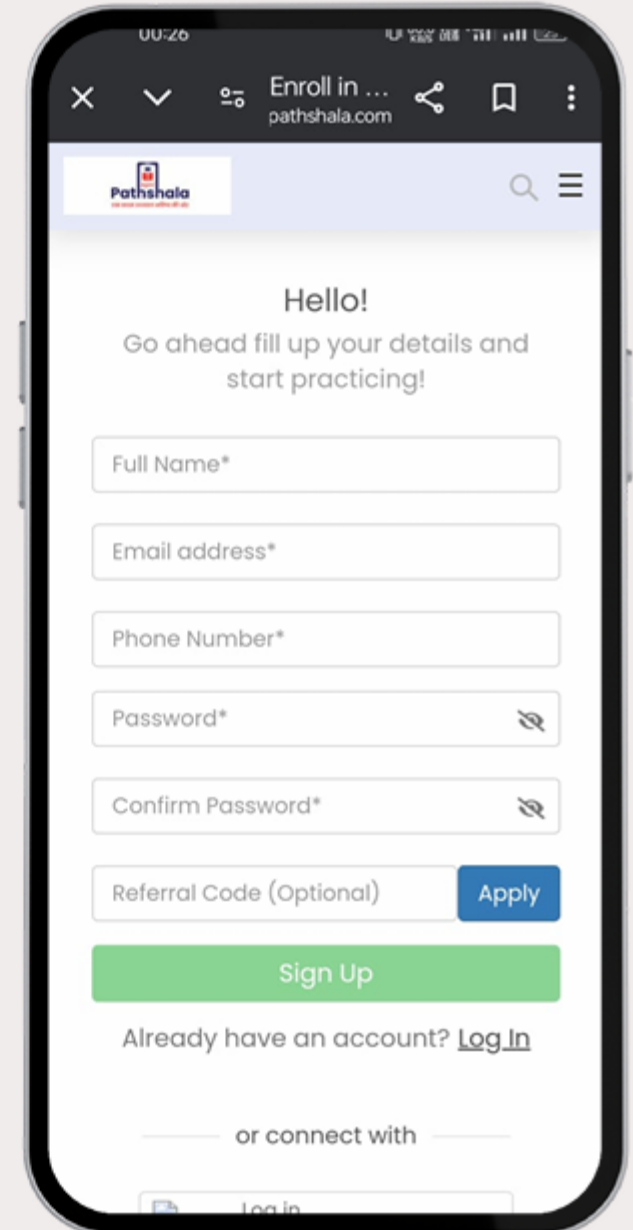
Step 5

Click on
Explore Now



Step 6

Fill the details
Pay Now!





LAUNCHING



BPSC

TEST SERIES

299/- ONE YEAR

- 50+ Mock Test
- 10+ Topic wise test
- 30+ PYQ's
- 65 + Current Affairs

Buy Now!

By Ankit Avasthi Sir





LAUNCHING



RO/ARO
TEST SERIES

299/- ONE
YEAR

- 30+ Mock Test
- 13+ Sectional test
- 8+ PYQ's
- 60 + Current Affairs

Buy Now!

By Ankit Avasthi Sir





UP POLICE बनने का सपना होगा साकार !



Test Series

UP POLICE EXAM

PRICE
99/- One Year

VACANCY: 60,244
EXAM. DATE : 23RD AUGUST
24TH AUGUST, 25TH AUGUST,
30TH AUGUST, 31ST AUGUST



By Ankit Avasthi Sir



UP POLICE बनने का सपना होगा साकार !

NEW

LAUNCHING



Test Series

UP POLICE EXAM



FEATURES

- ⇒ 20 Mock Test
- ⇒ 21 Sectional Test
- ⇒ 10 Practice Test
- ⇒ 25+ Topic Wise Test
- ⇒ 8+ PYQ's
- ⇒ 65+ Current Affairs Test

BUY NOW!

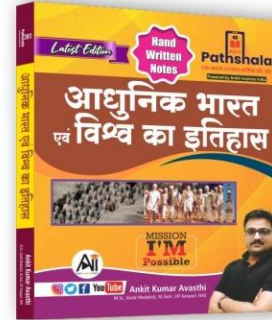
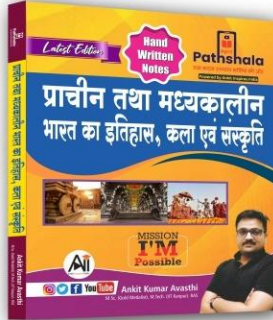
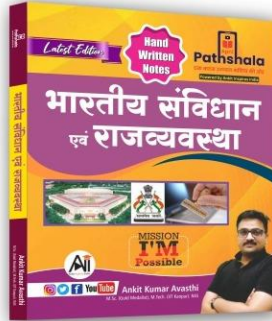
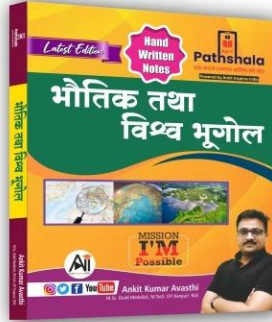
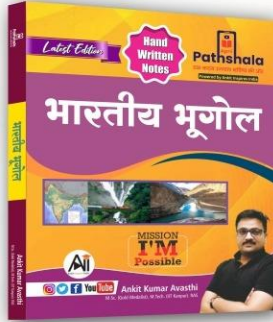
99/-

for ONE YEAR

By Ankit Avasthi Sir

GA FOUNDATION

Hand Written
Notes



₹ Only
1999

6 पुस्तकों
का
सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए
गए नंबर पर संपर्क करें....

 **7878158882**

- सिन्धु नदी का उद्गम कर्लाश पर्वतीय क्षेत्र में बीखर-सू हिमनद से होता है।
- तिब्बत में इस नदी को सिंगी खंबान कहते हैं।
- यह फमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है।
- यह नदी भारत में लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी के बीच बहती है।
- पाकिस्तान में यह अटक (Attock) नामक स्थानों पर मैदानों में प्रवेश करती है।
- पाकिस्तान में कराँची के पास डेल्टा बनते हुए यह अरब सागर में गिरती है।
- सिन्धु नदी की दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदियाँ :- श्योक, रुद्रा, हुनजा, गिलागिट, स्वात, काबुल तथा गोमल
- इसकी प्रमुख बायें हाथ की सहायक नदियाँ झेलम, पिनाब, रावी, व्यास, सतलज, द्रास तथा जास्कर पंचनद
- सिन्धु से पंचनद पाक में मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है।
- 'लेट' सिन्धु नदी के किनारे स्थित है।

पंचनद

i) झेलम :- इस नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में

- बेरिनाग झील से होता है।
- * यह नदी बल्लर झील का निर्माण करती है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
- इस नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है।
- किशनगंगा इसकी दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदी है।
- इस नदी पर तुलबुल परियोजना प्रस्तावित है। यह एक नवविद्यन परियोजना है।
- यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है।

ii) पिनाब :- पिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बाराकच्छा दर्रे के पास चन्द्र तथा भागा नदियों के मिलने (Confluence) से होता है।

- 1962 में इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ स्थित हैं।

उदाहरण :- तुलहस्ती, सलाब, बगलिहार

- यह सिन्धु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।

iii) रावी :- रावी नदी का उद्गम शैलांग दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में होता है।

- हिमाचल प्रदेश में इन नदी पर चमेरा बाँध स्थित है।
- पंजाब में इस नदी पर धीन परियोजना स्थित है।

₹ 1999



visit Our Website :-

WWW.apnipathshala.com

1) BPSC Courses

2) RPSC Courses

3) UPPSC Courses

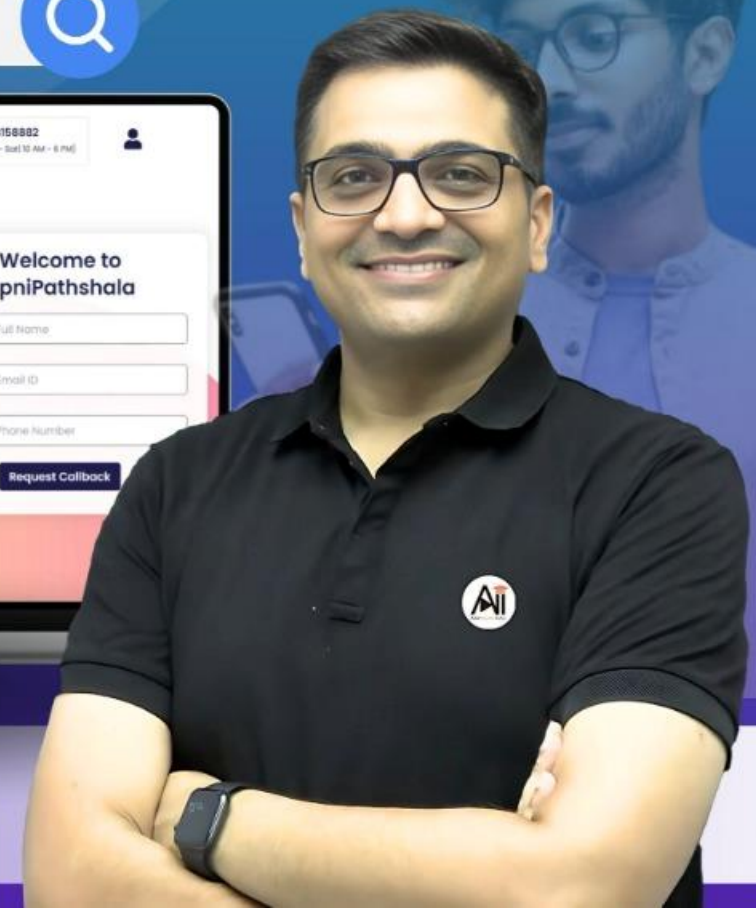
4) RNA And Class Pdf

5) video lecture

6) Daily Current Affairs

7) Infographic

8) Test series , Quiz



अब तैयारी हुई और आसान

CALL CENTRE

7878158882



HOW MAY I HELP YOU



AnkitInspiresIndia

➔ Download "Apni Pathshsla" app now!

Follow us:

